हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

9 मार्च, 2010

खण्ड 1, अंक 3

अधिकृत विवरण

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

विषय सूची

मंगलवार, 9 मार्च, 2010

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3) 1
डी०ए०वी० कालेज, मन्यौला (अम्बाला) के विद्यार्थियों का अभिनन्दन	(3)11
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भण)	(3)12
अध्यक्ष द्वारा स्थगन प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण सूचना में परिवर्तित करने संबंधी सूचना	(3)18
भारतीय जनता पार्टी तथा इण्डियन नेशनल लोकदल के निलम्बित सदस्यगण को वापिस बुलाने के लिए अनुरोध करना	(3)19
मंत्री द्वारा वक्तव्य	(3)20

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (3)26

वाक-आउट (3)28

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भण) (3)28

बैठक का समय बढ़ाना (3)61

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भण) (3)61

वर्ष 2009-2010 के लिए अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) प्रस्तुत करना (3)70

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना (3)71

वर्ष 2009-2010 के लिए अनुपूरक अनुमानों की मांगों (द्वितीय किस्त) पर चर्चा तथा मतदान (3)71

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 9 मार्च, 2010

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में सुबह 10.00 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चड्ढा) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now questions hour please.

Mewat Canal

***101. Chaudhary Aftab Ahmed :** Will the Irrigation Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal for providing Irrigation Water to Mewat area through the proposed Mewat Canal;

(b) if so, the stage of the construction of this proposed canal for execution of the proposal ; and

(c) the quantity of water to be supplied by this proposed canal and the total area to be covered by this proposed canal in the Mewat District ?

Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav):

(a) Yes, Sir.

(b) Approval of the State Government to the construction of Mewat Canal was granted in March, 2007. The propoal was sent to Central Water Commission vide letter No. 377-81/152, dated 20-3-2007. WAPCOS Limited-a public sector enterprise, under the aegis of the Union Ministry of Water Resources, is presently in the process of finalising its Detailed Project Report (DPR).

(c) This will be known only when the DPR is finalised.

चौधरी आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि यह जो मेवात कैनाल है इसकी डी०पी०आर० कब तक आ पायेगी और कब तक इस पर काम शुरू हो पायेगा ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह जो मेवात कैनाल है यह बहुत ही महत्वपूर्ण कैनाल है और विशेष तौर पर मेवात, पलवल और हथीन के एरिया के लिए इसका विशेष महत्व है। इन एरियाज में पानी औखला बैराज से मिलता है और यह पूरी दिल्ली को पार करके आता है जिसकी वजह से पानी पोल्यूटिड मिलता है। हमें जो पानी दिल्ली बोर्डर से मिलता है वह 3 बी०ओ०डी० मिलता है

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

लेकिन हम मेवात कैनाल के लिए 30 बी०ओ०डी० पानी देंगे । इस पर उत्तर प्रदेश सरकार का कंट्रोल है जिसकी वजह से हमें दिक्कत आती है, इसलिए इसमें समय लगेगा । इसमें गुड़गाँव कैनाल और आगरा कैनाल से 50-50 की रेशो में पानी औखला बैराज से बंटकर आता है । जो पानी आता है उसकी क्वालिटी भी खराब है । सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने 10 जनवरी, 2007 को पुन्हाना में घोषणा की थी तथा मार्च 2007 में इसकी क्लियरेंस भी हो गई है । उसके बाद हमें यह केस सैन्ट्रल वाटर कमिशन के पास भी भेजना पड़ेगा क्योंकि इसमें इन्टरस्टेट इश्यू इनवोल्व हैं। हमें पहले पानी औखला बैराज से मिलता था अब हम कोशिश करेंगे कि यह पानी हमें ताजेवाला हैड से मिल जाये। एक तो इसमें पोल्यूशन की समस्या समाप्त हो जायेगी और दूसरे हमें पानी भी पूरा मिल जायेगा। जहाँ तक माननीय सदस्य का सवाल है कि इस पर कब तक काम शुरू हो जायेगा तो इस बारे में मेरा कहना है कि इसकी डी०पी०आर० बन रही है। जैसे ही डी०पी०आर० तैयार हो जायेगी हम केस सैन्ट्रल वाटर कमिशन को भेज देंगे । सैन्ट्रल वाटर कमिशन से इसकी क्लियरेंस मिलने के बाद इस पर काम शुरू हो सकेगा । अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि यह कैनाल मेवात, पलवल और हथीन एरिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे उनकी पीने के पानी की समस्या को हम दूर कर सकेंगे।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, मेरा सिंचाई विभाग के बारे में एक जनरल सवाल है क्योंकि सिंचाई मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं । पानी की उपलब्धता कम होने के कारण नहरों में पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं छोड़ा जाता है । जहाँ 700 क्यूसिक कैपेस्टी की नहर है उसमें 300 क्यूसिक पानी ही छोड़ा जाता है । उससे न तो कैनाल में ही पानी चढ़ पाता है और न ही आउट लैट में पानी पहुंच पाता है । इसलिए मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि जो पानी छोड़ा जाये वह पर्याप्त मात्रा में छोड़ा जाये ताकि नहर में भी पानी चढ़े और आउटलैट में भी पानी पहुंच पाये ।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इनकी बात वाजिब है। सर, आज भाखड़ा के अन्दर जो पानी है वह पिछले साल के मुकाबले 40 फुट नीचे है। इसके अलावा जहां हमें बी०एम०एल० और यमुना से 10 लाख क्यूसिक पानी मिलता था, आज 6 हजार क्यूसिक पानी ही आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, अब सिर्फ चार ग्रुप ही रह गए हैं। हमारी कोशिश है कि वहां पर पूरा पानी मिले लेकिन पानी की कमी की वजह से हम उनके हिस्से में से 25 प्रतिशत पानी ही दे पाते हैं, सर, फिर भी हमारी कोशिश यह रहेगी कि उनको पूरा पानी मिल सके। स्पीकर सर, आज सिरसा में भी चार ग्रुप ही चल रहे हैं। अभी वहां पर हम पांच ग्रुप नहीं कर रहे हैं। अगर वहां पर समस्या ज्यादा होती है तो हमें वहां पर भी पांच ग्रुप करने पड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में बर्फ पिघल जाएगी तो पानी ज्यादा हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हम वहां पर कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पानी दिया जा सके।

चौ० आफताब अहमद : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि टेलों पर जो क्षेत्र हैं वहां पर पानी की बहुत दिक्कत है। वहां पर पानी की चोरी भी बहुत है जिसकी वजह से भी टेल एंड वालों को पानी की बहुत दिक्कत होती है। क्या मंत्री जी इसमें सख्ती करके टेल एंड तक पानी पहुंचाने का कष्ट करेंगे ताकि वहां के लोगों को पानी पहुंचाया जा सके ?

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, इनकी बात बिल्कुल सही है, सर, हमारा कुछ एरिया उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, उन्होंने वहां पर पम्प सैट्स लगाए हुए हैं और हमारे ऐरिया में भी लोगों

ने पम्प सैट्स लगाए हुए हैं। हमारी सरकार की तरफ से स्पेशल पुलिस स्टेशंज के बारे में एक प्रस्ताव बनाया गया है जिससे इरिगेशन और पीने के पानी की थैफ्ट को रोका जा सके। इस बारे में हमारे पास केस आया हुआ है और हम जल्दी ही उस बारे में विचार करेंगे। पानी की चोरी होने की वजह से टेल एंड पर पीने का पानी नहीं पहुंच पाता है। इस चोरी को रोकने के लिए हम स्पेशल पुलिस स्टेशन बनाएंगे। इसके लिए जो हमारे पास सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया है उसको जल्दी एप्रूव करेंगे ताकि पानी की थैफ्ट रुक सके। सर, आपने पीछे के दिनों में देखा था कि एक गांव में गांव के लोगों ने हमारे एस०डी०ओ० और जे०ई० को बन्दी लिया था। अब हम जल्दी ही स्पेशल थाने बनाकर इस बारे में कार्यवाही करेंगे।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि आज पानी की कमी है। आज आप देखें कि हमारे यहां पर फसल पकाई पर है और आप पकाई के समय तक वहां पर पानी को ज्यादा कर दें बाद में चाहे आप वहां पर पानी को कम कर देना।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमने पांच ग्रुप कर दिए हैं। सिरसा में चार ग्रुप ही हैं और उनको हम पांच ग्रुप करने की बात करेंगे ताकि फसल पकने तक उचित पानी मिल सके।

Upgradation of Schools

*52. **Smt. Kiran Chaudhary :** Will the Education Minister be pleased to state–

(a) whether the Government is upgrading the schools in the State; and

(b) if so, the details of schools likely to be upgraded in Bhiwani District togetherwith the criteria for upgradation thereof ?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail):

(a) Yes Sir, however the norms for upgradation of schools is under revision.

(b) Upgradation of schools in Bhiwani district would be considered after finalisation of revised norms.

Smt. Kiran Chaudhary : Speaker Sir, I would like to know what are the norms for the upgradation of schools ? Have the criteria in this regard already been fixed or not ?

Smt. Geeta Bhukal Matanhail : Speaker Sir, we are already revising the existing norms for upgradation of schools. These existing norms are 150 students from primary to middle and at least 25 students should be studying in the class 5th for the last 2 years. And 150 students for middle to high class and at least 50 students should be studying in 8th class for the last 2 years and 150 students for high to secondary classes. As per record of the school education, the land area for the primary to middle school is about one acre, middle to high is about two acres and high to senior secondary is two acres. The building norms are primary to middle school is 8 rooms with the condition of one room per section for the education purpose and the middle to high, 10 rooms and for high to senior secondary, 12 rooms are required. We are revising these norms in addition to the newly upgraded schools.

Smt. Kiran Chaudhary : Speaker Sir, how many Schools in Tosham fulfill these norms and by when these schools will be upgraded ? As you know that our Government lays a great deal of emphasis on education and education is only possible when we bring it from the bottom. As you know that our children are weak and only on manpower, we can bring up them as educated citizens if they are given proper facilities. Sir, I would like to know that how many schools in my constituency fulfill these norms and what the Government is doing and by what time the same will be upgraded?

Smt. Geeta Bhukkal Matanhail: Speaker Sir, I would like to inform the Hon'ble Member that the total number of primary, middle and high schools upgraded in the Bhiwani district are in the larger number as compared to the other districts. Speaker Sir, the Hon'ble Member has asked about district Bhiwani. First of all, I would like to give information about the Bhiwani District. Sixty eight schools have been upgraded from Primary school to middle schools in district Bhiwani.

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहूंगी कि तोशाम में कितने स्कूल अपग्रेड करने के नोर्म्ज फुलफिल करते हैं और जो स्कूल अपग्रेडेशन के लिए नोर्म्ज फुलफिल करते हैं वे सारे के सारे अपग्रेड होंगे या नहीं ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मै सम्मानित साथी को बताना चाहूंगी कि स्कूल अपग्रेडेशन के जो नोर्म्ज हैं वह अंडर रिवीजन हैं । आलरेडी भिवानी डिस्ट्रिक्ट में एज पर नोर्म्ज से बहुत ज्यादा स्कूल अपग्रेड हुए हैं। (Interruption)

Mr. Speaker : Please, let her finish. Madam Chaudhary, you may put the question after that. आप पहले क्वैश्चन का जवाब आने दो और उसके बाद आप अपनी सप्लीमैंट्री पूछ लेना ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, कम या ज्यादा की बात नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदया से यह पूछ रही हूं कि जो स्कूल नोर्म्ज फुलफिल करते हैं वे अपग्रेड होंगे या नहीं ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल: अध्यक्ष महोदय, हम नोर्म्ज की रिवीजन कर रहे हैं । जो भी स्कूल एज पर रिवीजन नोर्म्ज के अंडर आएंगे वह जरूर अपग्रेड किए जाएंगे ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहती हूं कि तोशाम में कितने स्कूल नोर्म्ज पूरे करते हैं और जो स्कूल नोर्म्ज पूरे करते हैं उनको कब तक अपग्रेड कर दिया जाएगा ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, जो क्वैश्चन था वह पूरे भिवानी जिले के स्कूलों की अपग्रेडेशन के बारे में था । अगर ये तोशाम के बारे में जानना चाहती हैं तो इस बारे में एक सैपरेट क्वैश्चन दे दें । We will consider it.

Smt. Kiran Chaudhary : Speaker Sir, I would like to know from the Hon'ble Education Minister कि जो स्कूल नोर्म्ज पूरे करते हैं उनको कब तक अपग्रेड कर दिया जाएगा ? (शोर एवं विघ्न)

Mr. Speaker : Madam, before putting the question you should at least ask me that 'I want to put the supplementary'.

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, मैंने आपका नाम लिया है। मैंने अध्यक्ष जी कहा है।

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष जी कह दिया लेकिन परमिशन तो नहीं ली।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, मैं आपकी इजाजत से माननीय मंत्री महोदया से यह आश्वासन लेना चाहूंगी कि तोशाम के अंदर जो स्कूल अपग्रेडेशन के नोर्म्ज के क्राईटेरिया को पूरा कर रहे हैं वे कितने हैं ? यह इंफोर्मेशन तो इनके सर्व में आ गई होगी। मैंने इस बारे में इनको चिट्ठी भी लिखकर भेजी थी लेकिन अनफोरचुनेटली उस चिट्ठी का जबाव नहीं आया। मैं जानना चाहूंगी कि तोशाम के अंदर कब तक नोर्म्ज फुलफिल करने वाले स्कूलों को अपग्रेड कर दिया जाएगा ? शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 109.53 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार से इनके लिए मिलेगा। इन्होंने शिक्षा केन्द्र खोलने के लिए पांच हजार की आबादी की बात कही है। यह शिक्षा के क्षेत्र में पैसा लगा रही हैं इसलिए जब तक हमारे स्कूल अपग्रेड नहीं होंगे तब तक हमारी बच्चियों और हमारे बच्चों को पढ़ने की सुविधा गांवों में नहीं मिल पाएगी।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्या को बताना चाहूंगी कि जैसा मैंने इनको बताया कि upgradation of school is under revision. भिवानी डिस्ट्रिक्ट में और पर्टीकुलरली तोशाम में जो भी स्कूल एज पर रिवाइज्ड नोर्म्ज पाया जाएगा, we will consider that. मैं भिवानी जिले की इंफोर्मेशन बताना चाहूंगी क्योंकि हम नोर्म्ज को रिवीजन कर रहे हैं। राईट टूं एजुकेशन एक्ट आने के बाद we will decide the norms.

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ------

Mr. Speaker : At least, you should take permission from me before asking the question.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहती हूं कि जैसा सम्मानित सदस्या ने कहा है, इन्होंने हमें चिट्ठी लिखी थी और हमने इनकी चिट्ठी के हिसाब से ही जितने भी केशिज इन्होंने अपग्रेडेशन के लिए भेजे थे we are considering those cases. इस समय हमारे जो अपग्रेडेशन के नॉर्म्ज हैं उनको हम रिवाइज कर रहे हैं as per the Right to Education Act.

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मुझे तो ऐसा लगता है कि आज इधर की बैंचिज का काम आप कर रही हैं।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह बच्चों की शिक्षा का मामला है और बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और सरकार शिक्षा पर खर्च भी बहुत कर रही है और स्कूल अपग्रेड कर रही है लेकिन सुविधायें नहीं हैं तो इसका क्या फायदा है।

Mr. Speaker : Please let the Minister to finish her reply. (Interruption) You should take the permission from me before asking the question and I would not deny the permission.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन और माननीय सदस्या को भी बताना चाहूंगी कि भिवानी जिले में हमने largest number of Schools as compared to other Districts अपग्रेड किए हैं भिवानी में स्कूलों की कुल संख्या 1142 हैं जिनमें से प्राइमरी 690 हैं और मिडल स्कूल 149 हैं, हाई स्कूल 155 हैं और सीनियर सैकेंडरी के 148 हैं। यह डिस्ट्रिक्ट भिवानी की पोजीशन है उसके बाद दूसरा नंबर हिसार का आता है यहां हमने 904 स्कूल अपग्रेड किए हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में हमने प्राइमरी के 1072 स्कूल अपग्रेड किए हैं, मिडल टू हाई 267 अपग्रेड किए है, हाई टू सीनियर सैकेंडरी 419 अपग्रेड किए हैं, टोटल 1758 अपग्रेड किए हैं । जहां तक भिवानी का ताल्लुक है भिवानी में सबसे ज्यादा स्कूल अपग्रेड किए हैं। जैसा हमने नॉर्म्ज के बारे में कहा था उसके बारे में मैं एक ही बात कहूंगी कि ऐज पर नॉर्म्स रिवाइज्ड होने के बाद जितने भी केसिज माननीय सदस्या भेजेंगी we will consider them.

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने जो जवाब दिया है उससे मुझे बहुत खुशी हुई है कि इतने सारे स्कूल अपग्रेड किए हैं लेकिन मैं साथ ही साथ यह भी जानना चाहती हूं कि हमारे इलाके तोशाम के अंदर कितने ऐसे स्कूल हैं जो अपग्रेडेशन के पूरे के पूरे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब इन्होंने यह भी कहा है कि नॉर्म्ज को रिवाइज कर रहे हैं, ये कब तक हो जाएंगे ? (विघ्न)

Mr. Speaker: Madam, please read your question. ऑफ हैंड how can she say कि तोशाम के स्कूलों का क्या हाल है ?

चौ० आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि जो अपग्रेडिड स्कूल्ज हैं खास तौर से हमारे मेवात जिले में उनमें आज भी अध्यापक नहीं हैं, क्या सरकार के पास कोई ऐसा प्रस्ताव है कि अपग्रेडिड स्कूल में अध्यापक लगाए जाएं ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो सके ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि विशेष तौर से डिस्ट्रिक्ट मेवात में इस तरह की समस्या जरूर है । अध्यापकों की कमी जरूर है और पूरे प्रदेश से इन पदों को भरने के बारे में आलरेडी रिक्वीजिशन हमारी तरफ से गई हुई हैं उनमें से कुछ के रिजल्ट भी आने वाले हैं और रिजल्ट आने से कुछ पदों पर तो भर्ती हो सकेगी लेकिन 1-2 मामलों में सब-ज्यूडिस मैटर है जैसे ही फैसला हो जाएगा, अति शीघ्र अध्यापकों की भर्ती पूरी कर ली जाएगी ताकि स्कूलों में पढ़ाने के लिए पूरे अध्यापक मिल सकें।

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री आफताब अहमद जी को बताना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व वाली सरकार विशेष तौर से मेवात इलाके में शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति चिंतित है और आजादी के बाद पहली बार वहां इंजीनियरिंग कालेज और मेडीकल कालेज बनाए गए हैं और जो अस्पताल वहां बंद पड़ा हुआ था उस अस्पताल में सब तरह के इक्विपमैंट्स लगाकर और डॉक्टर्ज की भर्ती करके कांग्रेस की मौजूदा सरकार ने उसको चालू किया है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य की और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि यह जो मेवात के इलाके की समस्या है यह बड़ी

ही गंभीर समस्या रही है कि जो भी शिक्षक उस एरिया में लगाए जाते थे वे वहां से ट्रांसफर करवा कर चले जाते थे इसलिए हमने यह फैसला किया है मेवात के लिए अलग कॉडर बनाएंगे ताकि वहां के लिए अलग से रिक्रूटमैंट हो और वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि कई स्कूल ऐसे हैं जो स्टूडैंट्स के नार्म्स को पूरा करते हैं अर्थात् जितने स्टूडैंट्स होने चाहिएं स्टूडैंट्स तो उतने ही हैं लेकिन वहां पर जगह की कमी है। क्या मंत्री जी बतायेंगी कि जहां जगह की कमी है वहां पर पंचायत से जमीन लेकर स्कूलों को अपग्रेड किया जायेगा ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगी कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारा विभाग स्कूलों के अपग्रेडेशन के बारे में नॉर्म्स को रिवाईज कर रहा है। इन नॉर्म्स की रिवीजन में हमने area of land भी मैंन्शन किया है । जैसा कि बताया गया है कि प्राईमरी स्कूल से मिडिल स्कूल अपग्रेड करने के लिए एक एकड़ जमीन, मिडिल से हाई स्कूल अपग्रेड करने के लिए दो एकड़ जमीन और हाईस्कूल से हायर सैकेण्डरी स्कूल अपग्रेड करने के लिए भी दो एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। जहां तक बाहर की लैण्ड लेने के लिए बताया गया है जब अगर किसी स्कूल को अपग्रेड किया जायेगा तो नार्म्स पूरा करने के लिए उतनी जमीन हमें जरूर चाहिए जितनी जमीन नार्म्स में दी गई है।

Violations of Forest Conservation Act, 1980

***28. Shri Sampat Singh, :** Will the Forest Minister be pleased to state—

(a) the number of violations of Forest Conservation Act, 1980 that have come to the notice of the department in the State since the enforcement of the said Act;

(b) out of above, the number of violations regularised after charging Compensatory Afforestations Management Funds togetherwith Net Present Value; and the details of the provisions of regularization of such violations;

(c) the total amount charged and deposited in CAMPA;

(d) the total Compensatory Afforestation Management Funds received by the State Government from CAMPA; and

(e) the number of violations still are to be regularised ?

Finance Minister (Captain Ajay Singh Yadav) :

(a) 772 No. of violations have come to the notice of the Department.

(b) 224 No. of violations have been regularized after charging penal compensatory afforestation charges togetherwith normal Net Present Value and Compensatory Afforestation charges. All these charges are deposited in the account of Adhoc Compensatory Afforestation Fund

[Captain Ajay Singh Yadav]

Management and Planning Authority (Adhoc CAMPA) of the Govt. of India. For these regularization Rs. 2,35,65,610 was deposited in Adhoc CAMPA. The violations are regularized by the Ministry of Enviroment and Forests, Govt. of India, as per guidelines laid down in the handbook of Forest (Coservation) Act, 1980 issued by the Ministry.

(c) The total amount of Rs. 187,43,71,719 have been charged and deposited against all the sanctioned proposals from Haryana in Adhoc CAMPA Fund, New Delhi.

(d) Rs. 19,11,41,000 have been received from Adhoc CAMPA, New Delhi by the State CAMPA, Haryana.

(e) 548 No. of violations are still to be regularized.

प्रो० सम्पत सिंह : सर, मेरा पहला प्रश्न मन्त्री जी से यह था कि फोरेस्ट एक्ट की जो टोटल 772 वाईलेशंज हुई हैं उनमें से अब तक केवल 224 वाईलेशंज को after charging पैसे वगैरह लेकर रेगूलैराईज किया गया है। पहले तो यह कि इसके बावजूद भी 548 वाईलेशंज बाकी रह गई हैं । माननीय मंत्री जी काफी सीनियर हैं और इंटैलीजेंट भी हैं । मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि इनमें से क्लीयर वाईलेशंज कितनी रह गई हैं । दूसरा यह कि जो वाईलेशंज कोर्ट कचहरी में पैंडिंग हैं वे कितनी हैं और कोर्ट कचहरी में दस साल से ज्यादा पैंडिंग वाली कितनी वाईलेंशंज हैं। कई बार क्या होता है कि जो फोरस्ट आफिसर्ज और विभाग के दूसरे ओफिशिएल हैं वे आपस में मिलकर चलते रहते हैं और उन दोषियों को नोटिस जारी कर देते हैं । अक्सर यह देखा गया है कि इनमें बिल्डर्स आ रहे हैं, हाई-वे पर कितने ही शो-रूम्ज बनाये जा रहे हैं, ढाबे बनाये जा रहे हैं हर जगह पर इनमें फोरेस्ट एक्ट की वाईलेशन हो रही है उसमें एक्ट की धारा 72 शामिल नहीं हैं। तीसरा यह है कि ये वाईलेशंज अब तक पैंडिंग क्यों हैं ? जो फोरेस्ट आफिसर्ज और ओफिशिएल्ज इन वाईलेशंज के लिए जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया है ? क्या गलैरिंग एग्जाम्पल कोई आया है जिसमें बिल्डर्स या बड़े लोग इन्वोल्वड हैं जिन्होंने हाई-वे पर होटल, रेस्टारेंट वगैरह बनाये हुए हैं खासकर पिन्जौर वाली साईड में, मैं मंत्री जी से यही पूछना चाहता हूं कि क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, टोटल वाईलेशंज 772 हैं जिनमें से 548 वाईलेशंज बाकी रह गई हैं and their proposals involving violations have been applied under Forest Conservation Regulation Act, 1980 for regularization. The cases which are pending at different levels like Chief Conservator, Principal Chief Conservator of Forests, in the State Govt. and even in the Ministry of Govt. of India are totaling 358 and total cases which have been filed in the Environmental Court are 118 and balance cases जहां तक डैमेज चार्जशीट इश्यूड हैं वे टोटल 72 केसिज हैं। अध्यक्ष महोदय, वायलेशंज के मैक्सिमम केसिज फरीदाबाद में आज की तारीख में 126 पैंण्डिंग हैं। जो टोटल केसिज थे उसमें 11 केसिज belong to strip forest along roads and 150 belong to section-4 and 5 areas of Aravali and 96 cases have been filed in Environment Courts. In 30 cases notices have been issued to offenders for filing cases in the Environment Courts और जो नार्मल ओफैंसिज होते हैं, जैसा कि इन्होंने कहा सड़क पर कई बार कोई पेड़ काट लेता है तो under the Forest Act 1927 यह अधिकार दिया

गया है कि हमारे जो फोरैस्ट ओफिसर्ज हैं ये उनके ऊपर बकायदा 500 रुपये जुर्माना कम्पाउंड कर सकते हैं । यह जुर्माना पहले 50 रुपये था अब उसको बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है । Section 68 of Forest Conservation Act है जिसमें आफिसर्ज को पावर्ज दी गई हैं कि 500 रुपये जुर्माना कम्पाउंड करके उसको रैगुलेराइज कर सकते है । जहां तक इन्होंने कहा है कि वायलेशन के कितने केसिज हैं तो इस बारे में ये सैपरेट नोटिस दे दें । इन्होंने जो कैम्पा के बारे में प्रश्न पूछा था उसका जवाब मैंने दे दिया है लेकिन इन्होंने कहा है कि वायलेशंज की संख्या कितनी है तो इस बारे में ये स्पैसीफिक प्रश्न करें तो मैं जवाब दे सकता हूं अन्यथा मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा ।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पैसीफिक प्रश्न पूछा है कि वायलेशन कितनी है, इन्होंने ठीक जवाब दिया है कि कोर्ट के केसिज इक्का दुक्का हैं । सभी डिपार्टमैंट्स के अंदर इस तरह के केसिज पड़े हैं। जैसा इन्होंने जवाब दिया है कि ये केसिज डी०एफ०ओज० के पास, कंजर्वेटर के पास, चीफ कंजर्वेटर के पास या पी०सी०सीज० के पास है। ये अधिकारी इन्हीं के हैं और ये अधिकारी फोरैस्ट वायलेशन के केसिज में इतनी लीनियंसी क्यों बरत रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह भी पूछना चाहूंगा कि एक तरफ हमारा जो फोरैस्ट एरिया है आज कितने परसैंट रह गया हैं और पहले यह एरिया कितने परसैंट था ? क्या यह फोरैस्ट एरिया घटा है ? दूसरी तरफ वायलेशन पर वायलेशन होती जा रही है। अरावली की बात और दूसरी जगह की बात मंत्री जी ने कही है। बिल्डर्ज की, सैक्शंज 4 और 6 की बात इन्होंने बताई । कई बार कुछ इस तरह के लोग हैं जो फोरैस्ट को उड़ा देते है और अपनी बिल्डिंग बना लेते हैं। मंत्री जी, क्या इस तरफ आप ध्यान रखते हैं, क्या पंचकूला या पिंजौर में कोई ऐसा केस आपके नोटिस में आया है, जिनमें फोरैस्ट एक्ट के तहत चाहे वह स्टेट एक्ट है या सैंट्रल एक्ट है कोई वायलेशन हुई है ? अगर हाइवेज पर कोई वायलेशन हुई है तो इस बारे में आपने क्या कार्यवाही की है ? आप कहते हैं कि लोग ढाबा या शोरूम या कोई और चीज बना लेते हैं तो यह वायलेशन आपके एक्ट में आती है या गवर्नमैंट आफ इंडिया के एक्ट में आती है ?

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, अगली बात आप फिर कर लेना नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा ।

प्रो० सम्पत सिंह : ठीक है सर ।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, टोटल कितनी वायलेशन है इस बारे में मैंने बता दिया है। 358 केसिज ऐसे हैं जो डिफरैंट लैवल्ज पर हैं, कोई कंजर्वेटर ऑफ फोरैस्ट लैवल पर है, कोई पी०सी०सीज० लैवल पर हैं और गवर्नमैंट और कोई गवर्नमैंट आफ इंडिया, मिनिस्ट्री आफ इन्वायर्नमैंट लैवल पर है । 358 केसिज की पूरी डिटेल मैंने दे दी है। जहां तक इन्होंने बात रखी कि कोई इस तरह की वायलेशन होती है तो हम क्या करते हैं। मैं इनको बताना चाहूंगा कि कम्पनसेटरी फोरैस्ट के तहत 150 रुपये प्रति प्लांट के हिसाब से ले लिए जाते हैं और उसके लिए बाकायदा केस बनाकर हम भेजते हैं। कोई भी डिफोरेस्टेशन सैंट्रल गवर्नमैंट की एप्रूवल के बिना नहीं होती। किसी ने ढाबा, होटल बनाने के लिए डिफोरेस्टेशन करनी है तो उसको भारत सरकार से एप्रूवल लेनी पड़ेगी। भारत सरकार की परमीशन के बिना कोई वायलेशन नहीं हो सकती। कोई पैट्रोल पम्प खोल लेता है और पेड़ काट लेता है तो उस वायलेशन को रैगुलेराइज करने के लिए केस सैंट्रल गवर्नमैंट को भेजना पड़ता है। डैनसिटी के हिसाब से 9.8 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कैलकुलेट किये जाते हैं। कोई भी वायलेशन होती है तो बाकायदा उसका हिसाब कैलकुलेट करते हैं। हमारी जो कैम्पा अथोरिटी है उसमें ऐसे पैसे जमा कर दिए जाते हैं। इसकी नोटिफिकेशन अभी 14 जनवरी, 2010 को हुई है जिसके तहत तकरीबन 19 करोड़

11 लाख रुपये हमारी कैम्पा को मिले हैं । कैम्पा का उद्देश्य केवल फोरैस्ट प्रोटैक्शन मैनेजमैंट करना है और वाइल्ड लाइफ सैंचुरीज को मेन्टेन करना है । कोई पेड़ काट लेता है और उसके बदले जितने प्लांट लगाने की बात की जाती है तो उसके सारे पैसे कैम्पा द्वारा लिए जाएंगे । इसमें 3 कमेटियां बनी हैं । एक गवर्निंग बॉडी होगी जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जी करेंगे। इसके बारे में हम पॉलिसी फारमूलेट कर रहे हैं। यदि भविष्य में कोई वायलेशन होगा तो फोरैस्ट प्रोटैक्शन एक्ट के तहत कार्यवाही करेंगे। इसकी नोटिफिकेशन 14 जनवरी, 2010 को हो गई है और दो महीने में यह पूरी पॉलिसी फ्रेम कर देंगे कि फारैस्ट वायलेशन को किस प्रकार से रोका जाये । इसके लिए मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जायेगी। उस कमेटी में कौन-कौन मैंबर होंगे उसको जल्दी ही फोरमूलेट कर दिया जायेगा । इस कमेटी की मीटिंग हम दो महीने में कर लेंगे । इसके लिए स्टैंडिंग कमेटी भी बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता चीफ सक्रेटरी करेंगी । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि जो वायलेशन होते हैं उनकी कंपाउंडिंग एप्रूवल सैंट्रल गवर्नमैंट से होती है । यह बात ठीक है कि जो ढाबे वगैरा रोड़ साईड में बनते हैं वे फोरैस्ट एक्ट का वायलेशन करते रहते हैं लेकिन उन पर हम फोरैस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत जुर्माना भी लगाते हैं । जुर्माना किस रेट से लगाया जाता है वह जानकारी मैंने पहले ही माननीय साथी को दे दी है । (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने एरिया के बारे में नहीं बताया। दूसरी बात मंत्री जी बार-बार कह रहे हैं कि 358 केस पैंडिंग हैं। यह एक सीरियश मैटर है। ये केस स्टेट आफिसर्ज के पास बकाया है इस तरफ मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। उन फोरैस्ट आफिसर्ज के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा जो अपना काम ठीक प्रकार से नहीं करते। मैं जानना चाहता हूं कि उस तरफ सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही । कितने सालों से ये केस पैंडिंग हैं। इसके अतिरिक्त मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि जो 187,43,71,710 रुपये कंपाऊंड के जमा हुए हैं उनमें as a matter of right हमारी स्टेट का कितना पैसा बनता है तथा जो पैसा बकाया है वह कब तक वापिस ले लेंगे । मंत्री जी ने बताया है कि अब तक 19 करोड़ रुपये मिला है । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस पैसे का यूज किस परपज के लिए करना होता है ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में मौजूदा समय में 7 प्रतिशत जमीन पर फोरैस्ट है। पहले कितनी जमीन पर फोरैस्ट था यह जानकारी मेरे पास अभी नहीं है। माननीय साथी ने कहा है कि 187,43,71,710 रुपये कंपाऊंड के जमा हुए हैं। इस बारे में मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की एक स्टैंडिंग कमेटी बनी हुई है उसी कमेटी के आदेश से पैसे रिलीज होते हैं । मैंने पहले भी बताया है कि 19.11 करोड़ रुपये अब तक हमें मिल चुके हैं । जहां तक इस पैसे के यूटीलाईजेशन की बात है इस बारे में भी मैंने विस्तार से बताया है । मैं माननीय साथी को फिर से बताना चाहूंगा कि इस पैसे के यूज के लिए कैम्पा अथोरिटी बनी हुई है जिसका काम Protection and management of natural forest, protection and management for wild life centuries and national parks है । इसका काम यह भी होता है कि जो वायलेशन होता है उसको रेट के मुताबिक कंपाऊंड करके प्लांटेशन की जाती है । जो यह कैम्पा अथोरिटी है इसी के आदेशों के द्वारा ही इनवायरमैंट सर्विसिज के और रिसर्च एंड ट्रेनिंग के काम किये जायेंगे जिसके बारे में मैंने बताया है कि इसकी नोटिफिकेशन 14 जनवरी, 2010 को हो गई है। तीन कमेटीज गठित की जा रही हैं । एक गवर्निंग बॉडी होगी जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। This Governing

Body should laid down the broad policy, framework for the functioning of the State CAMPA. Haryana Government will review its work from time to time. जिसकी मीटिंग हम दो महीने में कर लेंगे । दूसरी स्टैंडिंग कमेटी होगी जिसकी अध्यक्षता चीफ सक्रेटरी करेंगी । This Committee will laid down rules and procedure to monitor the progress of utilization of funds. It will also approve annual plan of operation prepared by the Executive Committee and the Committee will meet once in six months. इसके अलावा तीसरी एग्जीक्यूटीव कमेटी होगी । It will be chaired by the PCCF. It will take steps in successful implementation of annual plan of operation approved by the Steering Committee. एक बात इन्होंने फॉरेस्ट कवरेज एरिया के बारे में पूछी है। इस बारे में मैं इनको बताना चाहूंगा कि यह कवरेज एरिया पहले 17.13 प्रतिशत था जो कि अब घटकर 6.8 प्रतिशत रह गया है। स्पीकर सर, इसके कई रीजन्ज़ हैं जैसे जब हम सड़कों की थाईडनिंग करते समय उनकी चौड़ाई 12 फुट से 18 फुट तक बढ़ाते हैं तो उस समय हमें साईड वाले पेड़ों को काटना पड़ता है। इसी प्रकार से यह भी आप सभी जानते हैं कि आज जगह-जगह पर बिल्डिंग्स बन रही हैं, जगह-जगह पर बड़े-बड़े मॉल्ज़ बन रहे हैं और जगह-जगह पर नई-नई कालोनियां भी बन रही हैं । वहां पर भी पेड़ काटे जा रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अर्बनाईज़ेशन की वजह से भी हमारा फॉरेस्ट कवरेज एरिया कम हो रहा है । इसके साथ ही मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूंगा कि यमुनानगर और कुरुक्षेत्र का जो एरिया है यह एरिया एग्रो फोरेस्ट्री के नाम से जाना जाता है। हमने इस एग्रो फोरेस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए अनेकों प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाये हैं जैसे पहले हम 10 रुपये प्रति पौधा देते थे जिसे अब हमने 5 रुपये प्रति पौधा कर दिया है। हमारी कोशिश मैक्सीमम प्लांटेशन की है ताकि हमारा फॉरेस्ट कवरेज एरिया बढ़ सके। कि हम अपने फारेस्ट कवरेज एरिया को 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत पर लेकर आयें ।

मुख्यमन्त्री कि (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जो मेरे साथी सदस्य ने सवाल पूछा है इस बारे में मैं इनको बताना चाहूंगा कि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की एक ग्रीन बैंच है। इस बैंच ने प्रॉविजनली यह फैसला किया है कि जो 187 करोड़ रूपया कंपाऊंड का इक्ट्ठा किया गया है उसका 10 प्रतिशत तो हरियाणा को मिल चुका है और जो बाकी का है वह भी मिल जायेगा । यह सुप्रीम कोर्ट की ग्रीन बैंच का फैसला है । इसके अलावा जहां तक फॉरेस्ट कवरेज की बात का सम्बंध है इस बारे में मैं अपने साथी को बताना चाहूंगा कि अभी हमारा फॉरेस्ट कवर 7 प्रतिशत है और हमारा लक्ष्य इसको 10 प्रतिशत तक करने का है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतू हमने इस साल पांच करोड़ पेड़ लगाने का निर्णय लिया है।

डी०ए०वी० कालेज नन्यौला (अम्बाला) के विद्यार्थियों का अभिनन्दन

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, मैं आपकी अनुमति से एक अनाऊंसमैंट करना चाहता हूं। स्पीकर सर, डी.ए.वी. कालेज, नन्यौला (अम्बाला) के विद्यार्थी दर्शक दीर्घा में मौजूद हैं । हम पूरे सदन की ओर से अगली पीढ़ी का स्वागत करते हैं । इसके साथ ही मैं सभी सम्मानित सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि हम सभी ठीक प्रकार का आचरण करें ताकि ये सभी विद्यार्थी जो कि इस सदन की कार्यवाही देखने के लिए यहां पर आये हुए हैं, वे यहां से अच्छी शिक्षा लेकर जा सकें। ऐसी हम परमपिता परमात्मा से कामना करते हैं।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर पुनरारम्भण

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या अरावलीज़ के अन्दर कोई वॉयलेशंज हुई हैं या नहीं ? अगर वायलेशंज हुई हुई हैं तो फरीदाबाद ज़ोन के अंदर जो डी.एफ.ओज़. के खिलाफ शिकायतें आई हैं क्या उन शिकायतों के ऊपर अमल करके कोई एक्शन लिया गया है ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, माननीय सदस्या की यह बात बिलकुल सही है । पूरे प्रदेश में जितनी वॉयलेशंज हुई हैं उनमें सबसे ज्यादा फरीदाबाद के अंदर हुई हैं। वहां की टोटल 128 शिकायतें हैं। इनमें से इस समय केवल 2 शिकायतें ही रेगूलराईज़ हैं और बाकी की 126 शिकायतें अब भी विभिन्न स्टेजिज़ पर पैंडिंग हैं । इनमें से कुछ कोर्ट्स के अन्दर पैंडिंग हैं। इसका कारण यह है कि हमारे प्रदेश में केवल दो ही एनवायरनमैंट कोर्ट्स हैं एक फरीदाबाद में और दूसरा कुरूक्षेत्र में । ये शिकायतें इन दो कोर्ट्स में ही पैंडिंग पड़ी हुई हैं। जहां-जहां वायलेशंज रेगूलराईज़ हुई हैं इनमें 55232 रुपये अथोराईज़ वॉयलेशन एक्ट के अंतर्गत जमा हुए हैं । जैसे-जैसे वॉयलेशंज रेगूलराईज़ होंगी उसके बाद कम्पाऊंड होकर पैसा जमा होता रहेगा ।

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैंने अपने काबिल मंत्री से यह पूछा था कि डिफाल्टिंग ऑफिसर्ज़ के अगेंस्ट क्या इन्होंने कोई एक्शन लिया है या अभी लेने जा रहे हैं ? दूसरी बात मैंने यह पूछी थी कि वे इस अमाऊंट को कहां खर्च करेंगे ? स्पीकर सर, मेरी इन दोनों बातों का जवाब मन्त्री जी की तरफ से नहीं आया है। स्पीकर सर, मेरी दूसरी बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप फोरैस्ट के लिए कोई टास्क फोर्स बनायेंगे और क्या सर्वे करवायेंगे कि सारी स्टेट में कितनी वायलेशन्ज हैं ? अध्यक्ष महोदय, ये वायलेशन्ज 772 नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि यह संख्या लाखों में मिलेगी । मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी टास्क फोर्स बना कर जो रोड्ज पर वायलेशन्ज की गई हैं या अरावली आदि की दूसरी वायलेशन्ज हैं उसकी आप जाँच करवायेंगे ताकि स्टेट को पैसा आ सके और फोरेस्ट्स को बचाया जा सके ।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, जहाँ-जहाँ पर हमें ऑफिसर्स के खिलाफ शिकायतें मिलेंगी वहाँ कार्यवाही की जायेगी । इसके लिए ये एक स्पेशल नोटिस दे दें तो मैं बता दूंगा कि कहाँ पर कितने ऑफिसर्स के खिलाफ हमने कार्रवाई की है । वैसे इन का यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है । दूसरी बात प्रो. सम्पत सिंह जी ने कही कि यह पैसा कहाँ लगेगा ? इस बारे में मैंने डिटेल में बताया है कि उसके लिए एक कैम्पा अथॉरिटी बनी हुई है । मैंने डिटेल में बताया है कि कहाँ पर लगेगा जैसे कि Protection and Management of Natural Forests पर लगेगा, Protection and Management of Wild Life Sanctuaries पर लगेगा । इसी प्रकार से जैसे आपको पता है कि मोरों की संख्या कम हो रही है उनको बचाने के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ पर एक बर्ड सैंचुरी बनायें । इसी प्रकार से गिद्दों की कम होती संख्या को ध्यान में रखते हुए हमने पिंजौर में एक सैंचुरी बनाई है। इसी प्रकार से डिफोरैस्टेशन की बात है। जिन प्लांटों को काटा जाता है उसके स्थान पर नये प्लांट लगाये जायेंगे। इसी प्रकार से कुछ अन्य कार्यों के लिये भी इस पैसे का उपयोग किया जायेगा। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया है कि हमें 187 करोड़ रुपया मिलना था लेकिन उसमें से हमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 19.11 करोड़ रुपये ही मिल पाये हैं। जिस प्रकार से हमारे पास पैसा आता रहेगा उसी प्रकार से हम पैसा लगाते रहेंगे। यह नोटिफिकेशन 14.1.2010 को हुई थी इसलिए इस पर कार्यवाही शुरू

नहीं हुई है । हम जल्दी ही इस पर कार्यवाही शुरू करेंगे । इसी प्रकार से एक टास्क फोर्स की इन्होंने बात की है। जो स्टेयरिंग कमेटी है वह मुख्य सचिव की अध्यक्षता में काम करेगी। वह कमेटी बाकायदा पॉलिसी फ्रेम करेगी । उसी प्रकार से मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में गवर्निंग बॉडी है वह भी यही काम करेगी कि किस प्रकार से हम पॉलिसी फ्रेम करें ताकि ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन हो और हमारा फोरैस्ट कवर्ड एरिया बढ़ सके । इसके अलावा एक तीसरी एक्जिक्यूटिव कमेटी पी०सी०सी०एफ० के अधीन बनेगी जो यह कार्यवाही करेगी । तीन कमेटियाँ मैंने बनाई हैं । जैसे कि किरण चौधरी जी ने भी यहां बताया कि हमारी जो मैक्सिमम वायलेशन्ज है वह जिला फरीदाबाद में ही है । वह कई तरीके से होती है जैसे Unauthorised way for Petrol Pump through strip forests उसकी वजह से होती है । Unauthorised way for dhabas, factories, farmhouses उसके थ्रू होती है । Unauthorised way for educational institute through strip forests उसके थ्रू होती है । Unauthorised way for builders along road sides उसके थ्रू होती है । In Faridabad total 51 violations are minor in nature but 75 violations are major in the areas closed under section 4 & 5 of Punjab Land Preservation Act, 1900. These are committed by Farm Houses, Group Housing Societies, Educational Institutes, HUDA, Municipal Corporation and crushers etc. Out of these 45 violations have been prosecuted and for rest of 30 violations, permission for prosecution is pending जहां तक आफिसर्ज के खिलाफ कार्यवाही करने की बात है उस बारे में मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अभी पिछले दिनों हमने पिंजौर में एक डी.एफ.ओ. को सस्पैंड किया है क्योंकि उन्होंने वायलेशन की थी। समय-समय पर जहाँ भी इस प्रकार की बात आती है, वहाँ पर हम कार्रवाई करते हैं। अगर माननीय सदस्य टोटल ऑफिसर्ज के बारे में जहाँ पर कार्रवाई हुई है, जानना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से नोटिस दे दें मैं जवाब दे दूँगा ।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगी कि जो इको जोन की नोटिफिकेशन होनी थी क्या हमारी सरकार ने करके वह केन्द्र सरकार को भेजी है या नहीं ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में माननीय सदस्या सैपरेट नोटिस दे दें, मैं जवाब दे दूँगा ।

Construction of Flying Club

***124. Smt. Sumita Singh :** Will the minister for Transport and Civil Aviation be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government for modernization and extension of Flying Club, Karnal; if so, the time by which modernization work is likely to be started thereon ?

परिवहन मंत्री (श्री ओमप्रकाश जैन) : हां, श्रीमान जी। कार्रवाई पहले ही प्रारम्भ कर दी गई है।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि उस पर क्या कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई कब से शुरू की गई और इसकी क्या प्रोपोजल बनाई गई है ?

श्री ओमप्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, फ्लाईंग क्लब करनाल के आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है :- बड़े हवाई जहाजों के लिए रन-वे का 4500 फिट तक विस्तार, एयरफिल्ड का विद्युतीकरण, बाऊंड्री वॉल का निर्माण, नये हैंगर का निर्माण तथा आधुनिक सिंगल ट्विन इंजन सिमूलेटर की स्थापना पर कार्यवाही पहले से ही प्रारम्भ कर दी गई है । करनाल हवाई अड्डे पर विभिन्न आधुनिकीकरण के कार्यों के लिए कदम उठाये गये हैं । उदाहरणत: उच्चस्तरीय उड्डयन प्रशिक्षण देने हेतू एक आधुनिक मल्टी इंजन पूर्णत: कम्पयूटराईज और सिमूलेटर मशीन जिसकी कीमत 1.25 करोड़ रूपए है, खरीदी जा रही है तथा शीघ्र ही स्थापित कर दी जाएगी । इसके साथ ही चारदिवारी के निर्माण कार्य 32 लाख रूपए की लागत से प्रारम्भ कर चुके हैं। रात्रि उड़ानों की सुविधा के लिए 18.62 लाख रूपए की राशि का प्रावधान किया गया है तथा इस कार्य के लिए राशि जारी की जा रही है, उसके आधुनिकीकरण, तकनीकीकरण के लिए कलपूर्जे सप्लाई की योजना विचाराधीन है। आधुनिक तकनीक का जैनरेटर खरीदा जा चुका है । करनाल हवाई अड्डे पर एडम ब्लाक उपलब्ध है। बाहर हवाई अड्डे के लिए वर्तमान रन-वे जिसका आकार 3000X150 है उसको बढ़ाकर 4500X150 करने का प्रावधान है । करनाल हवाई अड्डे पर लम्बा-चौड़ा हैंगर पहले ही बनाया जा चुका है। करनाल हवाई अड्डे का कुछ भाग बना हुआ है और बाकी पर काम शुरू हो चुका है। एडम ब्लाक-कम-छात्रावास तथा अधिकारियों व सुरक्षा कर्मियों के लिए रिहायशी मकान उपलब्ध हैं। करनाल हवाई अड्डे पर एक उच्च क्षमता वाला जैनरेटर सैट भी उपलब्ध है।

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सारी बातें तफसील से बता दी हैं । मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्या सुमिता सिंह जी को कुछ और बातें बताना चाहूंगा । अध्यक्ष महोदय, हरियाणा इन्स्टीच्यूट आफ सिविल एवीएशन यानी (HICA) करनाल में हम चलाते हैं, हमारे मुख्तलिफ सिविल एवीएशन को, जो उसको मेन करते हैं उनके द्वारा लगभग 24 साल से हरियाणा में कोई ट्रेनिंग एयर क्राफ्ट नहीं खरीदा गया था । हमारे पास जो भी सिसनाज़ थे वे पुराने थे । पहली बार कांग्रेस की सरकार के आने के बाद चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने यह विशेष अनुमति दी । हम हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि एशिया में पहले प्रान्त थे जिसने सिसना के दो ग्लास कॉकपिट एयर क्राफ्टस लगभग जहां तक मुझे याद है 75 से 80 लाख रूपए के बीच में उस समय में लेकर आए थे । यह हम लगभग डेढ़ वर्ष पहले लेकर आए थे । उसमें से एक परमानैंटली करनाल में स्टेशन किया गया है और एक हिसार में स्टेशंड है। 24 साल के बाद किसी सरकार ने हमारे बच्चों को नए प्रकार से प्रशिक्षण देने का ग्लास कॉक पिट का इन्तजाम किया हैं । अध्यक्ष महोदय, ग्लास कॉकपिट के बारे में आप समझते है कि जिस प्रकार से बड़े एयर क्रॉफ्ट ए-320, बोईंग और दूसरे हैं उनका जो कॉकपिट होता है, उसका जो इन्स्ट्रूमैंटेशन पैनल होता है उसको ग्लास कॉकपिट कहते हैं। हमने यह एयर क्राफ्ट इसलिए खरीदे हैं ताकि जो सिसना के ऊपर हमारे बच्चे ट्रेनिंग करें वे भी लगभग उसी प्रकार का प्रशिक्षण ले सकें । अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार की खरीद के बाद उसकी कीमत लगभग 130 लाख रूपए हो गई थी । हमारे मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार से अनुरोध किया और हम भारत सरकार के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी की चिट्ठी और उनके व्यक्तिगत अनुरोध के बाद दो किरण एयर क्राफ्ट बगैर किसी पैसे के हमें दिए हैं । जिनमें से एक विमान करनाल के हिका के पास स्टेशन किया हुआ है। इसके अलावा कैप्टन सतीश शर्मा जी की अध्यक्षता में भारत का सिविल एविएशन इन्स्टीच्यूट चलाते हैं। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने भी बगैर कोई पैसा लिए मुफ्त में हरियाणा के बच्चों को प्रशिक्षण में बढ़ावा देने के लिए एक ग्लास कॉकपिट सिसना एयर क्राफ्ट में दिया है । जिसके हमने फिर

हरियाणा में बच्चों की ट्रेनिंग के लिए स्टेशन किया है । इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या जी को बताना चाहूंगा कि हरियाणा के गठन के बाद हरियाणा में सिमूलेटर नहीं लगाया गया है। जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया है कि पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय मंत्री जी ने निर्णय लिया है और सिमूलेटर की खरीद के लिए हरियाणा की हाई पॉवर परचेज कमेटी को मामला भेज दिया गया है ताकि हमारे बच्चे बजाए इसके कि वे आस्ट्रेलिया जाएं, जैसे बहुत से हरियाणा के बच्चे अमेरिका, न्यूजीलैंड या दूसरी जगहों पर जाएं और 32-32 या 35-35 लाख रूपए देकर जाएं और ट्रेनिंग करके आए । हमारी सरकार ने अब स्पेशल रेट्स पर हमारे यहां पर ही ट्रेनिंग की व्यवस्था की है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि क्योंकि अकेली सरकार सारे इंस्टीच्यूट नहीं चला सकती इसलिए सिविल सैक्टर के अंदर प्राईवेट सैक्टर के लोग भी आ जाएं । मैं आपकी अनुमति से सदन को बताना चाहूंगा कि हमने फ्लाईंग ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट हरियाणा के बच्चों के लिए और जो हरियाणा के बाहर के बच्चे हरियाणा में आकर प्रशिक्षण लेना चाहें, उनके लिए ई.ओ.आई. यानी जिसको एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट कहते हैं, वह 27 अगस्त, 2008 को सब देशों के समाचार पत्रों में दिया । इसमें पिंजौर, करनाल, भिवानी और नारनौल की स्ट्रिप हैं । अध्यक्ष महोदय, भिवानी की स्ट्रिप पर बहुत कम लोग जा पाते थे और नारनौल की स्ट्रिप पर भी लगभग कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी । ये दोनों स्ट्रिप खाली पड़ी थीं इसलिए इन सबके लिए भी हमने एक ई.ओ.यू. दिया । 19 लोगों की इस बारे में डी०पी०आर० मिली । अध्यक्ष महोदय, उन 19 लोगों के नाम पढ़ने के बजाए मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि भारत सरकार में डी०जी०सी०ए० यानी डायरैक्टर जनरल, सिविल ऐवीएशन के पास और मिनिस्ट्री ऑफ ऐवीएशन के पास जो ट्रांजक्शन एडवाइजर हैं मैसर्ज ग्रान्ट थोन्टन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, उनको हमने अपना कंसलटैन्ट लगाया । बाकायदा इवैल्यूएशन कमेटी बनायी गयी । इनमें जो तीन फर्म्ज हैं वे हैं मैसर्ज ओरियन फ्लाईंग स्कूल, चैन्नई जो आलरेडी अपना फ्लाईंग स्कूल चैन्नई के अंदर चलाती है, मैसर्ज अम्बर ऐवीएशन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, देहरादून जो पूरे उत्तरांचल के अंदर अपना ऐवीएशन स्कूल चलाती है और मैसर्ज टच वूड एंटरटेनमैंट, नयी दिल्ली । इन तीनों फर्म्ज को कंसलटैन्ट की मदद से इवैल्यूएशन कमेटी ने शोर्ट लिस्ट किया और उसने पाया कि ओरियन फ्लाईंग स्कूल, चैन्नई ने करनाल और नारनौल दोनों जगहों के लिए क्वालीफाई किया है। अम्बर ऐवीएशन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, देहरादून ने पिंजौर, करनाल और नारनौल के लिए क्वालीफाई किया है। अध्यक्ष महोदय, हमने यह भी निर्णय लिया है कि यह जरूरी नहीं कि एक ही आदमी को एक ही स्ट्रिप दी जाए, एक से ज्यादा स्ट्रिप भी दी जा सकती हैं क्योंकि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हरियाणा इंस्टीच्यूट ऑफ ऐवीएशन भी बंद नहीं होगा बल्कि वे भी वहां अपना काम चलाते रहेंगे । इस समय यह कंसलटैन्ट ऑफ डिपार्टमैंट के पास रिव्यू पर है और रिवाइज्ड इन्सपैक्शन रिपोर्ट हमें नवम्बर, 2009 में मिली है । बहुत जल्द हम यह भी देंगे, करनाल की स्ट्रिप के लिए यह हो जाएगा ।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष जी, मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने नये सिसना एयरक्राफ्ट और सिमूलेटर करनाल फ्लाईंग क्लब को दिए । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि जो इन्होंने बात कही कि रन-वे को बड़ा किया जाएगा । मैं बताना चाहूंगी कि रन-वे को बड़ा करने के लिए साथ लगती जमीन को ऐक्वायर करना पड़ेगा । क्या इसके लिए अभी तक कोई कार्यवाही शुरू की गयी है ?

श्री ओमप्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही प्रारंभ है ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे विशेष तौर से निर्देश दिए हैं इसलिए मैं आपकी अनुमति से सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि एरो क्लब ऑफ इंडिया जो हिन्दुस्तान का सबसे पायनियर और पुराना क्लब है उसके प्रैजीडैन्ट कैप्टन सतीश शर्मा जी हैं और वही हमारे गाइडर भी हैं । उन्होंने यह निर्णय लिया है कि नारनौल जो दक्षिणी हरियाणा का एक पिछड़ा इलाका है, वहां पर ऐरो क्लब ऑफ इंडिया की एक वर्ल्ड क्लास ऐकेडमी बहुत जल्द चालू करेंगे ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या भिवानी की तरफ से कोई प्रपोजल आया है कि वहां जो हवाई पट्टी है, उसका विस्तारीकरण किया जाए? चौधरी बंसीलाल जी ने वहां पर एक हवाई पट्टी बनायी थी । उस समय एक मैसेज किया गया था कि वहां कोई कंटेनर टर्मीनल या कुछ और लेकर आएंगे । क्या हरियाणा सरकार की तरफ से इस बारे में कोई प्रपोजल केन्द्र सरकार को भेजी गई है क्योंकि मेरी सिविल ऐवीएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल जी से जब इस बारे में बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अगर आपकी सरकार कोई प्रपोजल भेजेगी तो हम आपको जरूर देंगे ।

श्री ओमप्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं विधायिका से कहूंगा कि वे इसके लिए सैपरेट क्वैश्चन दे दें, इसका जबाव दे दिया जाएगा ।

Concession in Tariff

***24. Shri Sampat Singh :** Will the Power Minister be pleased to state—

(a) whether any scheme giving some concession in tariff was announced for regular payees of electricity bills when the policy of waiving off of tariff arrears of tubewell farmers was announced; if so, the details thereof;

(b) the number of persons who were regular payees and have benefited out of that concessional scheme alongwith the total amount thereof;

(c) the total amount of arrears of agriculture tubewell owners waived off till today togetherwith the amount still pending; and

(d) the total number of categorywise defaulters of electricity consumers togetherwith the total amount thereof as on today ?

बिजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप) : श्रीमान, विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(ए) हां श्रीमान, नियमित रूप से बिजली बिलों को भरने/अदा करने वालों के लिए जून 2005 में टैरिफ में रियायत देने की योजना की भी घोषणा की गई थी जिन कृषि तथा घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा दिनांक 17-6-2005 तक पिछले 10 मास के बिजली बिलों का नियमित रूप से लगातार भुगतान किया गया था उनके लिए अगले 20 महीनों के

बिजली बिलों में एस०ओ०पी० (बिजली विक्रय) में 5 प्रतिशत की वित्तीय रियायत दी गई थी।

(बी) कुल 7536 नियमित उपभोक्ताओं ने जिन्होंने योजना के अन्तर्गत आवेदन किया और लगभग 16.15 लाख रुपए का लाभ प्राप्त किया।

(सी) योजना के अन्तर्गत माफ की गई कुल राशि 998.9 करोड़ रुपये थी जिसमें से 1,61,955 कृषि नलकूप मालिकों/उपभोक्ताओं की 349.14 करोड़ रुपए की राशि माफ की गई थी। दिनांक 31-1-2010 तक 1,37,170 कृषि उपभोक्ताओं के विरूद्ध 138.33 करोड़ रुपए की राशि बकाया है।

(डी) दिनांक 31-1-2010 तक बिजली उपभोक्ताओं की श्रेणी अनुसार बकाया राशि का विवरण निम्न प्रकार है:

क्रम संख्या	श्रेणी	संख्या	राशि (रुपये करोड़ में)
1.	ग्रामीण घरेलू	861243	1916.00
2.	शहरी घरेलू	277102	327.38
3.	गैर-घरेलू	144384	243.14
4.	औद्योगिक	23988	210.73
5.	कृषि	137170	138.33
6.	एच०एस०एम०आई०टी०सी०	170	0.80
7.	जन-स्वास्थ्य	9105	77.57
8.	पंचायत	998	8.09
9.	स्ट्रीट लाईट	252	17.24
10.	लिफ्ट सिंचाई	957	186.93
11.	अन्य	1515	56.15
	योग	1456884	3182.36

प्रो० संपत सिंह : अध्यक्ष महोदय, फार्मर्ज के पैडिंग लोन और रूरल एरिया में डीमैस्टिक पैडिंग लोन एरियर्स हैं उनको सरकार ने माफ किया है, उसकी सारे देश में सराहना हुई है और चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने एक लैंडमार्क स्थापित किया है और इससे दूसरी स्टेट्स भी कुछ लैसन ले रही हैं और

[प्रो० संपत सिंह]

सोच रही हैं कि उनको भी फार्मर्ज के लिए कुछ करना पड़ेगा । फार्मर्ज हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं उनको जिस तरीके से इंसैंटिव भी दिये गये, वह भी एक लैंड मार्क है। सरकार ने यह भी सोचा कि इस बात का केवल डिफाल्टर्ज को ही फायदा न हो इसलिए इंसैंटिव देंगे तो लोग पे करेंगे, इस बारे में सरकार की मंशा बहुत अच्छी थी । Speaker Sir, I will appreciate it like anything. परन्तु सर, यहां यह साबित हो जाता है Man proposes, God disposes. ये तो ऐसे हो गया कि Chief Minister proposes, utility disposes. जवाब के 'बी' पार्ट में बताया गया कि 7536 रैगुलर पेयीज कंज्यूमर्ज जो हैं उनको 16 लाख 15 हजार रुपये का फायदा मिला है । इंसैंटिव बहुत ही बढ़िया दिये थे उसमें यह था कि जो दस पहले के इंस्टाल्मैंट्स दे रहे हैं उनको 5 परसैंट रिबेट अगले 20 महीने तक मिलता रहेगा, यह बहुत ही बढ़िया पौलिसी थी । यह जो नंबर 7536 आया है एक तो इसके बारे में पूछना चाहूंगा कि उस टाइम जो पोलिसी ऐनाउंस हुई थी उस समय कितने रैगुलर पेयीज थे वह पेयीज अब कम क्यों आए हैं दूसरा यह जानना चाहूंगा कि--

श्री अध्यक्ष : दूसरी सप्लीमैंट्री आप फिर पूछ लेना ।

Prof. Sampat Singh : Speaker Sir, he is my batch mate. माननीय सदस्य बहुत इंटैलीजैंट हैं और मेरे क्लासमेट भी रहे हैं। ये 1982 बैच के हैं । इसलिए ये जवाब देने में सक्षम हैं।

Mr. Speaker : Sampat Singh ji, you will get another opportunity to speak.

प्रो० संपत सिंह : सर, मैं इसी के साथ ही यह भी पूछ रहा हूं कि एक जो डिफाल्टर्ज की बात है, ऐग्रीकल्चर में उस टाइम डिफाल्टिंग अमाउंट क्या थी और टोटल डिफाल्टर कितने थे ?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह तो मानते हैं कि यह एक बेहतरीन स्कीम थी जिसका उपभोक्ताओं ने 5 वर्ष पहले बहुत नुक्सान उठाया और उसकी वजह से जो पैंडिंग नुक्सान यूटीलिटीज को रहा वह सरकार के ऊपर 5 वर्ष पूर्व बोझ के रूप में आ गया। यह तो मुख्यमंत्री महोदय की दरियादिली समझ लीजिए कि वे जनता के हित को सदैव सर्वोपरि रखते हैं उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे किसान विशेषकर गरीब उपभोक्ता जो एक बहुत बड़े बोझ के नीचे दबा पड़ा था उसके लिए निर्णय लिया उसके लिए जैसा कि माननीय सदस्य मानते हैं कि एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है और तकरीबन 1100 करोड़ रुपये दिनांक 16.6.2005 को जो डिफाल्ट के रूप में थे ।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the question hour is over.

अध्यक्ष द्वारा स्थगन प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण सूचना में परिवर्तित करने सम्बन्धी सूचना

11-00 बजे **Mr. Speaker :** As Shri Om Prakash Chautala and 7 other M.L.As who had given notice of Adjournment Motion No.1 which was converted into Calling Attention Notice No.1 admitted for today, the 9th March, 2010 have been suspended from the services of the House for the remainder of the Session, therefore, the Calling Attention Notice No.1 will not be taken up.

भारतीय जनता पार्टी तथा इण्डियन नेशनल लोकदल के निलम्बित सदस्यगण को वापस बुलाने के लिए अनुरोध करना

श्रीमती कविता जैन: अध्यक्ष महोदय, श्री अनिल विज जी ने महंगाई के मुद्दे पर एक काम रोको प्रस्ताव सदन में चर्चा करने के लिए दिया था । मेरा आपसे निवेदन है कि यह एक ज्वलंत मुद्दा है इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा जरूर होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बहन जी, वे तो सारे चले गये आपको अकेले छोड़कर चले गये, उन्होंने क्या वुमैन डे मनाया ?

श्रीमती कविता जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस देश के अन्दर महंगाई का मुद्दा एक ज्वलंत मुद्दा है इसलिए इस पर चर्चा की जाये भारतीय जनता पार्टी, शिरोमणी अकाली दल और इण्डियन नेशनल लोकदल पार्टी के विधायकों को आपने सदन से बाहर निकाला है यह सरासर लोकतान्त्रिक परम्पराओं के खिलाफ है। मेरा आपसे अनुरोध हैं कि आप उन सबका निलम्बन वापस कीजिए। मैं चाहती हूं कि उन सभी विधायकों को सदन में वापस बुलाकर महंगाई के मुद्दे पर चर्चा करवाई जाए । आज महंगाई से ज्वलंत कोई मुद्दा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बहन जी, आपकी बात हो गई लेकिन उन्होंने बहुत माड़ा किया ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, कल जिस प्रकार का व्यवहार और जिस प्रकार का आचरण हमारे विपक्ष के साथियों ने सदन में दिखाया जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं यह एक दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार था हालांकि बहन जी तो उस समय सदन में उपस्थित नहीं थी। उन्होंने कल जो किया इस बात की हम आलोचना करते हैं और कण्डैम करते हैं । लेकिन प्रजातंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों ही बहुत जरूरी अंग हैं। मेरी आपसे दरखास्त है कि अगर बहन जी उन सदस्यों को जिनको कल निलम्बित किया था उनके दुर्व्यवहार के लिए अगर उनसे ये कहें कि वे सदन को सुचारू रूप से चलने देंगे तो भारतीय जनता पार्टी, शिरोमणी अकाली दल और इण्डियन नेशनल लोकदल के सदस्यों को भी वापस बुला लिया जाए we would welcome them. ये सदन में कोई कन्सट्रक्टिव सुझाव दें और अच्छी बात करें तो अच्छा होगा। मेरी आपके माध्यम से उनसे यही दरखास्त है ।

श्रीमती कविता जैन: अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि -------

श्री अध्यक्ष: बहन जी आपकी बात को हुक्म समझा है और सी०एम० साहब ने उन सदस्यों को वापस बुलाने के लिए कह दिया है। अब आप उनको बुला लाओ ।

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी की इस महंगाई के मुद्दे से जरूरी कुछ भी नहीं है मैं चाहती हूं कि सभी कार्यों को रोक कर बढ़ती महंगाई पर डिसकशन होनी चाहिए। क्या देश की जनता आपसे जवाब नहीं मांगेगी ?

श्री अध्यक्ष : बहन जी, इतना मान आपका किया। सी.एम. साहब ने आपकी बात मान ली और उनकी ससपैंशन को भी छोड़ने के लिए तैयार हैं । आप फिर भी जिद्द कर रही हैं । आप कृपा बैठ जाईये।

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय सदस्या अपनी बात कह लें मैं फिर अपनी बात कहूंगा ।

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं । अध्यक्ष महोदय, महंगाई एक जनहित का और संवेदनशील मुद्दा है। इस पर चर्चा करने की बजाए सभी सदस्यों का आपने निलम्बन कर दिया । आपको पता है कि जितने भी माननीय सदस्य हैं या मंत्री जी हैं उन्हें अपना वर्क आउट लिखकर लाना पड़ता है ।

Mr. Speaker : Please take your seat.

श्रीमती कविता जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने विपक्ष के सभी सदस्यों का निलम्बन करके विपक्ष का मुंह तो बन्द कर दिया है । आप केन्द्र की यू.पी.ए. सरकार को और राज्य की सरकार को जनता के कोप से नहीं बचा सकते जिस तरह से विपक्ष के सदस्यों का निलम्बन हुआ है उससे साफ लगता है कि दाल में जरूर कुछ काला है और सरकार जनता को जवाब देना नहीं चाहती । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बहन जी, आपकी बात मान ली गई है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि उनको बुलाने के लिए हाउस की सहमति ले ली जाए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, यदि हाउस की सहमति हो तो क्या इंडियन नेशनल लोकदल, भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणी अकाली दल के सदस्य जिनका कल उनके व्यवहार को देखते हुए निलंबन किया गया था, को वापस बुला लिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है कविता जी, हाउस की सहमति हो गई है, अब आप उनको बुला लाइए।

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत धन्यवाद।

मन्त्री द्वारा वक्तव्य

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही आगे तभी चलेगी जब इस महंगाई के मुद्दे पर चर्चा करवाई जाएगी । आपको हमारा काम रोको प्रस्ताव लाना पड़ेगा । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आपकी पार्टी के सदस्यों ने आपको जो कहा है अगर आपको वही करना है, तो आप बैठ जाइए । (विघ्न)

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही आगे तभी चलेगी जब महंगाई जैसे ज्वलनशील मुद्दे पर चर्चा करवाई जाएगी । यह बहुत जरूरी मुद्दा है । जिस देश के अंदर आम जनता खाने-पीने की वस्तुओं के लिए लड़ती हो वहां भुखमरी की स्थिति हो जाएगी । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : बहन जी, इसकी कोई रैलेवैंसी नहीं है ।

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी तभी सदन की कार्यवाही आगे चल सकती है। (विघ्न)

Mr. Speaker : You have said everything. Please take your seat. I will not allow you to discuss that.

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है । पहले काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए । (विघ्न) तानाशाही नहीं चलेगी । अध्यक्ष महोदय, आप विपक्ष के बगैर कोई चर्चा नहीं करवा सकते ।

लोक निर्माण(भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने कल सदन की गरिमा को भारी ठेस पहुंचाई। लोकतांत्रिक मर्यादाओं की कल धज्जियां उड़ाई गई। ये लोग हाउस की वैल में आ गए। हाउस को एक बार नहीं बल्कि 4-4 बार एडजर्न करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से आपने बार बार इनको बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं पूरे सदन की तरफ से आपको आपकी विनम्रता के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने रिपीटिडली हाउस को एडजर्न किया, आपने उनको उनकी सारी उदंडता के बावजूद अपने चैम्बर में आकर अपनी बात रखने का मौका दिया । अध्यक्ष महोदय, काम रोको प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी संसद में भी लेकर आई थी। वहां पर भी स्पीकर साहिबा ने उस काम रोको प्रस्ताव को एक शोर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में कंवर्ट किया था। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा क्योंकि वे इस समय सदन में मौजूद हैं। इनकी पार्टी ने संसद में जो काम रोको प्रस्ताव दिया था वहां की हमारी अध्यक्षा श्रीमती मीरा कुमार जी ने उस काम रोको प्रस्ताव को शोर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में कंवर्ट किया। आपके नेताओं ने उसको स्वीकार किया और उस पर बकायदा चर्चा हुई । अध्यक्ष महोदय, आपने कल काम रोको प्रस्ताव को कालिंग अटैंशन मोशन में कंवर्ट करके आज के लिए रखा । प्राइस राईज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुख्यमंत्री जी, पूरी सरकार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और पूरा देश इस मंहगाई के मुद्दे को लेकर चिंतित है। अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि जो काल अटैंशन मोशन एडमिट किया है उस पर भाजपा के साथी भी और लोकदल के साथी भी जितने चाहे सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने यह कहकर और दरियादिली दिखाई कि आप उन्हें पूरा समय प्राइस राइस के ऊपर चर्चा के लिए देंगे और गवर्नर एड्रैस पर चर्चा करने के लिए पूरा समय देंगे । अध्यक्ष महोदय, आपने यह कह कर और दरियादिली दिखाई कि आप बजट पर चाहे जितना बोल सकते हैं उतना बोल लेना, तो ऐसे में डिस्कशन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी परन्तु अगर कोई प्रिमैडीटेटिड माइंड यह बनाकर आए कि हमने सदन को चलने नहीं देना तो यह ठीक नहीं है। कल हमने सदन में देखा कि किस प्रकार से संसदीय कार्य प्रणाली को तहस-नहस किया गया । स्पीकर के पोडियम तक कल किस प्रकार लोग आए और कागज दिखाकर स्पीकर की तरफ किस प्रकार इशारे किए गए । जिस प्रकार से अभद्र भाषा का इस सदन में इस्तेमाल किया गया, और जिस प्रकार से यहां नारेबाजी की गई, यह सदन की गरिमा की परिपाटी नहीं है। हमारे सम्मानित साथी कम से कम यहां जो लिखा है उसको पढ लेते । प्राइस राइस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हालांकि हमारे साथी हाउस में मौजूद नहीं हैं लेकिन हमारी बहन जी यहां मौजूद हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कुछ तथ्य इस सदन के नोटिस में अवश्य लाना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि महंगाई जो है यह देश की सरकार के लिए और प्रदेश की सरकार के लिए चिंता का विषय है। हमने हरियाणा प्रांत के अंदर और पूरे देश में कई कारगर कदम महंगाई के बारे में उठाये हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश पूरे देश में खाद्यान के भण्डार को भरने वाला प्रदेश है। आज के दिन देश खाद्यान के मामले में पूर्णत: स्वावलंबी हुआ है तो उसमें हरियाणा प्रदेश का विशेष योगदान है। वर्ष 2008 में विश्व स्तर पर जब खाद्यानों की उपलब्धता में

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

कमी आ रही थी उस समय हरियाणा में खाद्यानों के उत्पादन में बढोतरी हुई । रबी की फसल में 2008 में देश में केवल 102 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन किया गया जिसमें चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में 52 लाख मीट्रिक टन का योगदान हरियाणा के किसानों ने, हरियाणा के गरीब मजदूर और हरिजन भाईयों ने केंद्रीय पुल में दिया ताकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा पूरे देश की कल्याणकारी योजनाएं सुचारू रूप से चलें । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से खरीफ की फसल में 2008 में हरियाणा के किसानों ने 49 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन किया तथा हमारे प्रांत ने केंद्रीय पूल में 14.23 लाख मीट्रिक टन चावल का योगदान दिया ताकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई व्यक्ति भूखा न रहे। इसके अतिरिक्त तीन लाख मीट्रिक टन बाजरे का योगदान भी हमने केन्द्रीय पूल में दिया। सर, जो यह मौजूदा साल 2009 चल रहा है इसमें भी रबी की फसल में केन्द्रीय पूल हेतू 69 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक के गेहूं की खरीद केवल हरियाणा ने की है । यह राज्य के लिए खरीद का एक नया कीर्तिमान भी है। गत वर्ष सितम्बर, 2009 के मध्य में केन्द्रीय सरकार ने विशेष अनुसंसा हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की कि खरीफ वर्ष 2009-10 में अधिक से अधिक चावल का योगदान हमारा प्रदेश केन्द्रीय पूल में दे क्योंकि पूरे देश में सूखे की स्थिति है । अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 2009 में सूखे जैसी स्थिति के बावजूद हरियाणा सरकार ने इस अप्रत्याशित चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना किया तथा धान की रोपाई हेतू विशेष तौर पर बिजली और पानी का प्रबंध किया । जिसके परिणामस्वरूप विषम परिस्थितियों में भी हरियाणा में धान का रिकार्ड उत्पादन हुआ तथा पिछले वर्ष के मुताबिक इस साल 45 प्रतिशत धान की अधिक खरीद हुई । अध्यक्ष महोदय, यहां यह बताना भी उचित है कि सीजन के शुरूआत में हमने केन्द्र सरकार को आश्वासन दिया था कि हम 13.90 लाख मीट्रिक टन चावल का योगदान केन्द्रीय पूल में देंगे। हमें गर्व है कि हम इस लक्ष्य को 34 प्रतिशत बढ़ाकर देंगे ताकि पूरे देश के खाद्यान भण्डार पूरे हो सकें । इस वर्ष हमारा केन्द्रीय पूल में चावल का योगदान 18.60 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक होगा । अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह सकता हूं कि खाद्यान के उत्पादन में हम देश के सबसे अग्रणी राज्य हैं । इसके अतिरिक्त मैं दो-तीन बातें सदन के नोटिस में और लाना चाहूंगा कि हमने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की समीक्षा के लिए पूरे राज्य में उच्च स्तरीय कमेटियों का गठन किया है । हरियाणा सरकार ने इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कि काला बाजारी और जमाखोरी की वजह से कीमतें न बढ़ें दिनांक 20 जून, 2008 को गेहूं, चावल, दालें, खाद्य तेल, खाद्य तेल बीजों संबंधी स्टॉक घोषणा आदेश जारी किया है जिसमें उक्त वस्तुओं की निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक रखने पर सरकार को सूचित करने का प्रावधान रखा गया है । इसी प्रकार से 12 अगस्त, 2009 को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से आदेश जारी करते हुए चीनी को भी इन वस्तुओं में शामिल किया गया है। इन आदेशों के पालन हेतू 11 हजार से अधिक डीलरों को हरियाणा सरकार ने चैक किया है तथा कई फर्मों के चालान भी किए गऐ हैं । अध्यक्ष महोदय, चीनी का उत्पादन हमारे प्रदेश में 2010-11 में और ज्यादा हो उसके लिए पूरे देश में सबसे ज्यादा हमने गन्ने का भाव 210 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अरली वैरायटी का फिक्स किया है और 200 रुपये प्रति क्विंटल लेट वैरायटी का है। हरियाणा पूरे देश में पहला ऐसा प्रांत है जिसने इतना ज्यादा रेट दिया है। स्पीकर सर, हमने यह निर्णय भी लिया है कि जो शूगर केन है उसको लगाने के लिए दो हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सबसिडी किसानों को दी जाये। इस प्रकार का क्रांतिकारी निर्णय लेने वाला भी हरियाणा शायद पूरे देश में पहला प्रान्त होगा। स्पीकर सर, इसके अलावा हमने शूगर केन पर

टैक्नालॉजी मिशन की व्यवस्था भी की है । स्पीकर सर, अगस्त, 2009 में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने सभी 9293 उचित मूल्य की दुकानों की विशेष चैकिंग का निर्णय लिया और इनमें से 7995 दुकानों का हम निरीक्षण भी कर चुके हैं। इनमें से 2018 उचित मूल्य की दुकानों में जहां निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं और कमियां पाई गई वहां पर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है । स्पीकर सर, आवश्यक वस्तुओं की दरों की समीक्षा करने के पश्चात् मुख्यमंत्री जी ने 28 जनवरी, 2010 को आवश्यक वस्तुओं की दरों में स्थिरता लाने, कीमतों की वृद्धि को चैक करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गेहूं, चावल, चीनी, दालों, खाद्य तेल और खाद्य तेल बीजों में जो स्टॉक की सीमा है वह भी पूर्णतया निर्धारित की। इससे थोक और परचून विक्रेता भी तय सीमा से अधिक उपरोक्त वस्तुओं का स्टॉक नहीं रख सकेंगे। स्टॉक सीमा को निर्धारित करने के उपरांत 15 फरवरी, 2010 यानि कि गत महीने से हम लगातार निरीक्षण कर रहे हैं । 678 थोक विक्रेताओं, 19 परचून विक्रेताओं का हमने पिछले 15 दिन से अधिक में निरीक्षण भी किया है। स्पीकर सर, राज्य सरकार द्वारा खुला बाज़ार बिक्री योजना के तहत 19522 टन गेहूं नारी निकेतनों, वृद्ध आश्रमों, कुष्ठ रोगी आश्रमों, बाल सुधार गृहों आदि को 1176 रुपये प्रति क्विंटल की दर से जारी करने का निर्णय लिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों को 6.86 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं दे रहे हैं। स्पीकर सर, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पी०डी०एस० के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को अतिरिक्त तौर पर हम 11.75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 31480 टन गेहूं और देंगे। स्पीकर सर, इसके अलावा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर फल और सब्जियों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जाये इसके लिए हरियाणा प्रदेश के 17 जिलों में 85 जगहों पर हमने अपनी मंडी का आयोजन करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार ने खुला बाज़ार बिक्री योजना के तहत पांच लाख मीट्रिक टन गेहूं जारी किया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा अगले दो मास में 2 से 3 लाख टन गेहूं तथा चावल खुले बाजार में बेचने का भी निर्णय लिया है। स्पीकर सर, मैं आपकी अनुमति से दो बातें और माननीय सदस्यों के नोटिस में लाना चाहूंगा। स्पीकर सर, हमारे जो विपक्ष के लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं उन्होंने कल और शुक्रवार को महंगाई बढ़ने और विशेषकर पेट्रो प्राईसिज़ के बढ़ने की चर्चा की थी । स्पीकर सर, मैं आपकी अनुमति से केवल दो आंकड़े सदन में देना चाहता हूं । स्पीकर सर, केन्द्र की सत्ता से कांग्रेस की सरकार वर्ष 1996 में चली गई थी। 1999 से लेकर अगस्त 2004 तक केन्द्र में एन०डी०ए० की सरकार थी। वर्ष 1996 में जब केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी उस समय डीज़ल का भाव 8.02 रुपये प्रति लीटर था। बाद में जब श्री बाजपेयी जी के नेतृत्व में केन्द्र में एन०डी०ए० सरकार सत्ता में आई तो लोकदल के पांच सांसदों के दम पर सत्ता में आई थी। अगर किसी भी समय ये लोकदल के पांच सदस्य अपना समर्थन वापिस ले लेते तो वह सरकार गिर जाती। उस समय डीज़ल 8.89 रुपये प्रति लीटर यानि 8.90 रुपये प्रति लीटर था। स्पीकर सर, लोकदल के पांच सदस्यों के समर्थन से चलने वाली केन्द्र सरकार ने किसानों के ईंधन डीज़ल की कीमत को 18 बार बढ़ाया। स्पीकर सर, यह मैं केवल आपकी अनुमति से सदन की जानकारी के लिए बता रहा हूं । जनवरी, 1999 में डीज़ल का भाव 8.89 रुपये प्रति लीटर था। फरवरी, 1999 में इसको बढ़ाकर 9.94 रुपये कर दिया, उसके बाद अप्रैल, 1999 में 10.37 रुपये प्रति लीटर किया, अक्तूबर, 1999 में इसको बढ़ाकर 13.91 रुपये प्रति लीटर कर दिया, जनवरी, 2000 में एन०डी०ए० की सरकार ने 14.04 रुपये प्रति लीटर कर दिया, सितम्बर, 2000 में एन०डी०ए० की तत्कालीन सरकार ने डीज़ल का भाव फिर से बढ़ा कर 16.55 रुपये प्रति लीटर कर दिया, मार्च, 2001 में फिर से डीज़ल का भाव बढ़ाकर 17.06 रुपये प्रति

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

लीटर कर दिया, फिर जनवरी, 2002 में बढ़ाकर 17.09 रुपये प्रति लीटर कर दिया, उसके बाद जून, 2002 में डीज़ल के रेट को बढ़ाकर 18.23 रुपये प्रति लीटर कर दिया फिर सितम्बर, 2002 में बढ़ाकर 18.68 रुपये प्रति लीटर कर दिया, अक्तूबर, 2002 में 19.63 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया और जनवरी, 2003 में 19.47 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया । इसी प्रकार से फरवरी, 2003 में ही उसको बढ़ा कर 19.84 रुपये कर दिया गया । सितम्बर, 2003 में डीजल के दाम 20.33 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिये गये । दिसम्बर, 2003 में 20.73 तथा जनवरी, 2004 में 21.73 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया। मार्च, 2004 में 21.74 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया। जून, 2004 में 22.74 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया और अगस्त 2004, में जब इनकी सरकार गई जब इन्होंने आखिरी बार बढाया उस समय डीजल के दाम 24.16 रुपये प्रति लीटर थे । इनकी सरकार ने 18 बार डीजल की कीमतें बढ़ाई थी। 8.02 रुपये प्रति लीटर पर हम डीजल के भाव छोड़ कर गये थे तब केन्द्र में लोकदल के 5 सांसदों के दम पर सरकार चलती थी, उन्होंने डीजल के दाम 24.16 रुपये तक बढ़ाये। अध्यक्ष महोदय, उस 5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नैशनल लोकदल की सरकार ने 171.77 परसैंट डीजल की कीमतों में बढौतरी की थी। इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, मिट्टी के तेल के दाम भी बढ़ाये गये। अध्यक्ष महोदय, जब कांग्रेस की सरकार 1996 में दिल्ली से गई तो उस समय मिट्टी के तेल की कीमत 2.52 रुपये प्रति लीटर थी। सर, मिट्टी के तेल की जरूरत सबसे ज्यादा हमारी गृहणियों को होती है। जब इनकी सरकार आई तो जनवरी, 1999 में मिट्टी के तेल का भाव 2.52 रुपये प्रति लीटर था। इन्होंने 5 बार मिट्टी के तेल के भाव बढाये । मार्च, 2000 में बीजेपी और इनेलो की सरकार ने मिट्टी के तेल का भाव 5.55 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा दिया। सितम्बर, 2000 में 8.35 रुपये प्रति लीटर तथा मार्च, 2002 में बढाकर इसको 8.98 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया। इसी प्रकार से जून, 2003 में 9.01 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया। इस प्रकार से 288 परसैंट इन्होंने मिट्टी के तेल के दाम बढ़ाए। इनकी सरकार गई और श्रीमती सोनिया गाँधी जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार दिल्ली में आई तो हमने 5 साल में एक पैसा भी मिट्टी के तेल के भाव नहीं बढ़ाये। इसी प्रकार से रसोई गैस जो गृहणियाँ इस्तेमाल करती हैं, जिस समय हमारी सरकार गई उस समय गैस के सिलेंडर के दाम 119.95 रुपये प्रति सिलेंडर था। जब 1999 में इनकी सरकार आई जो लोकदल के 5 सांसदों के सहारे पर चलती थी, इन्होंने आते ही एक सिलेंडर की कीमत 136 रुपये कर दी। फरवरी, 1999 में ही उसको बढ़ा कर 146 रुपये प्रति सिलेंडर कर दिया गया। मार्च, 2000 में 196.55 रुपये प्रति सिलेंडर तथा सितम्बर, 2000 में ही 232.25 रुपये प्रति सिलेंडर तक रसोई गैस के दाम बढाये गये। मार्च 2002 में 259.95 रुपये प्रति सिलेंडर तक बढाए। जून, 2004 में इनकी सरकार ने जाने से पहले 261.60 रुपये प्रति सिलेंडर कर दिया था। अध्यक्ष महोदय, 92.35 परसैंट तक इन्होंने रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाये। इसी प्रकार से जब हमारी सरकार गई उस समय पैट्रोल के दाम 21.30 रुपये प्रति लीटर थे और जब इनकी सरकार गई तो इन्होंने उसको 36.81 रुपये प्रति लीटर पर लाकर छोड़ा जो कि 53.76 परसैंट वृद्धि है। अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के साथी इसलिए सदन से नहीं गये कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया बल्कि वे इसलिए चले गये कि उनके पास इन आँकड़ों का कोई जवाब ही नहीं था । वे कायरता से अपनी पीठ दिखा कर यहाँ से चले गये हैं। न केवल भारतीय जनता पार्टी के साथी ही दौड़ गये बल्कि इंडियन नैशनल लोक दल के साथी भी दौड़ गये। इसी प्रकार से स्पीकर सर, यूरिया और डी.ए.पी. के

दाम भी बढ़ाये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो आँकड़े देकर बैठ जाऊंगा। एक मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आप भी एक किसान हैं और इस सदन में किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का बहुमत है। जब हमारी कांग्रेस की सरकार 1996 में दिल्ली में गई उस समय यूरिया के 50 किलो के एक बैग का रेट 166 रुपये था और जब 1999 में इनकी सरकार आई उस समय भी 166 रुपये प्रति बैग था। इन्होंने 29 जनवरी, 1999 को आते ही उस बैग का भाव 200 रुपये कर दिया। 29 फरवरी, 2000 को 30 रुपये और बढ़ा कर एक बैग की कीमत 230 रुपये कर दी। इसी प्रकार से 28 फरवरी, 2002 को 241.50 रुपये प्रति बैग कर दिये गये। सितम्बर, 2004 को जब ये गये तो 241.50 रुपये एक बैग की कीमत थी। चौटाला जी किसान का नाम लेकर जो घड़ियाली आँसू बहाते हैं। उन्होंने वाजपेयी जी को या बी०जे०पी० को कभी यह नहीं कहा कि आप यूरिया के बैग के रेट कम कर दो नहीं तो मैं समर्थन वापिस ले लूंगा। पता नहीं, इनकी क्या मजबूरी थी । पांच सांसदों के उपर सरकार चलती थी, क्या यह सच नहीं है। सबको मालूम है कि मेज के नीचे भाजपा से किस प्रकार से गुप्त समझौते चौटाला जी और उनके बेटे किया करते थे। इनके गुप्त समझौते की वजह से चाहे किसान भाड़ में जाएं इसकी चिन्ता इन्हें नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, जो हम यूरिया का भाव 166 पर छोड़कर गए थे उस यूरिया का भाव 241 रुपये इन लोकदल के साथियों के समर्थन वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। अध्यक्ष महोदय, 45.48 प्रतिशत यूरिया का रेट बढ़ाया था। डी०ए०पी०, जो आप, मैं और इस सदन के अधिकतर सदस्य अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं, जब हमारी सरकार गई तो 390 रुपए का रेट 50 किलो के बैग का था। इन्होंने 1999 के अन्दर 390 रुपए से बढ़ाकर 415 रुपए डी०ए०पी० के 50 किलो के थैले का रेट कर दिया था। अध्यक्ष महोदय, 29 जनवरी, 1999 को फिर रेट बढ़ाया और उसको 445 रुपए कर दिया। उसके बाद 28 फरवरी, 1999 को दोबारा से रेट बढ़ाकर 467 रुपए 50 पैसे कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो रेट बढ़ाए हैं। मैं यह दावे के साथ और जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि केन्द्र में श्रीमती सोनिया गांधी जी की सरकार है और सितम्बर, 2004 से लेकर आज तक केन्द्र की सरकार ने एक रुपए भी डी०ए०पी० और यूरिया का नहीं बढ़ाया है। कितना भी भार उनको सहना पड़ा लेकिन सोनिया गांधी जी की सरकार ने रेट नहीं बढ़ाया। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यूरिया, डी०ए०पी०, पैट्रोल, डीजल, एल०पी०जी० और कैरोसीन के रेट्स बढ़ाए हैं। आज वे इस सदन से दौड़ गए हैं और वे इसलिए दौड गए हैं क्योंकि वे सदन में हमें फेस नहीं कर सकते हैं। उनको मालूम है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाली इस देश की सरकार ने क्या क्या कारगर कदम उठाए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक आंकड़ा देकर अपनी बात को समाप्त करूंगा । किसान जब इनके राज में पिस रहा था तब डीजल के भाव इन्होंने 8 रुपए से बढ़ाकर 24 रुपए कर दिए थे, तब इन्होंने गैस के सिलैंडर का भाव 119 रुपए से बढ़ाकर 261 रूपए कर दिया था । तब मिट्टी का तेल 2 रुपए 52 पैसे से बढ़ाकर 9 रुपए कर दिया था। उस वक्त चौटाला साहब ने उल्टा डीजल और पैट्रोल पर वैट टैक्स लगाकर पैसा इक्ट्ठा करने का काम किया था । अध्यक्ष महोदय, आंकड़े अपनी कहानी खुद कहते हैं । इनके पांच साल के शासन काल में 1999-2000 से लेकर 2004-05 तक केवल डीजल के ऊपर वैट टैक्स हरियाणा के गरीब किसान और ट्रांसपोर्टरों से जो इक्ट्ठा किया वह आंकड़े मैं सदन में बताना चाहता हूं । 1999-2000 में चौटाला जी ने 31,018 लाख रुपए डीजल पर वैट टैक्स लगाकर इक्ट्ठे किए थे। 2000-01 में चौटाला जी ने और बी०जे०पी० की सरकार ने 42,902 लाख रुपए डीजल पर वैट टैक्स लगाकर इक्ट्ठे किए थे । 2001-02 में चौटाला जी ने 48,874 लाख रुपए डीजल पर वैट टैक्स लगाकर इक्ट्ठे किए थे । 2002-03 में 53,181 लाख डीजल पर वैट टैक्स लगाकर हरियाणा के किसानों से

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

इक्ट्ठे किए थे । 2003-04 में 71,891 लाख रुपए डीजल पर वैट टैक्स लगाकर चौटाला साहब की सरकार ने इक्ट्ठे किए थे। 2004-05 में 87,673 लाख रुपए वैट टैक्स से इक्ट्ठे किए थे यानि कि कुल 3365 करोड़ 39 लाख रुपए 5 साल में लोकदल और बी०जे०पी० की सरकार ने केवल टैक्स लगाकर हरियाणा के गरीब मजदूर, गरीब किसान और ट्रांसपोर्टरों से इक्ट्ठे किए थे। सर, पैट्रोल पर जो वैट टैक्स लगाया उससे 1433 करोड़ 94 लाख रुपए इन्होंने इक्ट्ठे किए थे। यानि कि पांच साल के अन्दर केवल डीजल और पैट्रोल पर वैट टैक्स से 4799 करोड़ 33 लाख रुपए की कुलैक्शन थी। अध्यक्ष महोदय, लगभग 4800 करोड़ रुपए गरीब किसानों से पांच साल में उनका शोषण करके इक्ट्ठे किए और आज ये गरीबी हटाने की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं । अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने आते ही श्रीमती सोनिया गांधी जी से आह्वान किया कि सरकारों को ही टैक्स का प्रतिशत वहन करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज गृहणियां सबसे ज्यादा एल०पी०जी० गैस के सिलैंडर का इस्तेमाल करती हैं। मेरी बहन यहां पर बैठी हुई हैं, इसलिए मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि जो 4 प्रतिशत वैट टैक्स लोकदल और बी०जे०पी० की सरकार एल०पी०जी० के सिलैंडर पर लगाती थी उस वैट टैक्स को हरियाणा सरकार ने 6 जून, 2008 से बिल्कुल समाप्त कर दिया है और ऐसा करने वाला हरियाणा ही अकेला ऐसा प्रान्त है जिसने 4 प्रतिशत वैट टैक्स को एल०पी०जी० के सिलैंडर से हटा दिया है। ऐसा करके 52 करोड़ रुपये के करीब चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व वाली हरियाणा की सरकार हरियाणा की गृहणियों को सब-सिडी देती है। हमने उस वैट टैक्स को बिल्कुल एबोलिश कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे किसान से डीजल पर 12 प्रतिशत वैट टैक्स लिया जाता था और हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने 6 जून, 2008 से उस दर को घटाकर 8.8 प्रतिशत कर दिया है। हमको ऐसा करने से नुक्सान हुआ है। हमको राजस्व का घाटा हुआ है। हमने आपकी तरह 4800 करोड़ रुपए किसानों और गरीबों से नहीं लिए हैं। हमको 2008-09 में लगभग 312 करोड़ रुपए का घाटा डीजल पर वैट की दर कम करने की वजह से हुआ है। स्पीकर साहब, 2009-10 में हमारा अनुमान है कि लगभग 350 करोड़ रुपये से अधिक का घाटा हुआ है। यह है एक सोशल वैलफेयर स्टेट, यह है एक गरीब और किसान के प्रति प्रतिबद्धता। अध्यक्ष महोदय, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि माननीय सदस्या जो यहां मौजूद हैं, को सदबुद्धि दे। इनको और बाकी विपक्ष के साथियों को कम से कम आकंड़ों और फैक्ट्स को फेस करने की हिम्मत दिखानी चाहिए। उनको कायरों की तरह से सदन से भागना नहीं चाहिए, महज कागज फेंक देने से काम नहीं चलता है। अध्यक्ष महोदय, हमारी आपस में एक रचनात्मक प्रतिस्पर्धा है, वाद विवाद है। अगर हम गलत होंगे तो हम उसको मानेंगे और यदि वे गलत हों तो उनको भी अपनी गलती को मानकर उसमें सुधार करना चाहिए।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

Mr. Speaker : Now, discussion on Governor's Address will resume. Now, Shri Kuldip Sharma, will resume his speech.

पंडित कुलदीप शर्मा (गन्नौर) : अध्यक्ष महोदय, 5 मार्च, 2010 को राज्यपाल महोदय ने सदन में जो अपना अभिभाषण दिया है मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। कल भी मेरी बात पूरी नहीं हो पायी थी।

श्रीमती कविता जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप विपक्ष के विधायकों का निलम्बन वापस करें उनको सदन में बुलाकर मंहगाई पर डिस्कशन करवानी चाहिए।

पंडित कुलदीप शर्मा : आप उनको जाकर बुला लाएं क्योंकि वे आपकी बात मानते हैं।

श्रीमती कविता जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, वे मेरे कहने से नहीं आएंगे मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उनको हाउस में बुला लें।

पंडित कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ये तो एक सम्मानित परिवार से संबंध रखती हैं इसलिए इनको तो चीनी के रेट के बारे में या एल०पी०जी० सिलेंडर के रेट के बारे में पता नहीं है।

श्रीमती कविता जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल बजट आने वाला है और उसके बाद उस पर डिसकशन होगी इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप विपक्ष के सदस्यों का निलम्बन रद्द कर उनको हाउस में वापस बुला लें।

श्री अध्यक्ष : आप ही उनको बुला लाएं।

श्रीमती कविता जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक आप उनको हाउस में आने की अनुमति नहीं देंगे तब तक वे सदन में वापस कैसे आ सकते हैं ?

पंडित कुलदीप शर्मा : आप उनको बुला लाएं तब तक मेरा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भाषण पूरा हो जाएगा। कल से मेरा भाषण मेरे गले में अटका हुआ है ।

श्रीमती कविता जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक आप उनके निलम्बन का आर्डर वापस नहीं लेंगे तब तक वे कैसे सदन में आ सकते हैं। आप मुझे उनको बुलाने के लिए आर्डर करें। कल बजट पेश होने के बाद डिस्कशन शुरू हो जाएगी इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उनको वापस सदन में बुला लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यह लोकतंत्र का गला घोटने के बराबर होगा ।

पंडित कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, 5 मार्च, 2010 को राज्यपाल महोदय ने सदन में जो अपना अभिभाषण दिया है मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

श्रीमती कविता जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लोकतंत्र के खिलाफ है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि जब तक आप विपक्ष के विधायकों का निलम्बन रद्द नहीं करेंगे तब तक वे कैसे सदन में आएंगे ? बजट सत्र की कार्यवाही विपक्ष के सदस्यों के बगैर कैसे पूरी होगी ?

श्री अध्यक्ष : वे तो आपको अकेला छोड़ गए हैं। आप जाकर उनको बुला लाओ।

श्रीमती कविता जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आपको विपक्ष के सदस्यों का निलम्बन रद्द करना होगा। ऐसे कहने से बात नहीं बनती है। आपको उनका निलम्बन रद्द करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यह सरासर लोकतंत्र के खिलाफ होगा।

पंडित कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदय का धन्यवाद करता हूं। कल यहां विपक्ष का जो इस प्रकार का घिनौना और अलोकतांत्रिक व्यवहार रहा है इस सदन को उनके इस व्यवहार की निंदा करनी चाहिए। हो सकता है कि कुछ समय पश्चात् माननीय संसदीय कार्य मंत्री यहां ऐसा निंदा प्रस्ताव लेकर आयें। माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 वर्ष पहले हरियाणा में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी, वह केवल सरकार और व्यक्ति का प्रभाव नहीं था, हरियाणा में एक नयी सोच और राजनीतिक संस्कृति आई जिससे हरियाणा में एक नया वातावरण आया। वर्ष 2005 से पूर्व किस प्रकार की कलुषित राजनीति हरियाणा में होती रही। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)** माननीय श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से किसान की जेब से छलावे से पैसा निकाल लिया गया, किस प्रकार से गुंडागर्दी की गई।

वाक आउट

श्रीमती कविता जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के बारे में बोलने का अवसर दिया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जाइए। (विघ्न)

श्रीमती कविता जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करती हूं कि सदन में हमारी पार्टी के नेता श्री अनिल विज जी ने जो आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के बारे में काम रोको प्रस्ताव दिया था उस पर मुझे बोलने का मौका दिया जाए और हमारी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के सदस्यों के निलंबन को रद्द करके उन्हें सदन में वापस बुलाया जाए, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जाएं।

श्रीमती कविता जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे एक और अनुरोध है कि मुझे आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर बोलने का मौका दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जाइए।

श्रीमती कविता जैन : उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं ऐज ए प्रौटैस्ट सदन से बाक आउट करती हूं।

(इस समय भारतीय जनता पार्टी की सदन में उपस्थित एकमात्र सदस्या श्रीमती कविता जैन आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर बोलने का समय न दिये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन कर गई)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भण)

पंडित कुलदीप शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, उस समय विपक्ष के दमन की राजनीति की गई। उसके बाद माननीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। उपाध्यक्ष महोदय, जिसने गरीबी नहीं देखी उसको अमीरी की कद्र नहीं होती। जिसको कांटा न चुभा हो उसको फूल का पता नहीं होता। जिसने इनेलो भाजपा का छह साल का कुराज न देखा हो उसको चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के राज की कदर नहीं हो सकती। आज हरियाणा में नक्शा बदला है और हरियाणवियों के चेहरों पर निखार आया

है। पहले किस प्रकार की संस्कृति हुआ करती थी। चौटाला जी और उनके परिवार के अन्य सदस्य 3-3 गठरियां नोटों की बांधकर चंडीगढ़ आया करते थे। मैंने एक दिन उनके बेटों से पूछा कि ये 200-200 किलो वजन क्यों बढ़ा रखा है, तो उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता हमें सिक्कों से तोलती है इसलिए हमने वजन बढ़ा रखा है ताकि ज्यादा पैसे आयें। इस चुनाव में बहुत शोर मचाया तो इनकी 31 सीटें आ गई। इनकी 31 सीटें क्या आ गई, जैसे मानो बासी कढ़ी में उफान आ गया हो। मैं मानता हूं कि कुछ गल्तियां हमसे भी हुई होंगी। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बाई डिफाल्ट 31 सदस्य आ गए लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता का जनादेश बिल्कुल साफ था। अगर आंकड़ों की राजनीति में जायें तो वोट परसैंट कांग्रेस को ही मिला या उसके मुकाबले में समूचे विपक्ष को मिला। उसमें इतना बड़ा अंतर है, जिससे एक क्लीयरकट बात उभरकर सामने आती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की कांग्रेस की सरकार को पूर्ण समर्थन और जनादेश हरियाणा की जनता ने अगले पांच साल तक हरियाणा प्रदेश में सरकार चलाने का दिया है। चौटाला जी को तो मैंने पहले ही कहा था कि कुर्सी के लिए इतना मत तड़फिये। मैं तो जन्म और कर्म से ब्राह्मण हूं। आपके छठे घर में शनि बैठे हैं। आप कुर्सी के चारों तरफ घूमते रहेंगे तो भी कुर्सी पर बैठ नहीं पाओगे। उनको मेरी बात समझ में नहीं आई, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता को यह बात समझ में आई है। पिछले पांच वर्षों में जो आल अराउंड डिवैलपमैंट हुई, जो कि माननीय राज्यपाल महोदय के संभाषण में परिलक्षित है। अब उस पर हमको गौर करना होगा। इस बात को जानना होगा कि उससे पहले क्या माहौल था और आज क्या माहौल बनकर आया है। जब इनका राज था तब एक ऐसा माहौल था जब हरियाणा से व्यापार और उद्योग उजड़कर दूसरे राज्यों में जा रहे थे। हरियाणा के इण्डस्ट्रियलिस्ट्स को शोषण करके दबाव की राजनीति बनाकर चन्दा इकट्ठा करके इस्पैक्टरी राज के दबाव में दोनों हाथों से लूटा जा रहा था। हरियाणा का इण्डस्ट्रियलिस्ट्स यू.पी. और राजस्थान में शिफ्ट हो रहा था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूँ :

"गुलची की सोच थी कि सब कुछ उजाड़ दूँ,
लेकिन हम बागबां थे चमन को बचा गये।"

उपाध्यक्ष महोदय, चौटाला जी की सरकार जाने के बाद हरियाणा में फिर माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। हमने कोर सैक्टर्ज को आईडैंटिफाई किया कि कहां क्या करने की जरूरत है ? सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान हरियाणा के किसानों पर गया। कोई भी केवल मात्र हरी पगड़ियां बांधने से किसान नहीं बन जायेगा, किसानों का हितैषी नहीं बन जायेगा या किसानों के हितैषियों से मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने हरियाणा के किसान से वायदा किया था कि किसानों को पानी और बिजली फ्री देंगे। जब हरियाणा का किसान इनको अपना वायदा याद कराने के लिए कण्डेला में इकट्ठा हुआ तो माननीय चौटाला जी ने हरियाणा के किसानों पर गोलियां चलवाई और घोड़ों की टापों के नीचे हरियाणा के किसानों को रौंद डाला गया। कभी महाभारत के युद्ध के समय में तरावड़ी का मैदान लाल हुआ करता था लेकिन उससे भी ज्यादा लालाज़ार किसान हितैषी चौटाला साहब के राज में जींद के अन्दर देखा गया। इतनी गोलियां चलीं जितनी हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध में नहीं चली होंगी। चौधरी देवीलाल जी स्वर्ग से बोले क्या दीवाली आ गई है, बोले नहीं आपका बेटा पटाखे चला रहा है और गोलियां चलवा रहा है। वह किसान जो उसको उनका वायदा याद करवाने गया था उस पर गोलियां चलवायीं। माननीय श्रीमती सोनिया गान्धी जी के निर्देशन पर पहली जनसभा सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने जींद में 14.5.2009 को सरकार बनने के बाद की थी। उसमें

[पंडित कुलदीप शर्मा]

जो पहली घोषणा की थी उसकी चर्चा अभी श्री सम्पत सिंह जी ने भी की है। सारा हिन्दुस्तान मानता है कि हरियाणा का किसान बिजली के बिलों के नीचे दबा और कुचला गया था। उन किसानों को राहत देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1600 करोड़ रुपये बिजली के कर्ज के माफ किए और बिजली के बिलों की माफी की। इसके साथ-साथ जो नई स्कीमें लेकर आये हैं, जिससे एक नई संस्कृति बनी कि हरियाणा के लोगों ने अब बिजली के बिल भरने शुरू कर दिये हैं । इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के अन्दर कोर सैक्टर और इलैक्ट्रिसिटी को भी आईडैंटिफाई किया गया । यहां पर लोग चार-चार बार, छः-छः बार मुख्यमंत्री रहे हैं वे 10-10 और 15-15 साल तक मुख्यमंत्री रहे लेकिन उनका विजन माओपिक था । उनकी दूरगामी सोच ने भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बनाई। अगर वे भविष्य के लिए कोई योजनाएं बनाते तो हर साल 14 से 17 प्रतिशत की बिजली की मांग बढ़ती है उसके लिए कोई योजना बनती । चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी आज सदन में मौजूद नहीं हैं, वे छः बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं उनके शासन काल में एक भी पॉवर प्लांट हरियाणा में नहीं लगा, अगर लगा हो तो वे इस सदन को बता दें। उसके मुकाबले में पानीपत में जो थर्मल प्लांट हमने बनाया था उस पर चौधरी देवीलाल का नाम लिखवा देने से क्या वह प्लांट चौधरी देवीलाल द्वारा बनवाया माना जायेगा। वह प्लांट चौधरी देवीलाल ने नहीं बनवाया था, वह कांग्रेस सरकार की देन थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोर सैक्टर को आईडैंटिफाई किया और चार पॉवर प्लांट केवल मात्र साढ़े चार साल की अवधि में हरियाणा में लगाने का काम किया है। इसको कहते हैं भविष्य की सोच वाला नेता। एक यमुनानगर का पॉवर प्लांट आलरेडी प्रोडक्शन में हैं। खेदड़ का पॉवर प्लांट प्रोडक्शन में ट्रायल बेसिज पर चल रहा है। ये लोग आरोप लगाते हैं कि क्षेत्रवाद की राजनीति हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि ये हरियाणा पर नजर डालें और देखें कि हरियाणा में क्या-क्या विकास कार्य हो रहे हैं ? हमारे मुख्यमंत्री महोदय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने पहला पॉवर प्लांट यमुनानगर जिले में लगाया। दूसरा पॉवर प्लांट हिसार जिले के खेदड़ में लगाया। अगर यूनिवर्सिटीज लगाने की बात आई तो सैंट्रल यूनिवर्सिटी महेन्द्रगढ़ में लेकर आए। डिफैंस यूनिवर्सिटी गुड़गांव को दी गई। सैनिक स्कूल रिवाड़ी को दिया गया। मैडीकल कालेज ई०एस०आई० फरीदाबाद में दिया गया। आज कल्पना चावला के नाम से एक मैडीकल कालेज करनाल में बनाया जा रहा है। इन लोगों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। ऐलनाबाद में मात्र वोट लेने के लिए क्षेत्रवाद की इन्होंने राजनीति की। मुख्यमंत्री की तो सोच समस्त हरियाणा के प्रति होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये मुद्दा उठा रहे हैं कि सिरसा में यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ। क्या इस बात के लिए ये जवाबदेह नहीं है कि 6 साल तक ओम प्रकाश चौटाला का शासन रहा और वह शासन 2005 में खत्म हुआ। इनके पिता चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री रहे और हरियाणा के भी मुख्यमंत्री रहे। इतने सालों तक मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री जैसे पद होने के बाद भी सिरसा में समस्याएं थी, यह बड़ी ही विचित्र बात थी। सिरसा में रोड्स और ब्रिजिज ये लोग नहीं बना सके । सिरसा का बाई पास ये लोग तैयार नहीं कर सके । चौधरी देवीलाल के नाम से यूनीवर्सिटी बनाने की बात की गई थी। उस यूनीवर्सिटी के दो कमरे और उसकी चार दीवारी बनाकर उसको अधूरा छोड़कर ये चले गए। चौधरी देवीलाल तीन तीन बार चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के खिलाफ चुनाव लड़कर हारे भी हैं लेकिन उसके बावजूद भी यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की ऊंची सोच थी कि चौधरी देवीलाल के नाम से बनी सिरसा की यूनिवर्सिटी को उन्होंने बनवाया । ये तो उस यूनीवर्सिटी को इसलिए नहीं चला रहे थे क्योंकि इनके चौधरी देवीलाल विद्यापीठ इंजीनियरिंग कालेज और दूसरे कई

प्राइवेट इंस्टीच्यूट सिरसा में थे । अगर ये यूनिवर्सिटी को चला देते तो वे इंस्टीच्यूट्स कैसे आगे चलते। इसी छोटी सोच के साथ इन्होंने कभी उस यूनिवर्सिटी को परिपूर्ण नहीं होने दिया । उपाध्यक्ष महोदय, आज चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की आकाश को चूमती इमारतें इस बात की गवाई देती हैं कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का अगर निर्माता कोई है तो वह कांग्रेस की सरकार है और इसके नेता चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी हैं न कि ओम प्रकाश चौटाला । ओम प्रकाश चौटाला और हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा में फर्क क्या था ? इन दोनों में फर्क नियत का था, फर्क सोच का था । एक तरफ छोटी सोच थी और दूसरी तरफ बड़ी सोच थी। एक तरफ ऐसे लोग थे जो खोखले नारों के साथ हरियाणा की जनता को छलना चाहते थे, किसान का नाम लेते थे, पानी का नाम लेते थे और बिजली का नाम लेते थे। उपाध्यक्ष महोदय, आज वे लोग सदन में नहीं हैं और पता नहीं वे कब आएंगें । मैं सदन के माध्यम से उनसे पूछना चाहूंगा कि जब इनको राज करने का मौका मिला तो इन्होंने इन समस्याओं के बारे में क्या किया । हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी हरेक मंच से पूछते हैं कि कोई एक स्कीम का नाम बता दो या एक नीतिगत फैसले का नाम बता दो जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किसान के हक में किया हो । एक फैसले का नाम बता दो जो उन्होंने हरियाणा में बिजली उत्पादन करने के लिए लिया हो । एक फैसला बता दो जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति के लिए ओम प्रकाश चौटाला की सरकार ने लिया हो। हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किए हैं। इस देश में पोलीटिकल डैमोक्रेसी तो आ गई लेकिन सोशल डैमोक्रेसी के लिए सबसे पहले एम्पावरमैंट का कोई अस्त्र है तो वह शिक्षा है। इस बात को आइडैंटीफाई करने वाले हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी पहले व्यक्ति हैं। महिलाओं की पढ़ाई के लिए गुरूकुल को भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय का स्वरूप दिया है जो कि नॉर्थ इण्डिया में महिलाओं के लिए एक मात्र यूनीवर्सिटी बनी है, जिसमें महिलाओं के लिए अलग से मैडीकल, डैंटल और इंजीनियरिंग कालेज बन रहे हैं। इंजीनियरिंग की 46 फैक्लटीज इस यूनीवर्सिटी में माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रांत की लड़कियों को पहले उच्च शिक्षा लेने के लिए दूसरे प्रांतों में जाना पड़ता था लेकिन आज हरियाणा में गोहाना के अंदर खानपुर गांव में हमारी बच्चियों को हर तरह की उच्च शिक्षा मिल रही है। विपक्ष के साथी आज वहां जाकर देखें कि जहां पहले कीकर और बेरी के पेड़ होते थे उनका स्थान बहुत खूबसूरत इमारतों ने ले लिया है और वहां पर आज चमन खिल गये हैं। इसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी राजीव गांधी एजूकेशन सिटी भी हमारे यहां लेकर आये हैं जिससे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत डवैल्पमैंट होगी। राजीव गांधी एजूकेशन सिटी पर आज जोरों से काम चल रहा है। इंटरनैशनल स्टैंडर्ड की एजूकेशन इन्स्टीच्यूट्स की और इस देश के टॉप इन्स्टीच्यूट्स की ई०ओ०आई०एस० वहां पर एजूकेशन लाने के लिए आई हैं। इसी के साथ-साथ मैडीकल कालेज रोहतक को पी.जी.आई. एम०एस० बनाया है। ऐम्ज और आई०आई०एम० को माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा के अंदर लेकर आये हैं। इसी तरह से इण्डियन लैदर इन्स्टीच्यूट को लेकर आये हैं। इस प्रकार से न जाने सैंट्रल लैवल के कितने ही इन्स्टीच्यूट हमारे मुख्यमंत्री जी प्रदेश में लेकर आये हैं और भविष्य में भी लेकर आयेंगे। इसी प्रकार से टैक्नीकल कालेजिज, इंजीनियरिंग कालेजिज, बी०एड० कालेजिज, नर्सिंग कालेजिज, फार्मेसी कालेजिज आदि मुख्यमंत्री जी प्रदेश में लेकर आये हैं। जिनकी पढ़ाई करने के लिए हमारे प्रदेश के बच्चों को अमरावती, जम्मू और बिहार जैसे प्रदेशों में जाना पड़ता था और असुरक्षित माहौल में रहना पड़ता था लेकिन हमारे राजकाल में, कांग्रेस सरकार के राज में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुशल नेतृत्व की बात की है और प्रदेश की जनता को बहुत अच्छा विजन दिया है। हमारे मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण आज प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तरक्की की है जिसकी वजह से आज प्रदेश में बहुत ज्यादा टैक्नीकल

[पंडित कुलदीप शर्मा]

सीट्स हैं । We have around 80,000 seats for technical field जो कि कल को इस देश की जरूरत है। India is emerging as the biggest knowledge bank in the world और हमें टैक्नोक्रैट्स, स्किलफुल लेबरर्ज, स्कील्ड टैक्नीशियंज आदि इन सबकी जरूरत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने हरियाणा प्रदेश के नौजवानों के लिए जो यह नर्सरी लगाई है इसमें से आने वाले समय में हमारे बच्चे निकलकर आयेंगे तो देश के अंदर हरियाणा का एक अलग प्रभाव बनेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब और किसान के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देने के लिए बहुत ठोस कदम उठाये हैं । इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं । आज के युग में शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं है और शिक्षा के बिना कोई लिबरेटर भी नहीं रह सकता। It is biggest emancipator. अध्यक्ष महोदय, फीस न देने के कारण गरीब के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे और लड़कियां तो प्राईमरी एजूकेशन भी नहीं ले पाती थी । हमारे साथियों ने गरीब और हरिजन के नाम पर राजनीति तो बहुत की लेकिन उनके बच्चों की शिक्षा के लिए कोई काम नहीं किया परंतु हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजनीति नहीं कन्ट्रीब्यूशन किया है और गरीब के बच्चों को शिक्षा देने के लिए कंक्रीट स्टैप्स उठाये हैं । मैं माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी का धन्यवाद करता हूं और पूरे सदन को भी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए कि इन्होंने गरीब के बच्चों के लिए पहली कक्षा से वजीफे की बहुत बेहतर स्कीम प्रदेश में शुरू करके गरीब के बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल की चार दीवारी में लाने का काम किया है । मुख्यमंत्री जी की बेहतर वजीफा स्कीम की वजह से ही आज प्रदेश में हरिजन और गरीबों के चार लाख बच्चे विद्यालय की चार दीवारी में आये हैं । उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की तरफ भी पिछले पांच साल के दौरान विशेष ध्यान दिया है। जहां पहले स्कूलों में टीचर नहीं होते थे उनकी पूर्ति करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने मैरिट बेसिज पर बिना किसी सिफारिश के 18 हजार गैस्ट टीचर्ज को इंडीकेट करके शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं एग्रीकल्चर सैक्टर के बारे में बात करना चाहूंगा। जहां पहले किसानों को लूटा जाता था वहां आज के विपक्ष के साथी उस समय चुप बैठे रहते थे। माननीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने सदन में सारे फिगर्ज बताये हैं। इनके राज में एक नहीं 18-18 बार रेट्स बढ़े। स्पीकर सर, किसान को उसकी फसल की उचित कीमत मिल जाये इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अगर किसी ने ईमानदारी से स्टैप्स उठाये हैं तो वह कांग्रेस की सरकार द्वारा उठाये गये हैं। इस बात के लिए अगर किसी ने केन्द्र और राज्य स्तर पर लड़ाई लड़ी है तो वह चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने लड़ी है। मैं इस बात की मिसाल इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि जब पैडी का एक्सपोर्ट रूक गया था उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री विदेश की यात्रा पर थे। जब वे 18 दिन की विदेश यात्रा से वापस घर लौटे तो दिल्ली एयरपोर्ट से अपने परिवार को मिलने के लिए घर नहीं गये बल्कि प्रधानमंत्री के कार्यालय में गये और उनका दरवाजा खटखटाया फिर प्रधानमंत्री को साथ लेकर यू०पी०ए० की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी के पास गये और उनको यह कहा कि वह अपने घर भी तभी लौटेंगे जब किसान को उसकी जीरी की फसल की उचित कीमत मिलेगी । डिप्टी स्पीकर सर, किसान के हित के लिए ऐसा साहसिक कदम उठाने वाले पूरे हिन्दुस्तान में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी पहले मुख्यमंत्री हैं। मैं विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस प्रकार का कोई आंदोलन किया था। इन्होंने किसानों की मांग को

प्रधानमंत्री और यू०पी०ए० की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी के समक्ष उठाया और उसी का नतीजा था कि पैडी की फसल का एम०एस०पी० विपक्ष की सरकार के समय जितना था उसको इतना बढ़ाया कि वह पहले से दोगुणा हो गया। इसी प्रकार से गेहूं की फसल के मूल्य के बारे में किया गया। जब यू०पी०ए० की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी को झाड़ली के पॉवर प्लांट की फाऊंडेशन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आये थे तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रीमती सोनिया गांधी जी से सलाह मश्विरा करके इस बात की घोषणा करवाई थी कि गेहूं का जो प्राईस है उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। विपक्ष की सरकार के समय में गेहूं का मूल्य कभी 5 रुपये, कभी 7 रुपये और कभी 8 रुपये बढ़ाया जाता था लेकिन हमारी सरकार के पिछले 5 वर्ष के शासन काल के दौरान गेहूं का दाम पहले से दोगुणा कर दिया गया। इस प्रकार से गेहूं का पूरे देश में जो हाईऐस्ट प्राईस है वह अगर कभी कहीं मिला है तो वह हमारे माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के सद्प्रयासों से कांग्रेस की गवर्नमैंट के अंदर हरियाणा के किसानों को मिला है। इसी प्रकार से गन्ने की बात कर लीजिए। विपक्ष के भाई एक तरफ तो गांव में जाकर गांव के लोगों के सामने बोलते हैं कि भाई यह सरकार गन्ने का भाव बहुत ही कम दे रही है और दूसरी ओर शहर में जाकर शहर के निवासियों से बोलते हैं कि सरकार ने चीनी का रेट बढ़ाकर चीनी को बहुत ज्यादा महंगा कर दिया है। ये दोपलड़ी बात करते हैं। इन लोगों के व्यवहार में ड्यूलटी है। हमारी सरकार ने गन्ने की फसल के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए गन्ने का प्राईस 210 रुपये, 215 रुपये और 220 रुपये तक किया। इस प्रकार से आज अगर पूरे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा गन्ने का प्राईस किसी को मिल रहा है तो वह हमारे माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के प्रयत्नों से हरियाणा के किसानों को मिल रहा है। इसी प्रकार से सहकारिता विभाग के किसानों के कर्जों को माफ करने का नारा तो स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी ने दिया था लेकिन उन द्वारा कर्जे माफ किये गये थे केवल मात्र 28 करोड़ रुपये के जब चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हुए तो उन्होंने सबसे पहले इस बात को आईडैंटीफाई किया कि किसान को ऋण करना है। इसलिए कर्जों पर जो ब्याज था लगभग 868 करोड़ रुपये सबसे पहले उन्होंने इस ब्याज को माफ किया। विपक्षी भाईयों के राज में कर्ज अदायगी न करने की सूरत में किसानों को हथकड़ियां लगाई जाती थी। यह काला कानून अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा था। इसके साथ ही यह भी होता था कि अगर किसान अपना कर्ज अदा न कर पाये तो उसकी ज़मीन को भी कुड़क कर लिया जाता था और उनको जेलों में बंद कर दिया जाता था। यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी कि सोच थी कि वे किसानों को इस प्रकार की परेशानियों से सदा-सदा के लिए मुक्त कराना के लिए इस बारे में दो कानून लेकर आये। पहला यह कि हरियाणा के किसी किसान की ज़मीन केवल इसलिए कुड़क नहीं की जायेगी कि वह अपना ऋण 12-00 बजे नहीं चुका सका। इसके लिए उन्होंने और कई तरीके सुनिश्चित किए। अब किसी किसान के द्वारा कर्जा न देने की सूरत में उस किसान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह है किसान के प्रति सोच। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि किसी किसान की भूमि का मूल्य जो है वह उसके लिए बड़ा महत्व रखता है। जब किसान ट्रैक्टर के लिए लोन लेने के लिए बैंक में जाता था तो बैंक उसकी 4 एकड़ भूमि को ट्रैक्टर के लिए लिये गये लोन के बदले अपने पास गिरवी रख लेता था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में किसान की भूमि की कीमत के हिसाब से उसके ट्रैक्टर के लोन लेने के लिए निर्धारित किया है। मान लीजिए किसी किसान ने ट्रैक्टर के लिए 2 लाख रुपये का लोन लिया और बैंक द्वारा अपने पास रखी गई भूमि की कीमत 10 लाख रुपये है तो बैंक उसमें से 2 लाख रुपये की भूमि ही अपने पास

[पंडित कुलदीप शर्मा]

सिक्योरिटी के तौर पर रख सकता है बाकी नहीं। यह सोच है किसान के प्रति। ये लोग तो किसान की जेब से पैसा निकालते थे। इन्होंने तो किसानों पर गोलियां चलवाई। अगली बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह है सोशल जस्टिस की। चौटाला साहब, यहाँ नहीं हैं। उनके समय में 2 लाख 37 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान की भूमि का अधिग्रहण हो जाता था। मेरा चुनाव क्षेत्र गन्नौर है उसमें एक बड़ा इंडस्ट्रीयल सैक्टर बना। ओम प्रकाश चौटाला जी के समय में किसान की एक एकड़ जमीन की कीमत मुआवजे के रूप में 2.37 लाख रुपये मिली। उपाध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्रीयल कंपलैक्स के फेज-2 और फेज-3 के लिए चौधरी भूपेन्द्र हुड्डा और कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में अभी-अभी जमीन का अधिग्रहण हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, किसान को उसके लिए 54 लाख 57 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिला है। इस प्रकार से हमारी सरकार ने आते ही फ्लोर रेट फिक्स कर दिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप वाइंड अप कीजिए ।

पंडित कुलदीप शर्मा : सर, मेरा कल से अटका हुआ भाषण है इसमें और समय लगेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के लोग कल शोर मचा रहे थे और काम नहीं करने दे रहे थे। सदन का चलना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाद-विवाद से समस्याओं का हल निकला करता है लेकिन चौटाला साहब का लोकतंत्र में तो विश्वास रहा ही नहीं। लोकतंत्र को तो इन्होंने अपने पैरों के नीचे कुचला है। ये लोग कानून व्यवस्था की बात करना चाह रहे थे, उनके राज में जिस प्रकार से गुण्डागर्दी हुई, उसका जीता जागता प्रमाण आज मेरे पास है। एक चिट्ठी चौटाला जी के भाई प्रताप सिंह चौटाला ने लिखी थी कि मुख्तार अंसारी, चौटाला जी के फार्म पर देखे गये थे । शाहबुद्दीन जोकि बिहार के माफिया का डॉन है वह तेजा खेड़ा फार्म पर अभय चौटाला जी के साथ आराम फरमा रहे थे। 'चौटाला सील्डिंग रविकान्त' ये हैडलाईन्ज हैं। चौटाला साहब की सरकार में ऐसे लोगों को बचाने का काम भी किया गया जिनके खिलाफ बड़े सीरियस चार्जिज थे। कितने ही क्रिमिनल को जेलों से निकालने के लिए जेलों के दरवाजे खोल दिये गये थे, उनकी सजा माफ करवा दी गई थी जिनको फांसी की सजायें थी उन लोगों को जेल के दरवाजे खोल कर बाहर जाने दिया गया था। उपाध्यक्ष महोदय, राजेश साहरण नाम का आदमी जो मर्डर और रेप के केसिज़ का एक्यूज्ड रहा है वह पंजाब और हरियाणा का किडनैपिंग का किंग पिन रहा है, डिम्पी नाम का आदमी जो अब किसी एनकाउंटर में मारा गया है, उसकी फोटो अभय चौटाला जी के साथ छपी हुई हैं। इनकी कम्पनी देखिए, हिन्दुस्तान के तमाम नामचीन गुण्डे, माफिया डान्ज का तेजा खेड़ा फार्म हाउस शरणगाह बना हुआ था। उपाध्यक्ष महोदय, अभय चौटाला ऐलनाबाद से चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने वहां पर संजय दत्त और सुनील शैट्टी को बुलाया हुआ था और भीड़ इक्ट्ठी करने के लिए उनको बस के ऊपर बिठा कर घुमा रहे थे। यहां तक वहां पर लोगों में अफवाह फैली हुई थी कि वहां पर बिपाशा बसु भी आएगी लेकिन वह नहीं आई जिसकी वजह से लोगों को निराशा हुई । उपाध्यक्ष महोदय, आप ही देखिए इनकी कम्पनी कैसी है। इस देश में लोगों का न्यायपालिका पर विश्वास जगाना बहुत ही मुश्किल है। इनके राज में महम हत्याकांड हुआ था, जिस में अमीर सिंह जैसा हत्याकांड हुआ था। इस प्रदेश में किसी ने कानून व्यवस्था को वापस लौटाया है तो वह आदरणीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार है। हमारी सरकार के वक्त में कोई एक भी ऐसा केस बता दें जिसमें किसी गुण्डे की सजा माफ की गई हो। आदरणीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह जी का नारा था कि गुण्डों या तो सरेन्डर

कर दो या हरियाणा को छोड़ कर चले जाओ। उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जनता का सरकार के अन्दर पुन: विश्वास लौटा है और उसी विश्वास का ही यह नतीजा है कि हरियाणा में दोबारा से चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व वाली सरकार आई है। यह अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास चर्चा के लिए और भी कई बातें हैं लेकिन मैं उन बातों को अपने माननीय साथियों के लिए छोड़ता हूं ताकि वे भी महामहिम राज्यपाल महोदय; के अभिभाषण पर बोलते हुए बोल सकें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि हरियाणा में सुव्यवस्थित अच्छी सोच वाली सरकार है, यह एक ऐसी सरकार जिसका विजन है। यह सरकार हरियाणा में ड्वैल्पमैंट को लेकर अच्छी सोच के साथ चल रही है। ये जो विपक्ष के लोग चले गए हैं उनके बारे में कहना चाहूंगा कि :—

रोज तारों की नुमाईश में चलना पड़ता था,
अच्छा हुआ चाँद चला गया ।

उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा हुआ कि वे सदन से चले गए। इस सदन को चलने दो, हमें इस सदन की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, उन्हें गुजरे हुए जमाने की याद आती है और उसी वजह से आज वे तड़प रहे हैं। आज हरियाणा की जनता इस बात को अच्छी तरह से पहचानती है और हमें उनके लिए और भी कुछ करना है। उपाध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा में रेलवे प्रोजैक्ट्स की 6 योजनाएं आई हैं, इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। उसके सर्वे और कम्पलीशन के लिए हम आगे कदम बढ़ाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद अब पहली बार हुआ है कि बजट में इतना एलोकेशन हरियाणा को मिला है। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी धन्यवाद के पात्र हैं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सदन में यह जो महामहिम राज्यपाल महोदय का सम्भाषण हुआ वह गवर्नमैंट की कम्पलीशन स्टेटमैंट है जिसको उन्होंने सदन में पढ़ा है। सदन में सभी सदस्यों को मिलकर उनका धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने अपने सम्बोधन से हमें अनुग्रहित किया है। हरियाणा की सरकार इस सदन के माध्यम से हरियाणा की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहती है कि भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व वाली सरकार उन लोकतांत्रिक मूल्यों का आदर करती है जो श्रीमती सोनिया गांधी जी के दिशा निर्देशन में घोषणा पत्र में हमने दिए थे। जिस प्रकार से पिछली बार पांच साल में घोषणा पत्र से बाहर निकलकर घोषणा पत्र के अलावा जो काम हमने करके दिखाएं तो इन पांच सालों में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम घोषणा पत्र को तो कार्यान्वित करेंगे ही बल्कि उसके अलावा भी एक बार फिर उससे बाहर निकलकर अपने विकास के इतिहास को दोहराकर हरियाणा को नम्बर एक बनाने का जो सपना माननीय मुख्यमंत्री जी का, कांग्रेस पार्टी का है, उसको पूरा करेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।

Mr. Deputy Speaker : Now Shri Dharamvir Singh, MLA will second the motion.

मुख्य संसदीय सचिव (श्री धर्मबीर सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं महामहिम गवर्नर साहब ने जो अभिभाषण 5 मार्च को दिया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । माननीय गवर्नर महोदय का यह जो अभिभाषण है, वह यह दर्शाता है कि हरियाणा की तस्वीर कैसी है और हमारे मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर हम किस प्रकार का हरियाणा बनाना चाहते हैं। ये जो हमारे सामने लोग बैठते हैं वे केवल इसलिए हाउस में उपस्थित

[श्री धर्मबीर सिंह]

नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने अपने जमाने में किस प्रकार से नुकसान किया था। उपाध्यक्ष महोदय, जब यह प्रदेश 1966 में बना तो उस समय हरियाणा की जनता को बहुत सी आशाएं थीं। बीच में इस प्रकार के कुछ लोग इस प्रदेश के अंदर आए जिन्होंने लगातार कई बार राज भी किया लेकिन इस प्रदेश का नाम उनके समय में बड़े शर्म से लिया जाता रहा था। उस समय भ्रष्टाचार के नाम से और गुण्डागर्दी के नाम से हमारे प्रदेश का नाम बदनाम हो चुका था। पांच साल पहले इस प्रदेश की जनता ने एक अच्छे इंसान के तौर पर एक ऐसा मुख्यमंत्री दिया जिसने एक प्रकार से नया हरियाणा देने की कोशिश की और उसी का नतीजा अब आपके सामने है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी पता होगा कि आज से पांच साल पहले इस प्रदेश में गुण्डागर्दी की वजह से हर प्रकार का विकास रूक गया था। उस समय किसान परेशान थे, उद्योगपति परेशान थे और हालत यहां तक पैदा हो चुके थे कि कोई भी उद्योगपति नया उद्योग लगाने की बात तो दूर पुराने उद्योग भी बंद करके दूसरी जगह ले जाने के लिए तैयार हो गए थे। उन हालत का सभी को पता था। चाहे लिबर्टी हो, चाहे पारले जी हो या चाहे एस्कोर्ट हो, सभी के साथ हालात एक जैसे ही थे। उस समय उनकी इंडस्ट्री के सामने सड़कों को खोदकर उनके गेट भी बंद कर दिए जाते थे। टूटे हुए कान वाले जितने भी बदमाश थे वे जेलों से फोन करते थे। उस वक्त जब लोगों को पता लगता था कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री चौटाला आ रहा है तो वे लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर देते थे या फिर छिप जाते थे । उपाध्यक्ष महोदय, इसका ताजा उदाहरण आपने लगभग एक साल पहले भी देखा होगा। लोक सभा चुनाव से पहले उस समय इन भाईयों ने नारनौल की तरफ से अपनी एक पदयात्रा शुरू की थी। उस पदयात्रा में जब इस प्रदेश की जनता ने दोबारा से उन बदमाशों को देखा तो जहां-जहां से वह पदयात्रा गुजरी वहां-वहां पर लोगों को फिर इनके पुराने दिन याद आ गए। लोगों ने सोचा कि कहीं फिर ये लोग सत्ता में न आ जाएं इसलिए उन्होंने पार्लियामैंट की एक भी सीट इनकी पार्टी को नहीं दी। हमारा एक भाई उस समय शहीद हुआ था। इसके बाद फिर जब पार्टी की हार के बाद इन्होंने पार्टी के लोगों के साथ विचार के लिए बैठक की तो सबसे बड़ी बात यही सामने आयी कि जिस बात के लिए ये बदनाम हुए थे कम से कम वह बात लोगों के सामने नहीं आनी चाहिए, उन बातों को दबाकर रखा जाना चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, उसी का नतीजा है कि पांच साल बाद फिर से इस प्रदेश की जनता ने प्रदेश की बागडौर भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के हाथों में दी है। हरियाणा बनने के बाद से लेकर हमारी सरकार के आने से पहले तक प्रदेश में उद्योग के क्षेत्र में 12,500 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था और वह निवेश हुड्डा साहब के आने के बाद 43000 करोड़ रुपये का हो चुका है। उपाध्यक्ष महोदय, एक लाख करोड़ रुपये का निवेश अभी पाइप लाइन में है। सिर्फ हरियाणा का ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का कोई भी उद्योगपति यह चाहता है कि हरियाणा में जमीन का टुकड़ा मिल जाए तो वह यहां उद्योग लगाए। हमारे हरियाणा प्रदेश के जो भी लोग हरियाणा से बाहर रहते हैं वे कोशिश करते हैं, पूछते रहते हैं कि चाहे एच०एस०आई०आई०डी०सी० का या कोई अन्य भी प्लॉट हरियाणा में मिल जाए तो वे यहां उद्योग लगाना चाहते हैं । आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सेफ इलाका कोई है जहां उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है तो वह मात्र हरियाणा प्रदेश है । हर उद्योगपति, एन०आर०आई० की पहली पसंद हरियाणा प्रदेश है। सी०जे०पी० और इंडियन नेशनल लोकदल के साथी बड़ा शोर कर रहे थे वे यहां से जानबूझकर महंगाई के नाम पर सदन से चले गए हैं क्योंकि वे सदन को फेस नहीं कर सकते थे । इस प्रदेश का किसान बड़ा ही मेहनती है, काम करना चाहता है और काम करता है हमारी सरकार के आने के बाद पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार का माहौल

यहां पर पैदा हुआ है उस बारे में उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी पता है तथा जिस प्रकार से हमारे पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर ने बड़े खुले तौर पर यहां बताया कि इस सरकार के आने के बाद एक भी पैसा खाद का नहीं बढ़ाया गया बल्कि किसान की हर फसल का चाहे वह ज्वार हो, गेहूं हो या बाजरा हो, कपास हो का भाव बढ़ाया गया है और साथ ही इनका उत्पादन भी बढ़ाया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि 2004-05 में 90 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 2008-09 में लगभग 15 लाख मीट्रिक टन ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया है। वह भी ऐसे माहौल में जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देश ही नहीं वरन सारा विश्व चिंतित है और इस बार बारिश भी बहुत कम हुई है। एक सवाल का जवाब देते हुए मेरे साथी कैप्टन अजय सिंह यादव जी ने भी बताया कि भाखड़ा में पानी का स्तर 40 फुट नीचे चला गया है। स्वाभाविक है कि नदियों में पानी नहीं होगा तो फसलों के उत्पादन पर प्रभाव तो पड़ेगा । पिछले साल में जहां हम भाखड़ा से 10 हजार क्यूसिक पानी लेते थे उसकी तुलना में आज भाखड़ा से हम 6 हजार क्यूसिक पानी ले रहे हैं इस प्रकार से हम लगभग 4 हजार क्यूसिक पानी कम ले रहे हैं और इससे प्रदेश के किसान की फसल के उत्पादन पर तो प्रभाव पड़ेगा ही। पिछली चौटाला सरकार किसानों की फसल के दाम नहीं बढ़ाती थी क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि हरियाणा प्रदेश का किसान खुशहाल हो। मुझे याद है कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने फैसला किया था कि रावी ब्यास का बढ़ा हुआ पानी हरियाणा प्रदेश को मिले इसलिए 1982 में खुद इंदिरा गांधी ने इसके लिए नीव पत्थर रखा था लेकिन उसके बाद पंजाब में आतंकवाद का माहौल पैदा हो गया था और वहां पर आतंकवाद की जड़ें जम चुकी थी। उसके बाद माननीय स्व० श्री राजीव गांधी जी ने प्रयास करके राजीव लौंगोवाल समझौते के नाम से समझौता किया ताकि रावी-ब्यास का सरप्लस पानी हरियाणा प्रदेश के किसान को मिले लेकिन उसका भी जो विरोध पंजाब के लोगों को करना चाहिए था वह हमारे प्रदेश के नेताओं ने किया। स्व० चौधरी देवी लाल जी ने इसके विरोध के लिए आंदोलन चालू किया। वह आंदोलन बहुत खतरनाक रूप धारण कर चुका था । (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, उस आंदोलन के कारण हमें वह पानी नहीं मिल सका, हालांकि उस वक्त प्रदेश की बागडोर चौधरी बंसी लाल जी के हाथों में थी। उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने 320 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज इस नहर के काम के लिए दिया था। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए ।)**जिस नहर के माध्यम से हरियाणा प्रदेश में पानी आना चाहिए था, उसके लिए स्वर्गीय राजीव गान्धी ने यह सारा पैसा केन्द्रीय सरकार से दिया था। पंजाब में एस०वाई०एल० कैनाल का जो पोरशन बनना था उस वक्त के मुख्यमंत्री ने इलैक्टिड पंचायतों को ले जाकर दिखाया कि नहर का काम शुरू हो गया है अगर इस काम को रूकवा दोगे तो आपको एस०वाई०एल० नहर के मार्फत रावी-ब्यास का पानी नहीं मिल पाएगा । लेकिन यह जन आन्दोलन बन चुका था लोगों को बहकाया जा चुका था। उसके पीछे लोकदल की खासकर एणनीति थी क्योंकि उनको पता था तकरीबन 35 सालों से रावी-ब्यास का सरप्लस 3.83 एम०ए०एफ० पानी जो 4200 क्यूसिक बनता है उसमें से 1800 क्यूसिक पानी पहले से ही भाखड़ा मेन लाईन के माध्यम से कुछेक इलाकों को मिलता था और उनको पता था कि अगर एस०वाई०एल० नहर बन गई तो 1800 क्यूसिक पानी घटकर बाकी पानी प्रदेश के दूसरे हिस्सों में चला जायेगा। इसलिए उन्होंने विरोध किया। जब आज के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को गहराई से देखा कि हमारे उस 4200 क्यूसिक पानी में से 1800 क्यूसिक पानी जो दक्षिणी हरियाणा को मिलना था, एस०वाई०एल० नहर न बनने के कारण वह पानी नहीं मिला। उस समय एक फैसला लिया गया कि प्रदेश की एक-एक इंच जमीन को पानी कैसे दिया जा सकता है। तब हांसी-बुटाना नहर के नाम से एक नई नहर का निर्माण करवाया गया लेकिन यह बात भी इन लोगों को मन्जूर नहीं थी। डायरेक्ट या इनडायेरक्ट रूप से कभी

[श्री धर्मबीर सिंह]

पंजाब सरकार के माध्यम से और कभी पंचायतों के माध्यम से उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कभी हाई कोर्ट और कभी सुप्रीम कोर्ट में जाकर पंजाब सरकार की मदद की। वे नहीं चाहते थे कि पानी का समान बंटवारा हो। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से थोड़ा पानी होने के बावजूद भी हरियाणा के किसानों को फायदा देकर उनका उत्पादन बढ़वाया है। आज किसान को बिजली दी जाती है क्योंकि उसको बिजली की जरूरत होती है। उसके बाद उसको पानी की जरूरत होती है या तो उसे पानी नहर से मिले या बारिश हो या उसको ट्यूबवैल से पानी दिया जाए। हम धन्यवादी हैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के जिन्होंने सबसे पहले 1600 करोड़ रुपये का बोझ किसानों का उतारा है जो सालों-साल से अधूरा पड़ा था। जिसके बारे में विपक्ष के लोग जो आज सदन में नहीं हैं इस बारे में वे आज नहीं सुनना चाहते हैं। मुझे याद है वर्ष 1999 के चुनाव में जब मैं लोकसभा का चुनाव लड रहा था तो उन्होंने एक नारा दिया था कि न रीडर होगा और न ही मीटर होगा। जब लोगों से वोट ले लिए तो अपनी बात से बदल गये। हम धन्यवाद करते हैं माननीय हुड्डा साहब का जिन्होंने आते ही वह 1600 करोड़ रुपये का किसानों का न केवल बोझ उतारा बल्कि एक नयी व्यवस्था की। अध्यक्ष महोदय, आप बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं। हरियाणा बनने के बाद हिन्दुस्तान में हरियाणा ऐसा पहला प्रदेश था जहां गांव-गांव में बिजली दी गई थी। तब से लेकर आज तक वे बिजली की तार और वे खम्भे किसी भी बीच की सरकार ने नहीं बदले । केवल माननीय हुड्डा साहब ने आने के बाद 23000 करोड़ रुपये की लागत से एक नया सिस्टम बनाया। नई जनरेशन के लिए चार पॉवर प्लांट बनाने का काम शुरू किया चाहे यमुनानगर का थर्मल प्लांट हो या खेदड़ का हो, चाहे झाड़ली और खानपुर खुर्द का हो। उनके लिए डिस्ट्रीब्यूशन के इस प्रकार के समझौते किए। गांवों के लिए, शहरों के लिए और एग्रीकल्चर सैक्टर के लिए अलग-अलग फीडर लगाए। केवल यही नहीं इसके साथ जो नये सब-स्टेशन बनाने थे या जहां अपग्रेडेशन करने चाहिए थे वहां अपग्रेड करने का काम जोरों से शुरू है। आज प्रदेश के हालात यह है कि कोई गाँव ऐसा नहीं है जहां पांच साल पहले यह कहते थे कि हमारे तार टूटने जा रहे हैं हमारे पास खम्भा नहीं है वहां पर खम्भे और तारे लगीं हैं। आज खम्भों और ट्रांसफार्मर्ज की बात हम लें तो सांगवान साहब जिस प्रकार से बाजरे की पूल्ली कटी हुई पड़ी होती हैं, उसी प्रकार से हर गांव में बिजली के खम्भों और ट्रांसफार्मर्ज की बौछार लगी हुई हैं। 23000 करोड़ रुपये का सुनिश्चित ढंग से प्रबन्ध केवल माननीय हुड्डा साहब ही कर सकते थे। इस प्रदेश के अन्दर आने वाले समय में बिजली की कोई कमी न रहे यह बीड़ा हमारे मुख्यमंत्री जी ने उठाया है। किसान से बिजली का क्या रेट लिया ? जो रेट एग्रीकल्चर सैक्टर का था, जो यूनिट के ऊपर हमारा खर्च होता था, वही 25 पैसे प्रति यूनिट किसान से आज लिया जाता है, वही रेट चौटाला साहब की सरकार के समय लिया जाता था। यही नहीं आप हैरान होंगे इस बात को लेकर कि होर्टीकल्चर के नाम से चौटाला साहब की सरकार चार रुपये प्रति यूनिट लेती थी, लेकिन माननीय हुड्डा साहब ने उसको घटाकर उसका रेट भी 25 पैसे प्रति यूनिट कर दिया ताकि प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा मिले। न केवल एक सैक्टर में बल्कि हर सैक्टर में किसानों को फायदा दिया है। अगर उसे बाजार से खाद लानी पड़ती है तो उसे पुराने रेट पर ही दी जाती है लेकिन अगर वह बाजार में अपनी फसल को बेचेगा तो उसे बढ़ा हुआ रेट गेहूं का, बाजरे का, कॉटन का हर चीज का दिया जाता है। यहां तक कि बिजली और पानी के रेट वही रखे। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि होर्टीकल्चर के मामले में तो बिजली के रेट 4 रुपये से घटाकर 25 पैसे तक कर दिए। किसान को बचाने के लिए को-ओपरेटिव सैक्टर में बहुत से काम किए गए हैं। पहले एक काला कानून होता था कि अगर कोई लोन 5000 रुपये लेकर

कोई डिफाल्ट कर जाता था या लाई माई स्कीम के माध्यम से कोई गरीब आदमी मकान बनाने के लिए लोन लेता था और वह लोन वापस नहीं कर पाता था तो पिछली सरकार उसको 42 दिन तक जेल में डाल देती थी। अध्यक्ष महोदय, बड़े शर्म की बात थी कि 42 दिन तक का जेल में रोटियों का खर्चा भी उसी डिफाल्टी से लिया जाता था। जीप जिसमें उसको पकड़कर ले जाते थे, उसका आने-जाने का सारा पैसा भी उसी डिफाल्टी को देना पड़ता था। माननीय हुड्डा साहब ने आते ही एक कानून बना दिया कि किसी भी किसान को जेल में नहीं डालने देंगे। सही मायने में यह किसान हितैषी सरकार है। आज दूसरे प्रदेश हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की इस बात का अनुसरण करते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने ऐसे नियम बनाए हैं। आज से 23 साल पहले केवल मात्र 38 करोड़ रुपये के लोन की माफी करके वाह-वाही लूटी थी। हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने एक बार में ही साढे आठ सौ करोड़ रुपये की माफी की है। भारत सरकार ने 70 हजार करोड़ रुपये की माफी की जिसमें से 1300 करोड़ रुपये का हमारे प्रदेश को लाभ मिला। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने ऐसे-ऐसे अनेकों कानून बनाए हैं। अगर कोई जमीन एक्वायर होती है और उसको कोई भी डिपार्टमैंट खरीदता है तो उस जमीन की कीमत के अलावा 10 हजार रुपये प्रतिवर्ष बतौर ठेके के उस जमीन का मुआवजा मिलेगा। यह ऐसा कदम था जिसके बारे में आज तक किसी ने सोचा तक नहीं था। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर सैक्टर में पहले मात्र 31 करोड़ रुपये का बजट था जिसको बढ़ाकर 173 करोड़ रुपये किया गया है । यह किसान को बचाने के लिए ही किया गया है ताकि इस प्रदेश का किसान और आगे बढ़ सके। हर सैक्टर में हमारी सरकार ने जन हित के कार्य किए हैं। अध्यक्ष महोदय, बिजली के क्षेत्र में भी पिछली सरकार की तुलना में हमारी सरकार ने बहुत अधिक कार्य किए हैं । एग्रीकल्चर सैक्टर में पिछली सरकार में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने पूरे 5 सालों में ट्यूबवैल के केवल मात्र 48 हजार नए कनैक्शन दिए थे । हमारी सरकार में माननीय हुड्डा साहब ने यह सोचा कि नहरों में पानी की कमी है और ऊपर से बारिश की भी कमी है इसलिए पौने 5 सालों में तकरीबन 96 हजार एग्रीकल्चर सैक्टर में ट्यूबवैल्ज के नए कनैक्शन दिए गए ताकि किसान अपनी फसल की अच्छी पैदावार प्राप्त कर सके । अध्यक्ष महोदय, हजारों सालों से इस प्रदेश का वही भूगोलिक क्षेत्र है । हमें याद है कि जब कभी बाढ़ आ जाती थी तो केवल मात्र एक 8 नम्बर ड्रेन होती थी और वह भी खासकर सोनीपत, गोहाना, रोहतक होकर दिल्ली और यमुना में पड़ जाती थी । अध्यक्ष महोदय, 1995 में आई बाढ़ के बाद हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी पहले मुख्यमंत्री हैं, जिनकी लम्बी सोच के मुताबिक इस प्रदेश का सर्वे करवाया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं कैप्टन साहब और इनकी पूरी टीम जिसमें चाहे इंजीनियर्ज हों, चाहे अधिकारी हों, को बधाई देता हूं, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके एक ऐसा नक्शा तैयार किया जिसके हिसाब से इस प्रदेश में जो फ्लड के समय पानी आता है वह आधा यमुना में चला जाए और आधा घग्घर में जाकर अबोहर से भी आगे निकल सकता है। अरबों रुपये की लागत से पूरा मुआवजा देकर घग्घर ड्रेन के नाम से एक ड्रेन बनाई गई है जिसमें जींद, भिवानी, हिसार और कैथल तक का एरिया कवर होगा । आज से पहले जब जमीन एक्वायर होती थी तो किसान कहता था कि मेरी जमीन बचाओ लेकिन हम पहली बार देख रहे हैं कि किसान सिफारिश करवाता है कि यह जो नाला निकलना है यह मेरी जमीन में से निकलवाया जाए क्योंकि उसको पूरा मुआवजा भी मिलेगा और साथ में 10 हजार रुपये सालाना बतौर ठेका 500 रुपये की बढ़त के साथ मिलेगा। जमीन जितनी एक्वायर होती है उसमें से आधे से ज्यादा वे यूज भी कर सकते हैं। हम इस प्रदेश को बाढ़ से कैसे बचा सकते हैं, एग्रीकल्चर सैक्टर को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं इस प्रकार की योजनाएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई हैं। इसके अतिरिक्त गांवों को शहरों के बराबर लाने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री

[श्री धर्मबीर सिंह]

जी ने पिछले पांच वर्षों में किया है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा पहला प्रदेश है जहां पर गांवों को नया रूप दिया गया है। हमारे से पहले वाली सरकारों के समय में कानून का उल्लंघन किया जाता था और इलैक्टिड बॉडी को एक तरफ बैठाया जाता था। पिछली सरकार के समय में पंचायतों को एक तरफ कर दिया गया था। उस समय इलैक्टिड बॉडी को एक तरफ करके शहरों में ब्लॉक डिवैल्पमैंट कमेटी बनाई गई और गांवों में विलेज डिवैल्पमैंट कमेटी बनाई गई । जिनका कोई खाता नहीं होता था और न ही किसी प्रकार का आडिट होता था। इन कमेटीज में पिछली सरकार के चहेतों को ही मैंबर बनाया जाता था। इन कमेटीज के पास जो पैसा वे लोग डिवैल्पमैंट के लिए देते थे उनमें से कुछ पैसा मैंबर खा जाते थे और जो बचता था उसकी माला पहना देते थे। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायत मैंबर से लेकर, समिति और जिला परिषदों के मैंबरों के लिए मानदेय 400 रुपये से लेकर 6500 रुपये तक फिक्स कर दिया है ताकि सभी इलैक्टिड मैंबर्ज को काम करने का अवसर मिले और पैसा भी मिले । अध्यक्ष महोदय, यदि पिछली सरकार के समय का बजट देखें तो पता चलता है कि उन्होंने अपने पांच साल के कार्यकाल के दौरान गांवों के विकास के लिए केवल मात्र 1300 करोड़ रुपये खर्च किए थे । यह पैसा भी वे लोग गांवों में दरबार लगाकर देते थे । वह पैसा भी केवल उन्हीं हल्कों में दिया जाता था जहां से उनको वोट मिले होते थे । जहां से उनको वोट नहीं मिलते थे उन हल्कों को उन्होंने डैड डिक्लेयर कर दिया था यानि की उनके लिए वे हल्के मर चुके थे । किलोई आदि हल्के उनके लिए डैड हल्के ही थे । उन्होंने जो वह 1300 करोड़ रुपये गांवों के विकास के लिए दिया वह पैसा भी अपने चहेतों को ही बी०डी०सी० के जरिये दिया । जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने पांच साल के दौरान 3316 करोड़ रुपये गांवों के विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के दिये हैं। पिछले एक साल का हिसाब करें तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछले एक साल के दौरान 1150 करोड़ रुपये से गांवों में विकास के काम करवाये हैं । अध्यक्ष महोदय, कहां पर पांच साल के दौरान 1300 करोड़ रुपये और कहां एक साल के दौरान 1150 करोड़ रुपये इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी गांवों के विकास के लिए कितने सचेत हैं । जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है इससे भी पता चलता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी गांवों के विकास के प्रति कितने सचेत हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रदेश को नया हरियाणा बनाया है। अध्यक्ष महोदय, इस समय विपक्ष के साथी सदन में नहीं हैं। उन्होंने जो कल किया वह जानबूझकर किया था ताकि आप उनको बाहर कर दें। वे लोग डरे हुए हैं क्योंकि वे सदन में होते तो वे असलियत का सामना कैसे करते। वे लोग पैंशन की बात भी करते रहते हैं। यदि आंकड़े देखें तो पता चलता है कि वर्ष 2004-05 के दौरान उनके समय में जो पैंशन बढ़ाई गई थी उस समय 9,94,466 आदमियों को केवल मात्र 259 करोड़ रुपये एक साल में दिए गए थे जबकि अब सालाना बुढ़ापा पैंशन 924 करोड़ रुपये दी जा रही है। यदि टोटल फीगर देखें वैल्फेयर के नाम पर, जिसमें हैंडीकैप्ट भी शामिल हैं, बीने भी शामिल हैं उनको सालाना 382 करोड़ रुपये पैंशन इनके समय में दी जाती थी और अब 1394.98 करोड़ रुपये सालाना पैंशन पर खर्च कर रहे हैं। गांवों के अंदर इसी प्रकार से गरीब और अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं उन सबके ऊपर एक नई लाईन दी है। आज के दिन केवल मात्र खेती करने से किसान का काम नहीं चलता। किसानों के लिए पशुपालन बहुत महत्वपूर्ण है। आम परिवार पशुपालन से अपना गुजारा कर लेते हैं। यदि पिछली सरकार का बजट पशु पालन के लिए देखें जिसमें गऊशालाएं भी शामिल हैं उन्होंने केवल 25000 रुपये दिए थे जबकि हमारी सरकार के समय में 11 करोड़ रुपये एक साल में खर्च किए जा चुके हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी उन्नत नस्ल की मुर्रहा भैंसों के बढ़ावे की तरफ भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। यही

वजह है कि पशु पालन बजट को मुख्यमंत्री जी ने लगभग चार गुणा बढ़ाया है ताकि किसान पशु पालकर अपना गुजारा कर सकें। आज हमारा प्रदेश हर सैक्टर के अंदर पूरे देश में एक नम्बर है। चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे पानी का क्षेत्र हो, चाहे उद्योगों की बात हो, चाहे खेलों की बात हो हर क्षेत्र में हमारा प्रदेश नम्बर एक है। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथी इस समय सदन में नहीं हैं, उनके समय में वे कहते थे कि वे खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं। वे केवल कहते थे और करते कुछ नहीं थे। केवल अपना खेल खेलते थे। हमारी सरकार द्वारा 181 खेल स्टेडियम गांवों में बनाये जा रहे हैं जिनमें से 96 के करीब बन भी गये हैं ताकि गांवों के बच्चों को भी प्रोत्साहन मिल सके और वे खेल में आगे बढ़ सकें। एक-एक स्टेडियम पर 70-70 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं और यदि सामने वाले साथी भी सदन में होते तो उन्हें भी इसका समर्थन करना पड़ता। उन्होंने तो केवल प्रदेश को लूटने का काम किया था, वे इन बातों को नहीं सुनना चाहते थे इसलिए वे शोर करके बाहर चले गये। माननीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास करवाया है और प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया है।

श्री अध्यक्ष : धर्मबीर जी, प्लीज अब आप वाईंड-अप करें ।

श्री धर्मबीर : अध्यक्ष महोदय, मैं अभी वाईंड-अप करता हूं । अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि चाहे कोई पक्ष का सदस्य हो या चाहे कोई विपक्ष का सदस्य हो सभी जनता की भलाई के लिए काम करें। यदि किसी क्षेत्र में कोई समस्या है तो उसके बारे में सदस्य बतायें, उनका समाधान हमारे मुख्यमंत्री जी जरूर करवायेंगे लेकिन वे लोग सदन से बाहर चले गये । अंत में मैं अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद करता हूं और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं । धन्यवाद ।

Mr. Speaker: Motion moved -

That an address be presented to the Governor in the following terms:-

"That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on 5th March, 2010 at 2.00 P.M."

श्री आनंद कौशिक (फरीदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरह से सरकार की सभी तारीफ कर रहे हैं और महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से हमें पता चला है कि क्या-क्या कार्य सरकार करने जा रही है और सभी मदों के लिए बजट में कई-कई गुणा बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है। नहरी पानी के समुचित बटंवारे और ग्राऊंड वाटर टेबल की रिचार्जिंग के लिए हांसी-बुटाना लिंक नहर और दादुपुर-नलवी नहर का निर्माण किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पहली सरकारों के समय में देखते थे कि गांव के लोग मुख्यमंत्री से मिलते थे और दूसरे मंत्रियों से मिलते थे कि हमारी गलियां बनवा दीजिए और हमारी सड़कें बनवा दीजिए। इसके विपरीत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों की समस्याओं को जानने के लिए पूरे प्रदेश का पैदल दौरा किया और पूरे प्रदेश से लोगों की समस्याओं को इक्ट्ठा किया है। अब उन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयासरत हो गये हैं। इस प्रकार से प्रदेश के लोगों को अपनी समस्यायें बताने की भी जरूरत नहीं है। ये जो काम करते हैं और विकास की जो योजनायें बनाते हैं वे पूरे

[श्री आनंद कौशिक]

हरियाणा प्रदेश के लिए होती हैं न कि किसी एक गली या किसी एक सड़क के लिए करते हैं। प्रदेश के लोगों की पीने के पानी की समस्या को भी इन्होंने महसूस किया है। उसी के समाधान के लिए इन्होंने पूरे प्रदेश में विभिन्न नहर परियोजनाओं को लागू किया जिसके तहत मेवात में भी नहर परियोजना लागू की गई और गुड़गांव में भी पीने के पानी के लिए साधन उपलब्ध करवाये हैं। अध्यक्ष महोदय, निःसंदेह इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। इस बारे में हमारे फरीदाबाद के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किये हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि फरीदाबाद क्षेत्र में हरियाणा के लिए जो पानी की नहरें बनाई गई हैं उनमें पानी कहां से आयेगा। इसके अलावा पीने के पानी के लिए रैनीवैल योजना निगम द्वारा भी दबैसिया से सायसा तक 50-52 ट्यूबवैल्ज़ लगाये गये हैं। इन ट्यूबवैल्ज़ का पानी का स्तर बहुत गहरा है जोकि लगभग 90-100 फुट नीचे है। सभी ज़मीदार भी इन्हीं ट्यूबवैल्ज़ से पानी लेते हैं। इस प्रकार से इन ट्यूबवैल्ज़ का वाटर लैवल 180 से 200 फुट नीचे चला जाता है। इसके अलावा किसी ट्यूबवैल की छत गिर जाती है और कभी मोटर खराब हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि यह पीने के पानी की एक टैम्परेरी स्कीम है इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके स्थायी समाधान की प्रार्थना करना चाहता हूं क्योंकि फरीदाबाद में पीने के पानी की बड़ी भारी किल्लत है। पीने के स्वच्छ पानी की उपलब्धि फरीदाबाद के लोगों के प्रति सरकार का बहुत बड़ा उपकार होगा क्योंकि यहां से जो आगरा और गुड़गांव कैनाल्ज गुजरती हैं उनके पानी में बहुत ज्यादा कैमीकल होता है। इसके अलावा इनमें दिल्ली के साथ-साथ दूसरे शहरों की और फैक्ट्रियों की सारी गंदगी भी डाल दी जाती है जिससे उसमें प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है जो किसी भी सूरत में पीने के योग्य नहीं होता। इसके अलावा रैनीवैल योजना निगम द्वारा यमुना के साथ जो ट्यूबवैल्ज़ लगाये गये हैं वे सिर्फ एक-दो महीना यानि केवल बरसात के मौसम में ही ठीक चलते हैं उसके बाद उनमें भी कैमीकल का पानी आ जाता है। अगर कोई पशु भी यमुना से क्रॉस हो जाये तो उसको भी चर्म रोग हो जाता है। इसके लिए कोई ट्रीटमैंट प्लांट भी नहीं लगाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन करना चाहूंगा कि फरीदाबाद की जनता के लिए पीने के पानी के लिए कोई परमानैंट साधन ईजाद करें। फरीदाबाद के लोगों के लिए यह जीवनदान वाली बात होगी। अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले कुछ समय पहले जब मैं फरीदाबाद से अपने कुछ साथियों के साथ ऐलनाबाद में चुनाव प्रचार के लिए गया और जब उन्होंने वहां पर चलने वाली नहरों में साफ नीला पानी देखा तो उन्हें बहुत महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि यहां पर तो पीने के लिए नहरों में साफ पानी चलता है जबकि हमारे यहां तो कैमीकल वाला गंदा पानी मिलता है। अध्यक्ष महोदय, कैमीकल का पानी जिस खेत में डाल दिया जाता है वह खेत भी बंजर हो जाता है। सिंचाई के लिए फरीदाबाद में कोई ऐसा साधन नहीं है। हमारे यहाँ पर दो मंत्री हैं, दो मुख्य संसदीय सचिव हैं और एक विधायक हमारे साथी है, इनसे भी आप जान सकते हैं। इसी प्रकार से मैं चाहूँगा कि नगर निगम के विकास के लिए भी फरीदाबाद में पैसे की बहुत जरूरत है। फरीदाबाद की जो अपनी आमदनी चूंगी और हाउस टैक्स से होती थी वह तो खत्म हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि वह बजट में इस बारे में जरूर प्रावधान करें कि सरकार पैसा बजट के माध्यम से फरीदाबाद के विकास के लिए दें। अध्यक्ष महोदय, मैं जिस इलाके से आया हूँ उस फरीदाबाद को अब ओल्ड फरीदाबाद कहने लगे हैं। उसका नाम

ओल्ड फरीदाबाद नहीं है वह तो सूफी बाबा फरीद की नगरी फरीदाबाद है जिसके नाम से सारा फरीदाबाद बसा हुआ है, इन्डस्ट्रीज बसी हुई हैं, सैक्टर बसे हुए हैं। लेकिन उसको ओल्ड फरीदाबाद इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि उसके अन्दर की हालत बहुत जर्जर हो गई है। मैंने फरीदाबाद की एक-एक गली में जा कर देखा है। जहाँ पर महाराणा प्रताप का बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर कूड़ा कर्कट भरा हुआ है। इसी प्रकार से जहाँ डॉ० भीमराव अम्बेडकर का बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर भी बहुत गंदगी फैली हुई है। वहाँ पर सफाई का कोई साधन नहीं है। तो मैं यह चाहूँगा कि उस बुजुर्ग नगरी फरीदाबाद को जिसको ओल्ड फरीदाबाद कहा जाता है, क्लीन व ग्रीन फरीदाबाद बनाया जाये । हम अपने बुजुर्गों की कद्र करते हैं, सरकार पूरा ध्यान दे ताकि उसकी तरक्की हो सके। अध्यक्ष महोदय, बदरपुर से लेकर फरीदाबाद तक दोनों साईड में ग्रीन बैल्ट बिल्कुल ही नहीं है। उसके दोनों तरफ सौन्दर्यकरण के लिए ग्रीन बैल्ट बनाई जाये। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण के तहत जो कार्य चल रहे हैं उसके माध्यम से भी हम चाहते हैं कि फरीदाबाद चमकेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कमिश्नर वहाँ पर लगाये हैं वे बहुत ही मेहनती और अच्छे अधिकारी हैं लेकिन मेरा अनुरोध है कि फरीदाबाद में सरकार ध्यान दे तभी कुछ तरक्की हो पायेगी ।

श्री अध्यक्ष : कौशिक साहब, आप वाइंड-अप करें ।

श्री आनन्द कौशिक : अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग झुग्गियों में रहते हैं। पिछली सरकार ने उन झुग्गियों को तोड़ने के लिए और गरीबों को उजाड़ने के लिए बहुत कोशिश की थी। उस समय हमारे ऊपर भी 6-7 केस बने थे और कई बार लाठीचार्ज भी हुआ था। जब मुख्यमंत्री महोदय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे तो कहते थे कि इन गरीबों को बचाओ, इसलिए हमने उनको बचाने का प्रयास किया था। आज हम चाहेंगे कि गरीबों को ऊपर उठाया जाये। उनको कोई मकान, कोई छत दी जाये या कोई न कोई फ्लैट गरीबों को अवश्य दिये जाये। मैं मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने वाई०एम०सी०ए० को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है लेकिन उसमें अब तक रजिस्ट्रार नहीं है इसलिए एक रजिस्ट्रार भेजा जाये। इसी प्रकार से वी०सी० भी 10-12 दिन में कभी-कभी चक्कर लगाता है। मैं चाहता हूँ कि सरकार द्वारा फरीदाबाद पर विशेष ध्यान दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री डी०के०बंसल (पंचकूला) : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा पिछले कुछ वर्षों से समावेशी विकास के बड़े बदलाव का साक्षी रहा है। प्रगतिशील माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने आम आदमी को विकास में भागीदार बनाने का नया रास्ता दिखाया है। इन 5 सालों में चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र था, चाहे वह उद्योग का क्षेत्र था या चाहे वह कृषि का क्षेत्र था हरियाणा ने हर क्षेत्र में तरक्की प्राप्त की है। पिछले 5 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी की विवेकशीलता से हरियाणा पूरे भारतवर्ष में नम्बर एक बना है। मैं इसके लिए मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। कृषि की जब बात करते हैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कदम कृषि के लिए उठाये, हमारी कृषि के उत्थान के लिए उठाये और किसानों के लिए उठाये है, आज उसी की वजह से राज्य में 2009 में खरीफ की फसल का 46.53 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है जो 2008 में 44.53 लाख मीट्रिक टन था। इसके साथ जब हम चावल की बात करते हैं तो 13.90 लाख मीट्रिक टन चावल के लक्ष्य की तुलना में राज्य सरकार केन्द्र सरकार के भण्डार में 18.60 लाख मीट्रिक टन चावल दे रही है जोकि 34 प्रतिशत अधिक है । मेरे

[श्री डी०के० बंसल]

कहने का अभिप्राय है कि जितने भी कदम मुख्यमंत्री जी ने उठाए हैं, वे अपने आप में ऐतिहासिक कदम हैं । इन्होंने किसानों को गन्ने की अगेती किस्म के लिए 185 रूपए प्रति क्विंटल, मध्यम किस्म के लिए 180 रुपए प्रति क्विंटल और पछेती किस्म के लिए 175 रूपए प्रति क्विंटल का भाव दिया है। यह पूरे भारत में सर्वाधिक भाव है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों को सबसे ज्यादा गन्ने का भाव देकर उनका मान पूरे हिन्दुस्तान में बढ़ाया है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं सदन में एक बात और कहना चाहूंगा कि पहले एक ऐसा कानून था कि जब हमारे ऋणदाता कोआप्रेटिव सोसाईटी से लिया गया लोन वापस नहीं कर पाते थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने उन सारे काले कानूनों को खत्म करके एक ऐसा कानून बनाया है कि किसान ने जो भी जमीन लोन के बदले में गिरवी रखी होती है उस जमीन को लोन की वसूली के लिए नीलाम नहीं किया जाएगा। बल्कि अब ऐसा किया है कि अगर ऋणदाता लिए हुए लोन को वापस नहीं कर सकेगा तो उसकी जमीन का एक हिस्सा पट्टे पर देने के बाद सरकार उसकी कमाई से अपना कर्ज वसूलेगी और बाकी का हिस्सा उसके खर्चे-गुजारे के लिए दिया जाएगा। मैं इस बात के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं । अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ हमारी सरकार ने जो ग्रामीण दस्तकार, छोटे दुकानदार थे उनके लिए अधिकतम ऋण सीमा को 25 हजार रुपए से बढ़ाकर 35 हजार रुपए कर दिया है। यह बात इस बात को स्पष्ट करती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिल में जो छोटे ऋणदाता हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके प्रति बहुत गहरा स्थान है। अध्यक्ष महोदय, आज जब हम गांवों के विकास की बात करते हैं तो इस सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना के तहत परिवारों को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया है। यह भी सरकार का बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है । अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत बी०पी०एल० परिवारों, पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के लोगों को 100-100 गज़ के प्लाट दिए हैं और ये प्लाट लगभग तीन लाख लोगों में बांटे जा चुके हैं । इस सरकार का यह भी एक ऐतिहासिक कदम है, इससे हमारे पूरे हरियाणा के कमजोर वर्ग के लोगों को, पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति के लोगों को बहुत लाभ पहुंचा है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं । अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ इन्दिरा गांधी आवास योजना के तहत जो योजना बनाई गई है उसमें बी०पी०एल० परिवारों को आवास इकाई के लिए करीब 35 हजार रूपए का सहयोग दिया गया है उससे बहुत ज्यादा लाभ हमारे कमजोर वर्ग के लोगों को पहुंचा है। अध्यक्ष महोदय, चालू वर्ष में 90 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता से 26 हजार मकान बनाए जा रहे हैं इसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाए हैं । अध्यक्ष महोदय, हमारे कमजोर वर्ग के परिवारों के जो बच्चे हैं उनके सपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने साकार किए हैं, करीब 18 लाख विद्यार्थियों को सहयोग दिया गया है। उनको 75 रूपए से लेकर 400 रुपए तक का मासिक वजीफा दिया है। हमारे उन विद्यार्थियों की जो सोच थी कि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, वह सोच पूरी हो रही है। इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गांधी पेय जल योजना के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कदम उठाए हैं उसके तहत 8 लाख परिवारों को पानी का मुफ्त कनैक्शन और एक पानी की टंकी दी है। यह भी हमारी सरकार ने कमजोर वर्ग के लोगों को बहुत बड़ा लाभ दिया है। अध्यक्ष महोदय, जितने भी कदम हमारे मुख्यमंत्री जी ने उठाए हैं उसमें उनकी एक सोच है कि पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में और हमारे राज्य में हमारा कमजोर वर्ग दूसरे वर्गों

के बराबर आए। मुख्यमंत्री जी की सोच है कि कमजोर वर्गों में और दूसरे वर्गों में आपस में समानता आए ताकि वे मिलकर हरियाणा और देश के लिए विकास के कार्य कर सकें। इसी तरह से चिकित्सा में निःशुल्क दवाईयां, सर्जरी पैकेज और एम्बुलैंस की सर्विस की सुविधा जो मुख्यमंत्री जी ने प्रदान करवाई है वह अपने आप में एक बहुत सराहनीय कदम है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ जो हमारे बुजुर्गों की पैंशन 300 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रति मास की है और जिस बुजुर्ग को पैंशन लेते हुए लगातार 10 साल हो गए हों तो उनकी पैंशन 700 रुपए प्रति मास की है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही हमारी विधवा बहनों की पैंशन को 350 रुपए से बढ़ाकर 750 रुपए प्रतिमास किया है। अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति के जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए वजीफे की राशि को 4000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए किया है। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने इन्डस्ट्रीज को हरियाणा में बहुत ज्यादा अपग्रेड किया है। जो हमारी टैक्नीकल आई०टी० की इंडस्ट्रीज है उन्होंने काफी तरक्की की है। इस साल करीब 21 हजार करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट हम उनके माध्यम से कर सके हैं। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, पंचकुला के अंदर बहुत सुविधाएं दी गयी हैं इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। अभी भी बहुत सी समस्याएं पंचकुला में पिछली सरकार के समय से हैं। वहां पर रैजीडैंशियल फ्लैट्स के लिए इंदिरा कालोनी, राजीव कालोनी और आजाद कालोनी के लोगों ने एप्लाई किया था। हुडा ने इसके लिए उनसे दस-दस हजार रुपये लिए थे परन्तु अब तक भी उनको न तो फ्लैट और न ही प्लाट अलॉट किए गए हैं । इस तरह के हजारों के हिसाब से लोग हैं। पंचकुला में 2100 फ्लैट्स तैयार हैं लेकिन अभी तक इनका कब्जा लोगों को नहीं दिया गया है। मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना है कि ये 2100 फ्लैट्स हमारी कालोनीज के उन लोगों को इंस्टालमैंटस पर दिए जाएं जिनसे हुडा ने पैसे ले रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा वहां पर सात हजार लोग ऐसे हैं जिनको फ्लैट्स चाहिएं। पंचकुला में जगह भी है इसलिए मेरा अनुरोध है कि जगह ईयरमार्क करके सात हजार लोगों के लिए फ्लैट्स बनाए जाएं। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पंचकुला जो एक नैशनल सिटी है वहां पर हालांकि काफी सुविधाएं हैं लेकिन अभी भी कई और सुविधाएं वहां पर नहीं हैं। जैसे वहां पर कोई मैडीकल इंस्टीच्यूट नहीं है, मैडीकल हब नहीं है जिसकी वजह से वहां के आम लोगों को मैडीकल फैसेलिटीज के लिए दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है। पंचकुला एक बहुत सुंदर शहर है लेकिन इसमें एजुकेशन हब भी नहीं बन सका है। मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना है कि पंचकुला के अंदर अपोलो, फोर्टिस या पी०जी०आई० जैसा कोई मैडीकल इंस्टीच्यूट बनाया जाए ताकि पंचकुला के लोगों को मैडीकल ऐड के लिए, मैडीकल फैसेलिटीज के लिए दूसरी जगहों पर न जाना पड़े और वहीं पर उनको सारी सहूलियतें मिल जाएं। इसके अलावा पंचकुला में कोई बड़ी इंडस्ट्री या एजुकेशन हब भी बनाया जाए ताकि यहां के विद्यार्थियों को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। वहीं पर उनको पढ़ाई की सुविधाएं मिल जाएं। अध्यक्ष महोदय, चण्डीगढ़ के एजूकेशनल इंस्टीच्यूट में हरियाणा के विद्यार्थियों को 15 परसैंट रिजर्वेशन मिलनी चाहिए क्योंकि पंचकुला चण्डीगढ़ के साथ ही जुड़ा हुआ है। इसी तरह से हुडा ने जो फ्री ट्रेड जोन पोलिसी हरियाणा में पानीपत, सोनीपत और यमुनानगर में लागू की है उसको पंचकुला में भी लागू किया जाये, ताकि यहां पर भी आबादी के अंदर शॉपिंग कम्पलैक्स बन सकें। पानीपत या सोनीपत में यह लागू करने से वहां पर लोगों को इसका काफी फायदा मिला है। अध्यक्ष महोदय, हुडा ने कुछ साल पहले इम्प्लीमैंटेशन ऑफ सैल्फ सर्टिफिकेशन पोलिसी की घोषणा की थी जिसमें चेंज ऑफ प्रोजैक्ट के बारे में उन्होंने कहा था। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि उस पोलिसी को पंचकुला में भी लागू किया जाए। इसके अलावा पंचकुला में इंडस्ट्रियल वेयर हाउसिंग/गोडाउन एवं ट्रांसपोर्ट फैसेलिटी की परमिशन भी दी जाए।

[श्री डी०के० बंसल]

श्री अध्यक्ष : ठीक है बंसल साहब, अब आप बैठें । अब आफ़ताब अहमद बोलेंगे ।

चौधरी आफताब अहमद (नूंह) : अध्यक्ष महोदय, आपने राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए मुझे जो समय दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी सरकार और विशेष तौर पर अपने मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि पिछले पांच वर्षों में बहुत ज्यादा तरक्की हरियाणा प्रदेश ने ओवरआल डिवैल्पमैंट में की है। पूरे हिन्दुस्तान में हरियाणा के नम्बर वन बनने पर हम गर्व महसूस करते हैं। जब हम अपने आपको हरियाणवी कहते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो हरित क्रांति की शुरूआत की थी उसका सबसे ज्यादा असर हरियाणा के भू-भाग में ही हुआ। हरियाणा ने कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा तरक्की की। किसान की वजह से हरियाणा ने पूरे देश का पेट भरने का काम किया है और पूरे प्रदेश में आर्थिक समृद्धि आयी है। पिछले पांच सालों में हमारी सरकार ने कार्य करके किसानों को जो रियायतें दी हैं, जो उनको सहूलियतें दी हैं वह काबिले तारीफ हैं। पिछली सरकारों के समय में किसानों का खेती के प्रति मोह भंग हो रहा था। अब उस खेती में फिर से उनका मोह होने लगा, जिस खेती को किसान घाटे का सौदा मान रहा था, उसमें वह फिर से दिलचस्पी लेकर जमींदारी करने लगा है। इसका क्या कारण है ? इसका कारण यह है कि चाहे ऋण की दरें घटाने की बात हो, चाहे पानी के न्यायोचित बंटवारे की बात हो, चाहे अन्य जितनी भी सुविधायें हैं वह इस सरकार के द्वारा उनको दी गईं। सबसे बड़ी समस्या किसान के समक्ष यह थी कि जब वह अपनी फसल को मंडी में बेचने जाता था तो उसे अपनी फसल के कम दाम मिलते थे। पिछले पांच सालों में इस सरकार ने किसान की फसल के रेट सबसे ज्यादा बढ़ाये, उनका फायदा किसान को मिला है। इसके लिए आदरणीय चौ० भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार बधाई की पात्र है। सिंचाई के क्षेत्र में भी पानी का समुचित और समान बंटवारा किया गया उससे भी हरेक इलाके में तरक्की हुई है। इसी के साथ-साथ हमारे अपने जिले में जिस तरह से इस सरकार ने सिंचाई की परियोजनायें चालू करने का प्रयास किया है उसके परिणाम अब आने शुरु हो गए हैं। आज भी इस अगस्त हाउस में बयान मेवात कैनाल और गुड़गांव कैनाल के बारे में दिया गया है इससे मुझे बहुत खुशी है और इस मौके पर मैं इससे आगे जाकर मांग और अनुरोध करता हूं कि जो प्रयास किए गए हैं उनको पूरी तरह से कार्यान्वित भी किया जाए। बिजली के क्षेत्र में भी हमारे उत्पादन के क्षेत्र में इस सरकार ने जो काम पिछले पांच साल में किया है वह अपने आप में रिकार्ड है। हरियाणा प्रदेश को बने हुए 42-43 साल हुए हैं इस अवधि में उत्पादन के बारे में सरकार ने जो अपनी वचनबद्धता पिछले पांच साल में दिखाई है और इन्होंने जो इन्वैस्टमैंट की है वह भी अपने आप में एक रिकार्ड है। यह रिकार्ड यह भी दर्शाता है कि प्रदेश में सरकार ने किसानों और उपभोक्ताओं की बिजली की जरूरतों की पूर्ति के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं उसके लिए हमें फख्र महसूस होता है। आज ऐग्रीगेशन और तार बदलने का इतना कार्य किया गया है कि इससे पहले इतना कार्य कभी नहीं हुआ था। हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हरियाणा में बिजली का उत्पादन और उसके उपयोग का हिसाब पूरा होगा तो उससे बहुत फायदा मिलेगा। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अंतिम छोर तक गरीब हरिजन भाइयों के हित की बात जो अब सोची गई है वह इससे पहले नहीं सोची गई, चाहे उसमें पीने के पानी की व्यवस्था की बात हो, चाहे गली निर्माण की बात हो, खेल स्टेडियम की बात हो या सैनीटेशन की बात हो वह प्रयास भी अब सामने आने लगे हैं। अब ग्रामीण क्षेत्र में भी किया गया विकास सामने दिखने लगा है। शिक्षा के बारे में

एक सवाल के जवाब में आज इस अगस्त हाउस में बताया गया उसमें हमारे मेवात क्षेत्र के लिए शिक्षा के प्रति मुख्यमंत्री जी ने उदारता दिखाते हुए हमारे इलाके के लिए अलग से कॉडर बनाने की जो बात की है वह सराहनीय कदम है। अकेले स्कूल अपग्रेड करने से कुछ नहीं होता, यदि उन स्कूलों में अध्यापक न हों तो उद्देश्य की प्राप्ति संभव नहीं है। अलग कॉडर बनाने के लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का तहेदिल से आभारी हूं। शिक्षा के मामले में जैसे हमारे क्षेत्र में मैडीकल कालेज इस सरकार के प्रयासों से बना, इंजीनियरिंग कालेज शुरु हुआ, सबसे बड़ी आई०टी०आई० बॉयज एंड गर्ल्ज के लिए हमारे जिले में बनने जा रही है। यह जो काम हुए हैं यह ऐतिहासिक हैं और आने वाले समय में भी इसी तर्ज पर चलते हुए शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किए जाएंगे। हमारे यहां शिक्षा के क्षेत्र में कमजोरी है। अगर हरियाणा की 5वीं,7वीं और 8 वीं योजना में देखा जाए तो जो ड्रॉपआउट है it is highest in Mewat District. उसको रोकने के लिए जितने कदम हम सरकार के माध्यम से उठा सकें, उतना अच्छा है क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम विकास कर सकते हैं। मेरे क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य के मामले में भी सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं। अस्पताल और बिल्डिंग्ज तो हमारे यहां पहले से ही बनी हुई थी लेकिन स्टाफ वहां नहीं था जिसकी वजह से आम आदमी वहां जाने का इच्छुक नहीं होता था, वहां पर सुविधायें नहीं होने के वजह से उनका मन अस्पतालों से विमुख होता जा रहा था लेकिन इसके लिए अब जो प्रयास किये गये हैं वे सराहनीय है और मैं आगे भी उम्मीद करूंगा कि वहां मशीनरी, इक्विपमैंट्स आदि की कमी को जल्दी से जल्दी पूरा करके हमारी सरकार स्वास्थ्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहरायेगी। इसके साथ-साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आजकल बारिश नहीं हो रही है जिस 13-00 बजे कारण पानी की कमी होती जा रही है। इसके साथ ही मैं यह मांग करूंगा कि अरावली की श्रृंखला में खनन भारी मात्रा में मौजूद है। खनन पहले भी होता था लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से उसको बन्द कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से यही मांग करूंगा कि जैसा कि हमारे फरीदाबाद में 600 हैक्टेयर भूमि में खनन खोलने का फैसला लिया गया है उसी तरीके से हमारे जिले में भी खनन के लिए इजाजत दी जाए जिससे लाखों परिवार उस खनन के माध्यम से अपना पेट भर सकें और रोजगार वहीं के वहीं उनको उपबल्ध हो सकें. हमारी जमीन में खारा पानी है। खनन की वजह से हमारे जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलने का एक उचित माध्यम बन जाएगा। इसके साथ-साथ हमारे मेवात जिले में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने बी०पी०एल० परिवारों के लिए बहुत अच्छी-अच्छी स्कीमें चला रखी हैं। इस बात को कहते हुए मुझे बड़ा खेद होता है कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का मेवात जिले में बुरा हाल है वहां पर बी.पी.एल. के परिवारों के जो अधिकार हैं उनके साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। बी०पी०एल० परिवार के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए वह उनको न मिलकर, कुछ निजी स्वार्थी आफिसर्ज की मिलीभगत से कुछ दूसरे लोगों को दिये जाने का खेल खेला जा रहा है। इन चीजों को मध्य नजर रखते हुए स्मार्ट कार्ड को चलाकर इसको ठीक किया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करते हुए मैं यही कहूंगा हमारी सरकार की विकास और उन्नति के द्वारा हरियाणा को नम्बर 1 बनाने की जो प्रतिबद्धता है हमें लगता नहीं कि उसमें कोई कसर रही है। जो कमियां रहेंगी और उनको पूरा करने की जो कोशिशें आगे होंगी उसमें लोक भलाई के लिए, हमारे किसान को गरीबों और हरिजनों को विकास करने के लिए तरक्की करने का पूरा मौका मिलेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री राजपाल भूखड़ी (सढौरा, एस०सी०): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो बताया गया है और हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो डाक्टर अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना स्नातकोत्तर स्तर पर लागू की है उस योजना से हमारे गरीब परिवार के बच्चों को 4000 रुपये से लेकर 12000 रुपये तक छात्रवृत्ति दी जा रही है, उसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सराहना करता हूं। यह हमारी सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है और इससे गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ने का अवसर मिलेगा। दूसरी बात हमारे जो अनुसूचित जाति के बच्चे विज्ञान, व्यावसायिक और टैक्नीकल ऐजूकेशन पाठयक्रमों में पढ़ने के लिए जाते हैं उनको आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 5000 रुपये से लेकर 14000 रुपये तक की वार्षिक छात्रवृत्ति दी है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने पिछले पांच वर्षों में जो हरिजन लोगों के लिए, गरीब लोगों को उनके रहने के लिए जो आवासीय असुविधा थी, उसको दूर करने के लिए जो प्लाट्स के लिए योजना बनाई है मैं इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सराहना करता हूं और धन्यवाद करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार द्वारा जो भी गॉव हमारे इलाके के इससे वंचित रह गये हैं, जिनमें प्लाट आबंटित नहीं किये गये हैं, उनमें भी जल्दी से जल्दी इन प्लाटों का आबंटन किया जायेगा। दूसरी बात, जो गरीब लोग हैं उनके जो कर्जों की बात है हमारी सरकार ने आदरणीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में उनको माफ करने की जो घोषणा की है, मैं उम्मीद करता हूं कि उसको जल्दी से जल्दी इम्पलीमैंट किया जायेगा। अब मैं कृषि क्षेत्र की बात करना चाहता हूं । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारा यमुनानगर का क्षेत्र है इसमें ज्यादातर गन्ने की खेती होती है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के शासनकाल में जब हमारे यहां के लोग गन्ने की बिजाई करते थे और गन्ना मिल में डालते थे तो उनको पेमैंट समय पर नहीं मिलती थी। अब हमारे यहां के किसान जब गन्ना मिल में डालते हैं तो उनको समय पर और सही रेट पर भुगतान किया जाता है। मैं समझता हूं कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने यह बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में हरसौला और दुलीना जैसे कांड हुए और गरीब लोगों को जिंदा जला दिया गया। हमारी सरकार में पिछले 5 वर्षों से राज्य में शांति स्थापित हो गई है। इसके लिए मैं इस सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सराहना करता हूं। हमारी सरकार में गरीब कन्याओं की शादी के लिए इंदिरा गांधी विवाह शगुन योजना के तहत पहले 5000 रुपये मिलते थे, उसको बढ़ाकर 11 हजार रुपये किया गया और फिर 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये और 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 31 हजार रुपये किया गया है। इस स्कीम से गरीब लोगों को अपनी बेटियों की शादी करने में काफी सहायता मिलेगी इसके लिए भी मैं हरियाणा सरकार की सराहना करता हूं। परिवहन के क्षेत्र में हमारी सरकार की काफी योजनाएं चल रही हैं और हमारी सरकार ने काफी अच्छे काम किए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो हमारा बिलासपुर कस्बा है उसमें बस स्टैंड बनाया जाए ताकि हमारे यहां के लोगों को फायदा हो । अध्यक्ष महोदय, हमारे सढौरा क्षेत्र में एक आई०टी०आई० बनी हुई है लेकिन उसमें कुछ ही ट्रेड्स चल रही हैं इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि जितनी टोटल ट्रेड्स होती हैं वे सारी ट्रेड्स उस आई०टी०आई० में चालू करवाई जाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रार्थना यह भी करना चाहता हूं कि हमारे सढौरा क्षेत्र में कोई टैक्नीकल कालेज खोला जाए जिससे गरीब बच्चों को पढ़ने का अवसर मिल

सके और वे टैक्नीकल एजूकेशन प्राप्त करके नौकरी प्राप्त कर सकें। अध्यक्ष महोदय, हमारा जो यमुनानगर का क्षेत्र है उसमें सड़कों के लिए हमारी सरकार ने बहुत पैसा खर्च किया है लेकिन फिर भी हमारे जिले में सड़कों की काफी दिक्कते हैं। हमारे यहां से जो ओवर लोडिड ट्रक निकलते हैं वे नैशनल हाइवे से निकलने की बजाय जो गांव के हमारे लिंक रोड्स हैं, वहां से निकलते हैं जिस कारण हमारे यहां की कोई सड़क 6 महीने में टूट जाती है और कोई एक साल में टूट जाती है। सरकार का इन सड़कों पर लगा पैसा वेस्ट हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां सरकार सडकों पर और भी बहुत पैसा खर्च कर रही है इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि हमारे यहां की रोड्स पर जो ओवर लोडिड ट्रक निकलते हैं उनको बन्द करवाया जाए, उन पर चौकियां लगाई जाएं और इन हैवी लोडिड ट्रकों को नैशनल हाइवे से निकाला जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वे भारत सरकार से सिफारिश करें कि यमुनानगर एक्सप्रैस को दिल्ली तक बनाया जाए और टोल रोड बनाया जाए ताकि यमुनानगर की सड़कें टूटने से बच सकें और सरकार को बार बार उन रोड्स पर पैसा खर्च न करना पड़े। टोल रोड बनने से यह फायदा होगा कि जो वाहन वहां से गुजरेंगे वे उस रोड़ के बनने का खर्चा वहन करेंगें। अध्यक्ष महोदय, मुझ से पहले यहां 32 सालों तक दूसरी पार्टियों के विधायक चुनकर आए हैं, मैं 32 साल के बाद यहां से चुनकर आया हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि यदि विपक्ष के साथी यहां सदन में उपस्थित होते तो मैं उनके मुखिया से एक बात पूछता कि पिछले दस वर्षों में या उससे पहले जो नुमाइंदे सढौरा से चुनकर आये उन्होंने हमारे क्षेत्र के विकास के लिए कभी सदन में बात क्यों नहीं उठाई ? पिछले पांच साल से हमारी सरकार है उस समय भी हमारे वहां से जो सदस्य चुनकर आया, उसने स्पीकर महोदय के माध्यम से सदन में हमारे हल्के के विकास के बारे में कोई बात नहीं उठाई। मैं मानता हूं कि यदि पिछले पांच साल के दौरान हमारे हल्के की नुमाइंदगी करने वाला सदस्य यहां पर अपनी समस्याएं उठाता तो मुख्यमंत्री जी उनका निवारण अवश्य करते। अध्यक्ष महोदय, हमारा घाड़ का क्षेत्र है जहां पर बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं यदि उनको सदन में उठाया जाता तो मुख्यमंत्री जी उनको अवश्य दूर करते। विपक्ष के साथी आज यहां से उठकर चले गये हैं मैं उनके मुखिया के सामने यह बात कहना चाहता था वे लोग तो केवल प्रोपर्टी डीलिंग करते रहे, केवल अपने घर भरते रहे और जनता की समस्याओं की तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी के समक्ष एक बात रखना चाहता हूं कि हमारा जो घाड़ का क्षेत्र है उसके लिए एक समिति का गठन किया जाये । उस समिति को घाड़ के क्षेत्र में भेजा जाये और वहां पर लोगों की जो दुर्दशा है उसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाये। इसके साथ-साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह भी अनुरोध करूंगा कि पिछले 32 सालों से सढौरा क्षेत्र का विकास रूका हुआ है, आज 32 साल बाद वहां से जनता की आवाज कांग्रेस की आवाज बनकर सदन में बोल रही है। इसलिए जो हमारे क्षेत्र का 32 साल का काला अध्याय था, उसको समाप्त करके एक नया रोशनी का अध्याय जोड़ा जाये। काला अध्याय समाप्त होकर, अब प्रकाश का अध्याय मेरे क्षेत्र में भी शुरू होना चाहिए ताकि वहां के लोगों में भी ऐसा विश्वास पैदा हो कि जहां पूरे देश में हमारा हरियाणा एक नम्बर पर है, वहां उनके क्षेत्र का भी विकास हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले पांच वर्षों में जो डिवैल्पमैंट के कार्य किए हैं उनमें हमारे एरिया में भी डिवैल्पमैंट कार्य हुए हैं लेकिन मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र की तरफ विशेष ध्यान दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं बजट का समर्थन करते हुए तथा आपका भी धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री सतपाल सांगवान (दादरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि मैं हरियाणा जनहित कांग्रेस से विधायक बनकर आया था परंतु पिछले पांच साल से चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने हरियाणा में जो कार्य किए हैं वे देखने लायक हैं और विशेषकर हमारे एरिया में भी बहुत विकास कार्य करवाये हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारा एरिया किसान का एरिया है और वहां पर रेतीली जमीन है। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने जब सबसे पहले 1600 करोड़ रुपये के किसानों के बिजली के बिल माफ किए तो हमारे एरिया में पहली दफा सही मायने में दीवाली उस समय मनी थी और उससे मैं भी बहुत ज्यादा इम्प्रैस हुआ था। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपनी लाईफ में भला करने की बजाय हमेशा रिवेंजफुल एटीच्यूड रखा है। अगर चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की तरह रिवेंजफुल एटीच्यूड के होते तो ये भाई आज विपक्ष में बैठने की बजाय जेल में बैठे होते। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने रिवेंजफुल एटीच्यूड रखते हुए बिना किसी बात के हमारे ऊपर धारा 302 और 307 के केस रजिस्टर करवाये। अब जब मैं फिर विधायक बना तो मुझे कहते हैं कि अरे सतपाल मेरी तरफ आ जा दोनों मिलकर हरियाणा में धुआंधार मचा देंगे । हरियाणा का तो मुझे पता नहीं लेकिन वे मेरा धुआंधार जरूर मचा देते। अध्यक्ष महोदय, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी का भार और परेशानी कम करने के लिए हमने 23 तारीख को ही फैसला कर लिया था कि हम कांग्रेस की मदद करेंगे ताकि स्थिर सरकार बन जाये । अध्यक्ष महोदय, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के बर्ताव के कारण हमने पहले ही कह दिया था कि सर, हम आपके साथ होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। यही वजह है कि हमने हमारी सारी की सारी हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी को उठाकर कांग्रेस में सम्मलित कर दिया और 6 में से 5 विधायक चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के साथ आ गये । स्पीकर सर, हमें इस बात का गर्व है और यह कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि हमने हरियाणा की चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को स्थिरता प्रदान करने के लिए अपनी हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी को इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी में मर्ज किया। यह फैसला हमने इस बात को ध्यान में रखकर लिया ताकि माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा आराम से अपनी सरकार चलायें और प्रदेश के हित में निर्बाध रूप से काम कर सकें और उन्हें सरकार की स्थिरता के बारे में सोचने की जरूरत न पड़े। स्पीकर सर, हमारे एरिया में सबसे बड़ी डिवैल्पमैंट जो हुई है उस का हमारे भाई धर्मबीर सिंह जी ने भी जिक्र किया है। स्पीकर सर, रोहतक इलाके वाले हमारे इलाके के निवासियों को बागड़ी कहकर बुलाते हैं क्योंकि हमारे यहां बाजरा बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा होता है। मैं धन्यवाद करता हूं इस सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने बाजरे का भाव भी बढ़ाकर गेहूं से थोड़ा सा नीचे करके 850 रुपये प्रति क्विंटल फिक्स कर दिया। इस सरकार के समय में हमारे इलाके के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस सरकार के समय में हमें बाजरे का जितना मूल्य मिला उतना पहले किसी सरकार के शासनकाल में नहीं मिला। स्पीकर सर, दूसरी बात इस सरकार ने किसानों के लिए यह की कि पहले किसान अपना ट्रैक्टर खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया करते थे जिसके लिए उसे अपनी 4 एकड़, 6 एकड़ और कभी-कभी 8 एकड़ तक जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी और जब वे किसी कारण से अपने लोन की किस्त की अदायगी न कर पाते थे तो आगे-आगे किसान हुआ करते थे और पीछे-पीछे पुलिस हुआ करती थी, यह देखने वाला सीन होता था और जिसके कारण कई किसानों द्वारा आत्महत्या जैसा कठोर कदम भी उठा लिया गया था लेकिन चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने सबसे पहले एक एकड़ जमीन पर किसान को ट्रैक्टर का लोन देना सुनिश्चित करवाया और उसमें यह कंडीशन भी लगाई गई कि ऋण का भुगतान न कर पाने

की सूरत में किसान को पुलिस द्वारा अरैस्ट नहीं किया जायेगा। यह भी इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसान को अपनी एक एकड़ जमीन गिरवी रखकर ट्रैक्टर का लोन मिलता है। स्पीकर सर, दूसरा सबसे बड़ा काम इस सरकार द्वारा यह किया गया कि तत्काल स्कीम के तहत पूरे हरियाणा प्रदेश में ट्यूबवैल्ज़ के 70259 बिजली के कनैक्शन वितरित किए गए। यह इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि अभी हमारे इलाके में फसल की पकाई का समय है इसलिए हमारे इलाके को थोड़ा ज्यादा पानी उपलब्ध करवाया जाये ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। स्पीकर सर, कुछेक जगह हमारा इलाका पिछड़ा हुआ है। मेरे हल्के के बौंद और इमलोटा गांवों में बरसात के मौसम का जमा पानी अभी तक भी नहीं निकाला गया है जिस कारण उन की चार-चार फसलें खराब हो गई हैं। सरकार द्वारा अभी तक भी मेरे इलाके के इन दो गांवों के किसानों को मुआवज़े के तौर पर एक नया पैसा भी नहीं दिया गया है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस ओर अवश्य ध्यान दें। स्पीकर सर, मैं ज्यादा न बोलते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे इलाके के लोगों ने हमें कम्पैल किया कि जाओ और चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को समर्थन दो। अपने-अपने हल्के की जनता की बात को शिरोधार्य रखते हुए हम हरियाणा जनहित कांग्रेस के पांच विधायक भाईयों ने हरियाणा जनहित कांग्रेस का कांग्रेस पार्टी में विलय कर लिया था। स्पीकर सर, जब हमने यह फैसला किया तो उस दिन हमारे इलाके में दीवाली जैसा जश्न मनाया गया था। स्पीकर सर, यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर किसी को मेरी इस बात में सच्चाई नज़र न आ रही हो और किसी प्रकार का कोई शक हो तो वह मेरे हल्के के लोगों से इस बारे में पूछ सकता है। स्पीकर सर, इसके साथ ही मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया।

श्री अनिल धनौड़ी (शाहबाद, एस०सी०) : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा में पिछले 5 वर्षों से कांग्रेस की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की अगुवाई में विकास के जो कार्य किये हैं उनको देखते हुए अगर उनको विकास पुरूष की उपाधि दी जाये तो गलत न होगा । पूरे हरियाणा में विकास और सिर्फ विकास हुआ है। मैं समझता हूँ कि पूरे के पूरे हरियाणा में पूरे क्षेत्रों में बराबर-बराबर विकास हुआ है। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ । हरियाणा के अन्दर विकास की जो आँधी लेकर चले थे, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच थी कि पूरे के पूरे हरियाणा को किस तरह से एक नया रूप दिया जाये, मैं समझता हूँ कि काफी हद तक माननीय मुख्यमंत्री जी और हरियाणा सरकार उसमें कामयाब हुई है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा के युवाओं के प्रतिनिधि के रूप में सबसे पहले युवाओं की बात रखना चाहता हूँ। वर्तमान सरकार ने युवाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। ऐजूकेशन के क्षेत्र में चाहे वह बी.एड कॉलेज हो, चाहे वह इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वह बहुतकनीकी विद्यालय या आई.टी.आई.हो या सरकारी स्कूल हो, मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी की जो सोच थी कि हरियाणा को ऐजूकेशन हब बनाया जाये तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उसके लिए भी बधाई देना चाहूँगा कि वह एक अच्छी सोच है तथा इनका यह अच्छा निर्णय है। युवाओं की आवाज उठाते हुए मेरा इस बारे में एक सुझाव है कि लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप यूनिवर्सिटीज एवं कॉलेजों में छात्र संघ के चुनाव करवाये जायें ताकि युवा

[श्री अनिल धन्तौड़ी]

राजनीति में नई शिक्षित लीडरशिप उभरकर सामने आये। मेरा यह मानना है कि अगर यूनिवर्सिटीज में टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ के चुनाव होते हैं तो छात्र संघ के क्यों नहीं ? यह धारणा निराधार है कि इससे झगड़े बढ़ेंगे एवं शिक्षा के स्तर में गिरावट आयेगी। ये आँकड़ों की बात है कि डी.यू. और पी.यू. जहाँ पर चुनाव होते हैं, उनका इनवायरमैंट भी हमारे जैसा है। उनका माहौल भी हमारे हरियाणा की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों जैसा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे हरियाणा में नई सोच के साथ एक नई लीडरशिप मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ लोग बीमारी से कम और एक्सीडैंट्स से ज्यादा मरते हैं। हमारे स्कूलों में सड़क यातायात एवं ट्रैफिक के नियमों से संबंधित एक ऐसा विषय आठवीं कक्षा से अनिवार्य कर देना चाहिए, जिसमें ड्राइविंग लाइसैंस बनाने की प्रक्रिया ट्रेनिंग ओरिएन्टिड होनी चाहिए। कम्प्यूटर स्टीमुलेशन को लाइसैंस बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। विदेशी पद्धति की भी उसमें सहायता ली जानी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के नौजवानों के सामने बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और हमारी भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने इसके लिए भरपूर कदम उठाये हैं। महात्मा गान्धी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना को चला कर भारत सरकार ने मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और इसका पूरा का पूरा समर्थन करते हुए हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ । इसमें मेरा एक सुझाव है कि हरियाणा में इतने इंजीनियरिंग कॉलेज खोलकर हुड्डा जी ने जो तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया है उस बारे में मेरा मानना है कि अगर माननीय मुख्य मंत्री जी डिप्लोमा होल्डर्स को और डिग्री होल्डर्स को स्वयं के रोजगार के लिए ऋण की सुविधा भी कर दें तो यह बहुत अच्छा होगा। डिप्लोमा और डिग्री होल्डर्स को 5 लाख रुपये तक के लोन अपने सैल्फ डिपैंडैंट रोजगार स्थापित करने लिए उनके डिग्री और डिप्लोमा की श्योरिटी पर बिना किसी सिक्योरिटी के दिये जायें तो मैं समझता हूँ कि इससे सैल्फ इम्पलाइमैंट को बढ़ावा मिलेगा और नौजवानों को इम्पलाइमैंट के अवसर मिलेंगे। युवाओं को कोआप्रेटिव मूवमैंट के बारे में शिक्षा देनी चाहिए । अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव है कि हमारी सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में चल रही हैं उनको कोआप्रेटिव मूवमैंट से जोड़ा जाए । इसमें हम गुजरात मॉडल को भी स्टडी कर लें और स्टडी करके उसको इम्पलीमैंट करें तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि प्राइवेट कालेजों में गरीब और अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए फीस माफी का प्रावधान होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल महिला दिवस था और मैं उस बारे में नहीं बोल पाया था तो मैं सभी महिलाओं को उसके लिए बधाई देता हूं और अपना सुझाव देना चाहता हूं कि हरियाणा में जिस तरह से सरपंच के लिए महिलाओं का रिजर्वेशन किया जाता है उसी तरह से हरियाणा के अन्दर नम्बरदारी के लिए भी अगर महिलाओं को 20 या 25 प्रतिशत आरक्षण कर दिया जाए तो इससे महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए बहुत सारी विकास की कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं और इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के शाहबाद भारकण्डा में पानी नीचे चला गया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों से लगभग 267 करोड़ रूपए की लागत से वहां पर दादूपुर नलवी नहर बनवाई है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना

चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर जल्द से जल्द पानी छोड़ा जाए ताकि मेरे किसान भाईयों को उसका फायदा मिले। इसके साथ ही मैं सरकार को एक और सुझाव देना चाहूंगा कि जल स्तर बढ़ाने के लिए मेरे हल्के के अन्दर जो फल्डी एरियाज हैं वहां पर बाढ़ का पानी इक्ट्ठा करने के लिए एक झील बनाई जाए ताकि उस झील से हमारे हल्के के पानी का लैवल ऊपर आ सके । इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी अन्डर ग्राउन्ड वाटर सप्लाई स्कीमें चलाई हैं और उसमें सरकार की तरफ से सबसिडी भी दी जा रही है। इस बारे में मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि इस स्कीम को और बड़े लैवल पर चलाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाईयों को इसका फायदा मिल सके। अध्यक्ष महोदय, जिन गांवों की पंचायतों के पास आमदनी का कोई साधन नहीं है उसके बारे में मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार द्वारा कुछ सालाना फंड उन पंचायतों को दिया जाए ताकि गांवों का और विकास हो सके। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं अपनी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी से एक डिमाण्ड करना चाहता हूं कि एम.पी. फंड की तरह से हरियाणा के एम.एल.एज. को भी फंड मिलना चाहिए ताकि हम अपनी तरफ से अपने इलाकों को कुछ दे सकें। अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां पर शाहबाद मारकण्डा की मण्डी है और यह मण्डी आलू मण्डी के नाम से न सिर्फ हरियाणा में बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध है। आलू मण्डी की फीस चार प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत करनी चाहिए या इससे भी कम करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, वहां पर फीस ज्यादा होने की वजह से व्यापारी 80 प्रतिशत आलू खेतों से सीधा उठा लेते हैं और उससे सरकार के रैवेन्यू को घाटा हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली, पंजाब और यू.पी. में यह फीस बहुत ही कम है इसलिए सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के की कुछ समस्याओं को आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मेरे यहां पर शूगर मिल के अन्दर 102 करोड़ रूपए की लागत से एक प्रोजैक्ट लगाया गया है या नई शूगर मिल लगाई गई है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, इनकी मेहनत से, इनकी अच्छी सोच से मेरे शाहबाद के अन्दर 24 मैगावाट का पॉवर-को-जनरेशन का प्लांट लगा है, जिसका 13 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करने जा रहे हैं। मैं सरकार को इसके लिए बधाई देता हूं लेकिन मेरा एक सुझाव है कि शूगर मिल में डिस्टलरी लगाई जाए ताकि मेरे इलाके के लोगों को और रोजगार मिल सके। अध्यक्ष महोदय, मेरा हल्का शाहबाद कुरूक्षेत्र से 25 किलोमीटर के डिस्टैंस पर है इसलिए मेरा हल्का सब-डिवीजन होना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से यह मांग करता हूं कि मेरे शाहबाद मारकण्डा को सब-डिवीजन का दर्जा मिले। मैं अपनी सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के कारण ही वहां पर ग्रामीण न्यायालय की स्थापना हुई है । माननीय अध्यक्ष जी, जैसे मैंने पहले बताया कि मेरे हल्के में आलू की एक बहुत बड़ी मंडी है इसलिए अगर वहां पर एक चिप्स का प्लांट लगा दिया जाए तो इससे वहां पर किसानों को भी फायदा मिल सकेगा और सरकार के खजाने में पैसा भी आ जाएगा। अध्यक्ष जी, मेरा हल्का दो हिस्सों में बंटा हुआ है । वहां पर रेलवे ब्रिज न होने के कारण यातायात को बहुत ज्यादा बाधित होना पड़ता है इसलिए मेरी आपके माध्यम से गुंजारिश है कि रेलवे लाईन के ऊपर वहां पर ओवर ब्रिज बनाया जाए ताकि मेरे क्षेत्र की जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में हॉकी की एक नर्सरी है वहां की नर्सरी की 9 लड़कियाँ नैशनल टीम में खेलकर आयी हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने पिछले दिनों दर्शन की सुरिन्द्र कौर जो इंडियन टीम की कैप्टन हैं, को डी.एस.पी. का पद देने की घोषणा की है । ऐसा करके उन्होंने

[श्री अनिल धन्तौड़ी]

एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है । विपक्ष के लोग कहते हैं कि वे क्षेत्रवाद करते हैं लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है । अगर सरकार ने या मुख्यमंत्री जी ने बिजली का कोई प्लांट लगाने की पहल की है तो वह सबसे पहले यमुनानगर में लगाने की पहल की है । उन्होंने हरियाणा के एक बेहद गरीब परिवार की लड़की को डी.एस.पी. का पद देकर उसको सम्मान दिया है इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद ।

श्री जगबीर सिंह मलिक (गोहाना) : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया । माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले पांच साल में हरियाणा का हर वर्ग चाहे वह कर्मचारी हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, किसान हो यानी 36 बिरादरी को जो लाभ दिया है, जो उनके लिए काम किया है उसके लिए मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं । सबसे ज्यादा काम उन्होंने एजूकेशन के क्षेत्र में किया है। एजूकेशन किसी भी देश या प्रदेश की तरक्की की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। इस बारे में मुख्यमंत्री की जो दूरगामी सोच थी उसके परिणामस्वरूप उन्होंने हरियाणा के अंदर नयी यूनिवर्सिटी की स्थापना की। उत्तर भारत में खानपुर कला गांव में भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना करके उन्होंने एक नया कदम उठाया है। इस यूनिवर्सिटी के बन जाने से उस एरिया में, उस सब डिवीजन में खुशी की लहर है। इस यूनिवर्सिटी के अलावा उन्होंने उसी खानपूर कला गांव में एक नया मैडीकल कालेज भगत फूल सिंह के नाम से खोलने का जो काम किया है उसके लिए उस इलाके के लोग उनको कभी नहीं भूल सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी भी जो काम उन्होंने किए हैं उनको भी सभी याद कर रहे हैं। कल्पना चावला के नाम से मैडीकल कालेज खोलने के लिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। मेवात के अंदर भी मैडीकल कालेज खोला जा रहा है। इसी तरह से आल इंडिया मैडीकल इंस्टीच्यूट की एक ब्रांच भी झज्जर जिले में खोली जा रही है। पांच सालों में स्वास्थ्य के मामले में बहुत ज्यादा सुविधाएं हरियाणा के लोगों को उन्होंने दी हैं। ऐसा करके उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मैं आपके माध्यम से उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर मैडीकल कालेज और यूनिवर्सिटी होने की वजह से कुछ गांवों से लिंक रोड मैडीकल कालेज तक नहीं है अगर वहां के आसपास के गांवों को सीधे लिंक रोड्ज के द्वारा मैडीकल कालेज तक जोड़ दिया जाएगा तो यह अच्छा रहेगा। हालांकि वहां पर कुछ जगह पर काम चला हुआ है लेकिन अभी और काम तीव्रता से करने बाकी हैं। अध्यक्ष महोदय, टैक्नीकल एजूकेशन में भी बहुत काम किए गए हैं। हमारे प्रदेश के जो बच्चे इंजीनियर बनने के लिए पहले प्रदेश से बाहर जाते थे उनको अब परेशानी से बचाकर अपने प्रदेश में ही उन्होंने उनको जो सुविधा दी है उससे बच्चों में इंजीनियरिंग का कोर्स करने का एक उत्साह है । इससे अब प्रदेश में बेरोजगारी दूर हो सकेगी और प्रदेश का भला भी हो सकेगा। इसके अलावा जो किसानों के लिए सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने काम किये हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं है। पिछले कुछ समय से किसान खेती को घाटे का सौदा समझने लगा था आज वही किसान खेती के कार्य में बड़े उत्साह से लगा हुआ है। वह अब इस काम में क्यों लगा है, वह इसलिए लगा है कि चाहे फसल के भाव की बात है, चाहे पानी की बात है, चाहे खाद की कीमत की बात है सरकार ने किसी भी इनपुट पर टैक्स नहीं लगाया बल्कि हर बार उसकी फसल के भाव बढ़ाये हैं। इन सब बातों से किसानों में खुशहाली की लहर है। पहले किसान जो खेती के लिए कर्ज लेता था उस कर्ज को न चुकाने पर उसे जेल में डाल दिया जाता था और जो 40 दिन की जेल होती थी उस दौरान का खर्च भी किसान के खाते में डाल दिया जाता था। उस काले कानून को खत्म करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है।

अब यह प्रोविजन कर दिया है कि किसान की जमीन बेची नहीं जायेगी बल्कि उसको पट्टे पर दिया जा सकेगा और पट्टे पर दी गई जमीन पर की गई खेती की आमदनी से उस लोन की रिकवरी होगी। इससे किसान की जमीन व उसका पैसा सुरक्षित रहता है। किसानों के जो 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल थे। उन बिजली के बिलों के बारे में जैसा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया कि बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए हॉर्टीकल्चर के क्षेत्र में भी बिजली रेट 4 रुपये प्रति यूनिट से कम करके 25 पैसे प्रति यूनिट कर दिया था। बागवानी के बिजली के रेट कृषि क्षेत्र के बराबर लाकर और उसको न बढ़ाकर बहुत ही बढ़िया काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। जहां तक पानी की बात है उसके लिए हांसी-बुटाना ब्रांच का निर्माण मुख्यमंत्री जी ने पुरजोर प्रयास करके किया है। इस पर लगभग 300 करोड़ रुपये की राशि की लागत आई है, उससे पानी के समान वितरण की योजना बनाई है इस योजना से यह लाभ होगा कि जो पानी दूसरे इलाकों में जाता था वह पानी अब हमारे उस इलाके के लोगों को मिलेगा जिनका उस पर हक था। यह सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। इसी तरह से दादूपुर-नलवी नहर का जिक्र आया, मेवात कैनाल का जिक्र आया। इन नहरों पर पहले कभी हरियाणा में राजनीति करने के लिए काम होता था उन पर कभी वास्तव में काम नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री जी ने नहर विभाग के काम करके हरियाणा प्रदेश में नयी प्रगति की है । जहां तक सड़कों की बात है इस प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। गोहाना के अंदर एक नैशनल हाइवे और बाई पास को मंजूर किया है और उसको जल्दी बनाने के लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय जी से प्रार्थना करता हूं। इसके अलावा एक नया नैशनल हाइवे जींद वाया गोहाना मंजूर हुआ है उस पर भी शीघ्र कार्य करने की आवश्यकता है और मैं उसके शीघ्र निर्माण की प्रार्थना करता हूं । इसके अतिरिक्त जो मुआवजे की बात है वह यह है कि पिछली सरकार के समय में किसान को 2 लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवजा भी नहीं दिया जाता था। जो कुण्डली मानेसर पलवल ऐक्सप्रेस-हाईवे है, उसका मुआवजा 2.5 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से मंजूर हुआ था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने सैंट्रल गवर्नमैंट को लिखकर उस जमीन का मुआवजा 18 लाख रुपये प्रति एकड़ करवाया, यह एक रिकार्ड की बात है। यह मुआवजा पहले मंजूर हो चुका था, परन्तु उसके बाद भी इस सरकार ने उस मुआवजे को रिवाइज करवाया है। इसी प्रकार से किसान की जो जमीन थी उसके अधिग्रहण का रेट माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाया। जहां तक इंडस्ट्रीज की बात है आज हरियाणा में ऐसा माहौल है कि जितने भी उद्योगपति हैं वे हरियाणा के अंदर इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर उन्होंने कई जगह इंडस्ट्रियल इस्टेट की स्थापना की घोषणा की हुई है, इसी तरह से वे गोहाना में भी इंडस्ट्रियल इस्टेट स्थापित करने की घोषणा करें तो मैं उनका शुक्रगुजार होऊंगा । जहां तक पॉवर सैक्टर की बात है, 5 हजार मैगावाट बिजली का उत्पादन प्लान मुख्यमंत्री जी ने बना रखा है जिसमें से 600 मैगावाट का उत्पादन अकेले यमुनानगर थर्मल पॉवर प्लांट से लोगों को दे रहे हैं। उसके बाद खेदड़ प्लांट जो है उसकी एक इकाई ने काम करना शुरू कर दिया है और दूसरी यूनिट अप्रैल तक काम करना शुरू कर देगी । झाड़ली प्लांट की एक इकाई में दिसम्बर तक काम शुरू हो जायेगा। दूसरे, खानपुर खुर्द के प्लांट में काम चालू है और उस प्लांट से जल्दी ही बिजली आनी शुरू हो जायेगी । इसके अलावा फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गाँव में एक परमाणु संयंत्र लगाने जा रहे हैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। देश में पहला परमाणु संयंत्र लगने जा रहा है जो हरियाणा प्रदेश के अन्दर लगने जा रहा है, यह हमारे लिए एक गौरव की बात है।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, वाईड-अप कीजिए ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि गोहाना हल्के के अन्दर जो इण्डस्ट्रियल इस्टेट की स्थापना और मिनी सैक्रेटेरियट बनाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, उसको पूरा करवाया जाए। हरियाणा सरकार ने जो तरक्की माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और श्रीमती सोनिया गान्धी जी के नेतृत्व में की है, उसका मैं आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद ।

श्री नरेश सेलवाल (उकलाना, एस.सी.): स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । सबसे पहले मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने कुछ विचार रखना चाहूंगा । सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में हमारी सरकार ने बहुत सारे कदम उठाये हैं । मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि खरीफ 2009 में भरपूर फसल हुई है, इसमें 13.90 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य की तुलना में 34 प्रतिशत अधिक हमारी फसल हुई है । हमारी सरकार ने रबी 2009 में केन्द्रीय भण्डार के लिए 69 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की है जोकि राज्य के लिए एक रिकार्ड था। इसके फलस्वरूप वर्ष 2008-2009 में गेहूं की प्रति हैक्टेयर उत्पादकता 46.14 क्विंटल के स्तर तक पहुंच गई, जो अब तक का रिकार्ड है । हमारी सरकार के प्रोत्साहन की वजह से हमारी आवश्यकता से अधिक हमारे किसान इसका लाभ उठा सकें हैं और अधिक फसल पैदा कर सकें हैं। गन्ना उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने चालू पिराई मौसम के लिए अगेती किस्मों के लिए 185 रुपये प्रति क्विंटल, मध्यम किस्मों के लिए 180 रुपये प्रति क्विंटल, और पछेती किस्मों के लिए 175 रुपये प्रति क्विंटल भाव दिया है। यह हमारा सभी राज्यों से सर्वाधिक मूल्य है। हमारी सरकार ने किसानों के लिए एक सराहनीय काम किया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की योजना के तहत प्रभावी क्रियान्वयन से किसानों की आय बढ़ी है और हमारी सरकार ने प्रौद्योगिकियां अपनाने के लिए फसलों का विविधीकरण करने और फलों, सब्जियों, फूलों, औषधीय और सुगन्धित पौधों की काश्त करने के लिए प्रोत्साहित किया है। जिसमें बागवानी के लिए भारत सरकार ने कटाई उपरान्त प्रबन्धन और विपणन परियोजनाएं शुरू करने के लिए चालू वर्ष में 170 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की है । इसके लिए मैं सरकार का आभारी हूं कि किसानों के लिए उन्होंने बहुत सारे सराहनीय कदम उठाये हैं । सिंचाई के लिए हमारी सरकार हांसी बांध-बुटाना बहुउद्देशीय लिंक नहर समान पानी के बंटवारे के लिए निकाल रही है, उसके लिए मैं क्या पूरा हरियाणा प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता है। इसके साथ-साथ दादूपूर नलवी नहर जो निर्माणाधीन है उसके लिए भी मैं सरकार की सराहना करता हूं । बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में हमारी सरकार लगभग तीन-चार स्थानों पर थर्मल पॉवर प्लांट लगाने जा रही है। यमुनानगर का हमारा पॉवर प्लांट तो चालू भी हो चुका है और खेदड़ गांव में राजीव गान्धी थर्मल पावर प्लांट जो मेरे हल्के के खेदड़ गांव में पड़ता है का कार्य प्रगति पर है। यह भी बहुत सराहनीय काम है जो 1200 मैगावाट की थर्मल पावर परियोजना है जिसमें से 600 मैगावाट की पहली ईकाई का सिंक्रोनाईजेशन हो चुका है जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया मैं भी उस समय वहां पर उपस्थित था। हमारी सरकार बिजली की उत्पादकता को बढ़ाकर बहुत सराहनीय कार्य कर रही है । इसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय जी को और इस प्रदेश की सरकार को बधाई देता हूं। ग्रामीण विकास की योजना के लिए जो हमारी सरकार काम कर रही हैं उनमें एक महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना है, जिसके तहत पात्र अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों वर्ग ए तथा बी०पी०एल० परिवारों को 100 वर्ग गज के प्लॉट मुफ्त में आबंटित किए जा रहे हैं। अब तक 2.91 लाख पात्र परिवारों को ऐसे प्लाट आबंटित किए जा चुके हैं तथा शेष पात्र परिवारों को प्लाट आबंटन की प्रक्रिया जारी है। अभी बहुत ज्यादा लोग जिनके पास बी०पी०एल०

कार्ड भी हैं और वे सक्षम भी हैं लेकिन वे ये प्लॉट लेने से वंचित रह गए हैं इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे सभी लोग जो बी०पी०एल० कार्ड धारक हैं और जिनके पास रहने के लिए उचित मकान नहीं हैं उन सब तक इस स्कीम का लाभ पहुंचाया जाए। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने बहुत ज्यादा योजनाएं चलाई हुई हैं। हमारी सरकार स्कूलों में पढ़ने वाले 18 लाख जरूरतमंद विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में अभूतपूर्व रूप से अग्रणी है। अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के कक्षा एक से बारह तक के प्रत्येक विद्यार्थी को 75 रुपये से 400 रुपये तक के मासिक वजीफे दिए जाते हैं। लिंगानुपात के अंतर को कम करने और लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत लड़कियों के लिए वजीफे की दर लड़कों से अधिक रखी गई है। इसके लिए मैं सरकार की और मुख्यमंत्री महोदय की सराहना करता हूं। मेधावी छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृति स्कीमों के अतिरिक्त सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं तक पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें और कार्य पुस्तिकाएं मुफ्त दी जा रही हैं। मैं इसके लिए सरकार की सराहना करता हूं कि कमजोर वर्गों के लिए सरकार ने इतनी बड़ी स्कीमें चलाई हैं ताकि वे शिक्षा का लाभ उठा सकें। जो बच्चे फीस नहीं दे सकते थे उनके लिए सरकार ने सभी तरह की सुविधाएं जैसे कपड़ा, वजीफा और पुस्तकें दी हैं ये सब सरकार के सराहनीय कार्य हैं। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में भी सरकार ने बहुत कार्य किए हैं। चिकित्सकों की निरंतर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। नि:शुल्क दवाइयां, सर्जरी पैकेज, गरीबों का नि:शुल्क उपचार आदि ये सरकार के सराहनीय कार्य हैं। जिला अस्पतालों का उन्नयन, शहरी मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, बड़े पैमाने पर नए उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण, सप्ताह में 24 घंटे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का खुला रहना जैसे कदम हमारी सरकार के महान कदम हैं। 14 नवम्बर, 2009 को शुरू की गई हरियाणा स्वास्थ्य वाहन सेवा नंबर 102 में 319 एम्बुलैंस चलाई गई हैं, जिससे हमारे गरीब लोगों को बहुत लाभ मिलेगा । गांव के जो बिल्कुल गरीब लोग होस्पिटल पहुंचने के लिए असमर्थ थे, इन एम्बुलैंस सुविधा के लिए वे हमारी सरकार के हमेशा ऋणी और आभारी रहेंगें । हमारे समाज में महिलाओं और बच्चों का विशेष स्थान है। एक बड़ा विस्तार करते हुए 17,444 आंगनवाड़ियों के मौजूदा तंत्र में 8,255 नए आंगनवाड़ी केन्द्रों की बढ़ोतरी की जा रही है । हमारे जो गरीब बच्चे हैं, वे आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्राथमिक शिक्षा ले सकेंगे। हमारी महिलाएं जो ग्रामीण आंचल में रहती हैं, उनको इन आंगनवाड़ी केन्द्रों से रोजगार के अवसर मिलते हैं, इसके लिए मैं सरकार की सराहना करता हूं ।

श्री अध्यक्ष: नरेश जी, कंक्ल्यूड करें।

श्री नरेश सेलवाल : अध्यक्ष जी, मुझे दो मिनट का समय और दे दीजिए। अध्यक्ष महोदय, हमारा उकलाना क्षेत्र नया हल्का बना है, उसमें काफी दिक्कतें हैं। हमारे उकलाना क्षेत्र में न कोई टैक्नीकल कालेज है और न ही कोई आई०टी०आई० है और न ही हॉयर एजूकेशन का कोई कॉलेज है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उकलाना क्षेत्र में एक आई०टी०आई० और एक हॉयर एजूकेशन का कालेज जरूर स्थापित किया जाए। मैं सरकार से एक और प्रार्थना करता हूं कि उकलाना क्षेत्र हिसार से लगभग 55 किलोमीटर पर पड़ता है। हमारी सब डिवीजन हिसार में है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उकलाना को सब डिवीजन बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से एक मांग है कि मेरे हल्के के अंदर अग्रोहा का क्षेत्र आता है जोकि हरियाणा के लिए एक धार्मिक स्थान और टूरिस्ट प्लेस भी है, लेकिन वहां पर बस स्टैंड भी नहीं है। वहां पर सवारियां खुल्ले परांगण में खड़ी होती हैं इसलिए अग्रोहा के अंदर बस स्टैंड का निर्माण अवश्य करवाया जाये। पूरे भारत वर्ष में अग्रोहा अग्रवाल

[श्री नरेश सेलवाल]

समाज का एक मात्र स्थान है इसलिए वहां पर जो भी कमियां हैं उनको जल्दी से जल्दी दूर करवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध यह भी करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी से खेदड़ गांव की पंचायत मिली थी और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि जिन परिवारों की जमीन खेदड़ प्लांट में एक्वायर हुई है, उन परिवारों में से एक-एक सदस्य को नौकरी दी जायेगी । इसलिए उस घोषणा पर अमल किया जाये और जिन परिवारों की जमीन एक्वायर हुई है उनके एक-एक सदस्य को वहां नौकरी दिलवाई जाये । अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं आपका धन्यवाद करता हूं और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं । धन्यवाद।

राव नरेन्द्र सिंह (नारनौल): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए जो समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । अध्यक्ष महोदय, मुझे तीसरी बार इस विधान सभा में आने का मौका मिला है। इससे पहले मैं 1996 और 2000 में चुनकर आया था। उस समय कांग्रेस विधायक के रूप में हम विपक्ष में बैठा करते थे। उस समय जो सरकार हुआ करती थी, उस सरकार के जो कार्य हुआ करते थे, उनमें स्पीकर महोदय जो कार्य करते थे उनके बारे में आप सभी जानते हैं। कल मैंने देखा जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी उस मौके के ऊपर किस प्रकार से हमारे विपक्ष के साथियों ने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई। अध्यक्ष महोदय, मैं लोक सभा की कार्यवाही टी०वी० के माध्यम से कई दफा देखता हूं। लोक सभा के अंदर जल्दी से किसी सदस्य को नेम नहीं किया जाता, सदन से बाहर नहीं निकाला जाता। लोक सभा इस मामले में बड़ी उदार होती है। अध्यक्ष महोदय, उसी तरह से कल आपने भी बड़ी उदारता दिखाई और आपके कार्य करने के तरीके से मैं प्रभावित हुआ। आपने और सदन के नेता ने विपक्ष के साथियों को पूरा मौका दिया कि वे सदन की कार्यवाही को चलने दें और सदन को तीन बार करीबन आधे-आधे घंटे के लिए एडजोर्न भी किया लेकिन वे नहीं माने । मुझे नहीं पता पहले का, लेकिन जब मैं दो बार विधायक था कभी ऐसा नहीं हुआ करता था। उस समय जब कभी हम लोग अपनी जायज मांग रखा करते थे उसी समय सदस्यों को वार्न करके नेम कर दिया जाता था और सदन से बाहर निकाल दिया जाता था। उस सरकार के जो मुखिया वर्ष 2000 से 2005 के दौरान में हुआ करते थे, कल वे भाई जब महिला दिवस के ऊपर बात कहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रहे थे कि अतीत को देखो । मेरे ख्याल में इंसान बोलने से पहले भूल जाता है कि खुद के अतीत के अंदर क्या हुआ था। अध्यक्ष महोदय, जिस इंसान के राज के अंदर हरियाणा की महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी थी, लूट खसूट का राज था, और भय तथा भ्रष्टाचार का माहौल था वे आज अतीत की बात करते हैं। उस आई०एन०एल०डी० के राज के अंदर हरियाणा के उद्योग प्रदेश से प्लायन कर रहे थे । हम जब दूसरे प्रदेशों में जाते थे तो हमें शर्म आती थी कि हमारे यहां भय और भ्रष्टाचार का माहौल है तथा चारों तरफ लूट खसोट चल रही है। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का राज आया। उस समय मैं विधान सभा में विधायक के रूप में नहीं था। कुछ समय के लिए मैं पार्टी से दूर भी रहा लेकिन सच बात तो इंसान को माननी चाहिए। हमारा जो यह सदन है यह लोकतंत्र का मंदिर है और इस मंदिर के अंदर सदस्य को सही बात कहनी चाहिए क्योंकि अगर यहां झूठ कहेंगे तो जैसा कि सामने लिखा है हम स्वयं पाप के भागीदार होंगे। अध्यक्ष महोदय, यह सच्चाई की बात है कि पिछले पांच साल के दौरान और इन तीन-चार महीनों के दौरान चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने जो विकास कार्य प्रदेश में करवाये हैं उसके लिए प्रदेश की जनता सही मायने में उनकी आभारी है वरना राज हमने पहले भी देखा है। राज हमारी कांग्रेस पार्टी का भी हुआ

करता था लेकिन किसी भी पार्टी के राज के बाद जब विधान सभा चुनाव हुआ करते थे तो उस पार्टी की 8-10 सीटों से फालतू सीट्स कभी नहीं आया करती थी। हमारे मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि इनके अच्छे कार्यों की वजह से दोबारा कांग्रेस पार्टी सत्ता के अंदर आई है । यह बात भी ठीक है कि कुछ साथियों की कमी रह गई जिसकी वजह से कुछ सीट्स कम रह गई वरना और ज्यादा सीट्स आनी थी। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं यह विधान सभा चुनाव हरियाणा जन हित कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीतकर आया था। मैं भी यह बात कहता हूं जैसा कि मेरे माननीय साथी सतपाल सांगवान जी ने कहा कि हम लोगों ने प्रदेश के लोगों के हित में कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला लिया था। 2009 के चुनाव के अंदर जो हरियाणा का मैनडेट आया था उसमें कांग्रेस पार्टी को 40 सीटें मिली थी और निर्दलीय भाईयों तथा बहुजन समाज पार्टी के समर्थन की वजह से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी लेकिन हम लोगों ने यह महसूस किया कि वास्तव में अगर हरियाणा का हित करना है और अगर सही मायनों में प्रदेश का विकास करवाना है तो हमें कांग्रेस पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा का साथ देना चाहिए, जो कि ईमानदारी से कार्य करते हैं। इसलिए हम लोगों ने यह फैसला किया। हमने अपनी हजकां के नेता को भी यह समझाने की कोशिश की कि प्रदेश का हित इसी में है कि हम सभी कांग्रेस पार्टी का साथ दें। स्पीकर सर, सही मायनों में जो फैसला हजकां के 5 विधायकों ने बहुमत के साथ अपनी हजकां पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय करने का किया है वह वैधानिक दृष्टि से पूरी तरह से सही था। मेरे विचार से यह अपने हल्के की जनता की आवाज़ के ऊपर सही समय पर लिया गया सही फैसला था। हम अपने इस फैसले के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। ऐसा करके हम लोगों ने सही पार्टी और सही व्यक्ति का प्रदेश के हित में सही समय पर साथ दिया है। हमें इस बात का गर्व है। हम किन्हीं और बातों की परवाह नहीं करते और न ही हम विपक्ष के भाईयों के झूठे आरोपों से डरने वाले हैं। हम भगवान को साक्षी मानकर सही बात करते हैं। परमात्मा इस बात को देखता है। मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हिन्दुस्तान की कोई भी जांच एजेंसी हमारे इस फैसले में ज़रा सा भी खोट निकाल दे तो हम जिन्दगी में चुनाव लड़ना छोड़ देंगे । एक बात मैं उन भाईयों को यह कहना चाहूंगा, जो अतीत में हमारी वजह से सत्ता में आये थे, अगर उन्हें बहुत ज्यादा घमण्ड है तो वे अपने पद से इस्तीफा दे दें, और इनके साथ हम भी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तथा दोबारा से चुनाव लड़ लेते हैं, इस प्रकार से कौन सही है और कौन गलत, इस बात का फैसला प्रदेश की जनता कर देगी। स्पीकर सर, इस हाऊस के अन्दर हमें सही बात को सही कहना चाहिए। स्पीकर सर, मेरे साथियों ने भी गवर्नर एड्रैस पर अपनी स्पीचिज़ दी हैं। मैं उनका रिपीटीशन करके सदन का समय खराब नहीं करना चाहूंगा क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को भी अपना जवाब देना है। स्पीकर सर, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि सिंचाई के मामले में हमारा जिला नारनौल और महेन्द्रगढ़ का क्षेत्र हरियाणा प्रदेश में अंतिम टेल पर पड़ता है इसलिए इस इलाके के अंदर नहर का पानी पहुंचना बहुत जरूरी है क्योंकि जो नांगल चौधरी और गोंद बलावा का इलाका है उस क्षेत्र के अंदर पीने के पानी का बहुत ज्यादा अभाव है। मुझे याद है कि इन 25-26 गांवों ने वर्ष 1996 के दौरान दोहान-पचीसी के नाम से चुनावों का बहिष्कार किया था क्योंकि उनका यह आरोप था कि उनको पीने का पानी भी नहीं मिलता है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस सरकार ने इस बारे में भरसक कोशिश की है कि वहां के लोगों को पीने का समुचित पानी मिले। मैं माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी से निवेदन करूंगा कि हरियाणा के लोगों के लिए जो पानी के समुचित बंटवारे का सही फैसला लिया है सर, इसके तहत मैं चाहता हूं कि मेरे इलाके में पानी का हिस्सा थोड़ा सा और बढ़ाया जाये। मैं इस बात के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री

[राव नरेन्द्र सिंह]

चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा का आभार व्यक्त करता हूं कि सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण महकमे का कार्यभार भी हमारे ही इलाके के रेवाड़ी से विधायक कैप्टन अजय सिंह यादव जी को सौंपा गया है। इसलिए मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि रेवाड़ी के बाद महेन्द्रगढ़ जिले के लिए भी जो कि हरियाणा के लास्ट में पड़ता है, उस इलाके के लिए भी पानी की मात्रा को बढ़ाया जाये ताकि लोगों को पीने के लिए पानी और खेतों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके क्योंकि वहां का किसान मेहनत करके कमाई करना जानता है। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वहां के नौजवान देश की सरहदों पर सेवा करते हैं। इसलिए भी यह जरूरी हो जाता है कि उस इलाके के लोगों का विशेष ध्यान रखा जाये। इसके साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 392 करोड़ रुपये की लागत से 109 किलोमीटर लम्बी हांसी-बुटाना लिंक नहर का निर्माण करने का साहसिक कदम उठाया है। जिसमें अभी पानी का प्रवाह नहीं हो पाया है, जो कि किन्हीं कानूनी कारणों से रुका हुआ है। मैं समझता हूं कि जल्दी ही ये कानूनी अड़चनें दूर हो जायेंगी तो निश्चित रूप से हमारे इलाके को भी उससे फायदा होगा। स्पीकर सर, इससे सिर्फ हमारे इलाके को ही नहीं अपितु हरियाणा प्रदेश के 16 जिलों को फायदा होगा। इसलिए मैं सिंचाई के मामले में यह कहना चाहूंगा कि इस बारे में कृपा करके थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान दिया जाये। खास तौर से जब बरसात के मौसम में पानी सरप्लस होता है तो उस बरसात के सरप्लस पानी को हमारे इलाके के अंदर छोड़ दिया जाये ताकि वहां का वाटर लैवल ऊपर आ सके । स्पीकर सर, हमारे इलाके में वाटर लैवल 1500 से 2000 फुट तक नीचे जा रहा है इसलिए वहां के किसान के हित के लिए यह जरूरी है कि सरकार के लैवल पर उसके कल्याण के लिए विशेष कदम उठाये जायें। जहां तक शिक्षा का सवाल है मैं माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा का इस बात के लिए आभारी हूं कि हम उस समय विपक्ष में हुआ करते थे और हमें इस बात का पता चला कि हमारे इलाके में सरकार केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करवाने जा रही है। प्रथम दृष्टि तो हमने यह सोचा कि पार्लियामैंट के इलैक्शन होने जा रहे हैं इसलिए सरकार ने इस बात को ध्यान में रखकर कोई नई घोषणा कर दी होगी। जिस समय माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने पूरे हरियाणा में खुलने वाले एकमात्र केन्द्रीय विश्वविद्यालय को हमारे जिले में खोला जाना सुनिश्चित कर दिया उस समय यह बात सच साबित हो गई। इस बात के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ-साथ जो सरकार द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सैमेस्टर प्रणाली शुरू की गई है यह भी काबिले तारीफ कदम है। इसके अलावा जो कम्प्युटर शिक्षा को सभी क्लासिज के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, सरकार का यह कदम भी सराहनीय है और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इसके दूरगामी परिणाम निकलेंगे। स्पीकर सर, इसके साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) मंत्री श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने नारनौल शहर को विशेष पैकेज के अंतर्गत रखकर हरियाणा के 15 शहरों में शामिल किया है जिसके तहत पूरे शहर को प्राथमिक तौर पर पानी और सीवरेज की 100 प्रतिशत सुविधा मुहैया करवाई जायेगी। इसके अलावा मैं एक बात के लिए और सरकार का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जो सरकार द्वारा हरियाणा के नौजवानों को पॉवरलूट की ट्रेनिंग देने के लिए बाछौद (नारनौल) के अन्दर एक इंस्टीच्युट शुरू किया गया है ।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, is it the sense of the House that the time of the sitting of the House be extended for one hour ?

Voices : Yes, yes.

Mr. Speaker : The sitting of the House is extended for one hour.

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भण)

14.00 बजे **राव नरेन्द्र :** अध्यक्ष महोदय, साथ ही मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और लोक निर्माण मंत्री जी का भी आभारी हूँ। हमने इनसे एक निवेदन किया था कि राजस्थान बॉर्डर से भिवानी-जीन्द की तरफ कोई अच्छी रोड़ नहीं है इसके सुधार के लिए कोई अलग से कार्यक्रम बनाया जाये। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि पिछले दिनों इस काम के लिए सर्वे भी करवाया गया है और नांगल चौधरी से लेकर राजस्थान बॉर्डर तक और भिवानी-जीन्द तक के रोड़ को फोर लेन बनाने के लिए केन्द्र को भी इस बारे में आगामी कार्यवाही हेतु लिखा गया है। लगभग 1100 करोड़ रुपये का जो प्रोजैक्ट बी०ओ०टी० के आधार पर सरकार बनाने जा रही है, यह एक बहुत ही बढ़िया शुरूआत होगी । उससे नांगल चौधरी में न केवल बाईपास की समस्या दूर होगी अपितु नांगल-चौधरी नारनौल रोड़ पर रेलवे ओवरब्रिज का भी उसमें समाधान होगा। नारनौल के बाईपास के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने खुद घोषणा की हुई है उसका उससे सुधार होगा। नांगल सिरोही गाँव जो महेन्द्रगढ़ विधान सभा में पड़ता है उसका भी विकास होगा । महेन्द्रगढ़ में बाईपास का भी समाधान होगा । इसके अलावा अनेक ऐसे कार्य होंगे जिससे उस इलाके का विकास होगा। साथ ही स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जरूर निवेदन करूँगा कि वे जिला महेन्द्रगढ़ को औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ घोषित करें । सर, हमारे पड़ोस का जो इलाका है चाहे वह बहरोड़ है, चाहे नीमराणा है, चाहे भिवाड़ी का इलाका है उन इलाकों में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। अगर सरकार जिला महेन्द्रगढ़ को औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ घोषित करती है तो बाहर के उद्योगपति वहाँ जाकर उद्योग लगाना चाहेंगे और उससे मैं समझता हूँ कि उस इलाके की काथाकल्प होगी । उद्योग लगेंगे तो उस इलाके के बेरोजगारों को फायदा होगा । उद्योग लगेंगे तो वहाँ के किसान की जमीन महंगी होगी और उसको फायदा पहुंचेगा। मुख्य मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरफ जरूर ध्यान दें । अध्यक्ष महोदय, महेन्द्रगढ़ के साथ में नारनौल हैडक्वार्टर है इसलिए मेरा इनसे निवेदन है कि हुडा की तरफ से वहाँ पर जिमखाना क्लब की व्यवस्था भी होनी चाहिए। टूरिज्म के लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से और मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि नारनौल हैडक्वार्टर होने के बावजूद वहाँ पर टूरिज्म का कोई रैस्ट हाउस नहीं है इसलिए इस तरफ भी आप ध्यान दें। इसी प्रकार से नारनौल में पुरातत्व की बहुत सी चीजें हैं जैसे जलमहल तथा ढोसी का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। इसी प्रकार से नारनौल का छत्ता ऐसी चीजें हैं जिस पर अगर सरकार विशेष ध्यान दे तो मैं समझता हूँ कि बाहर से भी पर्यटक विशेष रूप से उनको देखने के लिए आयेंगे । इन कुछ चीजों की तरफ आप कृपा ध्यान दें। इन शब्दों के साथ स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ ।

श्री रघुबीर सिंह तेवतिया (पृथला) : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद । हरियाणा में पिछले 5 साल जो सरकार रही उसने राजनीति के मायने ही बदल दिये हैं । जो बदले की भावना, जो झूठे मुकदमें, जो भय भ्रष्टाचार मिटाने का काम माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ । जो विकास के रूप में हरियाणा में हर क्षेत्र में काम चल रहे हैं उसके लिए भी मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ । सर, हमारा पृथला नया विधान सभा क्षेत्र बना है और उसके विकास के लिए काफी पैसा दिया गया है । वहां पर सड़कों का भी काम चल रहा है, कुछ सड़कें भी 12 फुट से 18 फुट चौड़ी बनाई जा रही हैं, चाहे वे फजलपुर से जनौली, मांडकौल, देवली और भगौला तक हो । चाहे आलापुर से आमरू, दुधौला, सिकन्दरपुर, भुर्जा कलबाके तक हो या पृथला से छपरौला, सहराला तक बनाई जा रही हैं। इसके बावजूद भी मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि बल्लभगढ़ से मोहना गांव तक सड़क का एक बहुत बड़ा भाग टूटा पड़ा है, उसको भी बनवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे से पहले बोलते हुए मेरे साथी विधायक ने फरीदाबाद के बारे में जिक्र किया था। वहां पर एक फैक्टरी द्वारा आगरा कैनाल में कैमिकल का पानी डाला जाता है । जब हमारे किसान भाई उस कैनाल से पानी खेतों में डालते हैं तो उनको चर्म रोग हो जाता है, इस बारे में सरकार को कोई न कोई कार्यवाही करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज फसल पकने के नजदीक है, हमारे यहां पर एक धतीर डिस्ट्रीब्यूटरी है, उसमें पानी छोड़ा जाए ताकि किसान को अपनी फसल पकाने में मदद मिल सके, यही मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है। अध्यक्ष महोदय, पलवल यू.पी. के नजदीक लगता है । हमारे हरियाणा में खाद की कोई कमी नहीं है और यू०पी० के मुकाबले हमारे यहां पर खाद सस्ती है । वहां पर जो यू०पी० से किसान और डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं वे उस खाद को ले जाते हैं और उसको ब्लैक करते हैं जिसकी वजह से हमारे यहां पर खाद की कमी हो जाती है । मैंने इस बारे में पिछली सरकार के वक्त में जब मैं विधायक नहीं था उस समय भी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की थी और मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने उसी वक्त वहां के डी०सी० को इस बारे में सख्त कार्यवाही करने के लिए कहा था। मेरा इस बारे में इस बार फिर से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि पलवल और यू०पी० के बीच में अलीगढ़ पर नाका लगाया जाए ताकि हमारे यहां पर होने वाली खाद की कमी को रोका जा सके। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हमारे पृथला में एक दोआबा मिल्क प्लांट है और मिल्क प्लांट वाले जो फैक्टरी से पानी निकालते हैं वह खुले में जाता है और उससे बहुत बदबू आती है। पानी बदबूदार होने की वजह से और खुले में होने की वजह से वहां पर बहुत मच्छर हो जाते हैं। इस बारे में वहां के किसानों और लोगों ने धरना भी दिया था। मेरा सरकार से और मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस बारे में भी ध्यान दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, जब चौटाला साहब की सरकार थी उस वक्त मोहाना गांव में उप-तहसील बनाने की घोषणा की गई थी। अध्यक्ष महोदय, उस क्षेत्र में 38 गांव पलवल के और 62 गांव फरीदाबाद जिले के आते हैं । वहां के लोगों को अपने काम करवाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है इसलिए मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वहां पर उप-तहसील बनवाई जाए । अध्यक्ष महोदय, इसके साथ हमारे यहां पर 10-12 गांव मनकपुर, सिकरौना, कबलपुर भांगर, लादियापुर, करनेरा, नंगला, जोगीयान, मौहला, हरफला, दूधौला व मीरापुर हैं, वहां पर खारा पानी है और बंजर जमीन है आज वहां का पानी नीचे चला गया है । हमारे हरियाणा में बहुत सी जगहों पर मीठा पानी है, वहां से हमारे इन 10-12 गांवों में मीठा पानी दिया जाए,

यही मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है और इस बारे में ध्यान दिया जाए । हमारे पृथला के अन्दर 100 गांव पड़ते हैं और वहां पर कोई भी सरकारी कालेज नहीं हैं । अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां से लड़के तो कहीं और जाकर पढ़ सकते हैं लेकिन हमारी जो बहन-बेटियां हैं उनको वहां से दूर न जाना पड़े इसलिए हमारे पृथला में एक सरकारी कालेज बनाने का कष्ट करें जिसकी वहां पर बहुत जरूरत है, इसके लिए कई गांवों की पंचायतें जमीन देने के लिए तैयार हैं। जनोली, अलादलपुर जैसे बहुत बड़े-बड़े गांव हैं। उस क्षेत्र का जो एरिया है वह भी बहुत बड़ा है इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इस बारे में ध्यान दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया है उसके लिए मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

Mr. Speaker : Now, the Hon'ble Chief Minister will give reply.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो 5 मार्च, 2010 को इस सदन में आकर सदन को सम्बोधित किया था, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, पांच साल पहले चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। उस वक्त हमें इस प्रदेश की सेवा करने का मौका मिला। पांच साल में राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक माहौल बदलने का हमने पूरा प्रयास किया। सत्ता संभालने के तुरन्त बाद हमने उसी समय यह महसूस किया कि परिवर्तन के पीछे लोगों की गहरी भावनाएं छिपी हुई थी। उनकी बहुत उम्मीदे थीं, आशाएं थीं। हमने उनकी उन्हीं भावनाओं और उम्मीदों को समझकर पांच साल में अपनी सरकार की नीतियों का निर्धारण किया। हमने प्रयास किया कि हर वर्ग का जीवन स्तर अच्छा हो, ऊंचा हो तथा पूरे प्रदेश का सामुहिक विकास हो। अध्यक्ष महोदय, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हरियाणा 1966 में बना और 1966 से लेकर अब तक केवल एक बार ही उसी पार्टी की सरकार बनी है जिस पार्टी की पहले सरकार थी। जैसे हमारे साथी नरेन्द्र सिंह ने कहा कि 1972 के बाद का अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो जिस भी पार्टी की सरकार रही है उसका चुनाव के बाद विपक्ष का नेता भी नहीं बना । 9 एम०एल०एज० भी उसके नहीं बनें। ऐसा पहली बार है कि दूसरी बार उसी पार्टी की सरकार बनी है जिसकी पहले सरकार रही थी । सबसे पहले हमने यह प्रयास किया कि उस समय जो माहौल था, उस को बदलते हुए हमने भयमुक्त शासन दिया। उस समय जो इंडस्ट्रीज यहां से छोड़कर जा रही थीं और लोगों का आत्मविश्वास हिला हुआ था, उसको हमने बदला। अध्यक्ष महोदय, उस समय की सरकार की ज्यादा चर्चा मैं नहीं करना चाहता क्योंकि सबको मालूम है। कई साथियों ने इसका जिक्र भी किया है । उस समय लोगों में एक भय बैठा हुआ था और हरियाणा का विकास रूका हुआ था । हमने सबसे पहला महत्वपूर्ण काम लोगों के मानस से भय निकालने का किया, उनको भयमुक्त किया ताकि सब मिलकर अपने प्रदेश को आगे ले जाने का प्रयास कर सकें। हमने प्रदेश में शान्ति का माहौल बनाया। हमने प्रदेश में एक फ्रैन्डली इन्वैस्टमैंट माहौल बनाया ताकि यहां पर लोग आएं और निवेश करें जिससे हमारे प्रदेश की प्रगति हो । अध्यक्ष महोदय, समूचे देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजरे हैं। आपने भी देखा होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आर्थिक मंदी आयी और जो विकसित देश जिनको हम डिवैल्पमैंट कंट्री भी कहते हैं, यानी अमरीका जैसे देशों के बैंक भी फेल हो गये और उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा गयी लेकिन मैं इस बात के लिए मनमोहन सिंह जी को और यू०पी०ए० की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को हार्दिक बधाई देता हूं कि बावजूद इसके हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था आज भी मजबूत है। आप चाहें किसी भी देश को देखें। अध्यक्ष महोदय, यह उनकी दूरदर्शिता का ही नतीजा है। यह कोई

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

छोटी बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश या प्रदेश के विकास के लिए अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो वह रिसोर्सिज की जरूरत होती है । जब तक रिसोर्सिज नहीं होंगे तब तक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी । इसके बिना आप कोई भी विकास का कार्य नहीं कर सकते हैं इसलिए सबसे पहले हमने अपने रिर्सोसिज को मजबूत किया और विकास कार्यो के लिए धनराशि की व्यवस्था की। इस बारे में आंकड़े आपके सामने हैं। किसी भी प्रदेश के विकास का पैमाना या पैरामीटर उसका प्लांड बजट होता है और वर्ष 2000 से लेकर 2005 तक पांच साल का बजट 9235 करोड़ रुपये का था और अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है, गर्व भी है और मैं सभी साथियों को बधाई भी देता हूं कि अब जो बजट वित्त मंत्री जी देने जा रहे हैं उसमें मेरे को उम्मीद है कि यह बजट 10400 करोड़ रुपये का होगा यह एक साल का बजट होगा जो कि उनके 5 साल के बजट से ज्यादा होगा । जिन बातों का राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया है उन बातों की चर्चा की पुनरावृत्ति मैं नहीं करना चाहता । प्रति व्यक्ति आय जो पिछले वर्षों में कम हुआ करती थी वह बड़े प्रदेशों में सबसे अधिक हरियाणा की है सिर्फ गोवा प्रदेश हमसे आगे है। जैसा आपने कल देखा कि मंहगाई के मुद्दे पर विपक्ष का व्यवहार रहा, वह बहुत ही निंदनीय रहा। मंहगाई का जहां तक सवाल है तो मंहगाई के बारे में यू०पी०ए० सरकार भी और हर व्यक्ति चिंतित है। उसे रोकने के लिए केन्द्र सरकार की यू०पी०ए० सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। जैसे श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने बताया कि उनके समय में किस प्रकार से डीजल के रेट बढ़े थे और किसानों को क्या मिला था ? इस बारे में सब उन्होंने तुलनात्मक रूप से बताया । मंहगाई के बारे में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि विपक्ष के साथियों ने मंहगाई पर घड़ियाली आंसू बहाने का काम यहां किया। मुझे नहीं लगता कि उनको इस बात की कोई चिंता है। जहां तक मैं समझता हूं, उनको चिंता इस बात की है कि हरियाणा की जनता ने इस सरकार को दोबारा यहां चुनकर कैसे भेज दिया । स्पीकर सर, फिर भी मैं आपका आभारी हूं कि आपने उनको कई बार मौका दिया । इस हाउस की गरिमा को बनाये रखने के लिए आपने तीन बार हाउस को एडजर्न भी किया और इस बात के लिए भी आश्वस्त किया कि आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। मंहगाई पर जो उन्होंने एडजर्नमैंट मोशन दिया था उसको कालिंग अटैंशन मोशन में कन्वर्ट करके आपने उसे स्वीकार किया । सुबह एक हमारी बहन बी०जे०पी० की सदस्या हैं उनके अनुरोध पर मैंने उसी समय हाउस की सैंस लेकर आपसे निवेदन किया और कहा कि विपक्ष के साथी अगर गरिमा से हाउस को चलाएं तो आप उन्हें वापस बुला लें। आपका मैं आभारी हूं कि आपने उसी समय कहा और उनको बुलाया लेकिन वे फिर भी वापस नहीं आए। वे वापस इसलिए नहीं आए क्योंकि उनके पास इन बातों का कोई पुख्ता जवाब नहीं है, उनके पास कोई इतिहास नहीं है। जब आंकड़े देखे जाते हैं, मुकाबला किया जाता है तो वे पिछड़ जाते हैं उनमें इस बात को फेस करने का साहस नहीं है। मैं यही कह सकता हूं कि मंहगाई की चिंता सबको है और इस मामले में तो उनको सरकार का सहयोग करना चाहिए और उसे रोकने के लिए सुझाव देने चाहिएं ताकि सरकार कदम उठा सके, वैसे सरकार कदम उठा रही है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश के विकास का जो सवाल है वह यह है कि फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। इस बात को मद्देनजर रखते हुए ही हमने अपने कार्यकाल में बिजली और पानी पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है । बिजली के बारे में आपको पता ही है कि 1966 में हरियाणा बना और 2005 तक बिजली की कुल जनरेशन 1587 मेगावाट थी और बाहर की परियोजनाओं में हिस्सा मिलाकर कुल जनरेशन 4000 मेगावाट थी और अब हर वर्ष यह जनरेशन 10 से 15 प्रतिशत बढ़ते हुए 9000 मेगावाट तक पहुंच जायेगी, बल्कि उससे भी ज्यादा जनरेशन हो

जायेगी । स्पीकर सर, अगर विकास करना है तो बिजली ही विकास की धुरी है, बगैर बिजली के विकास नहीं हो सकता है लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पांच साल के दौरान एक भी नया प्लांट पहले की सरकार ने नहीं लगाया और न ही इसके लिए कभी सोचा। इस कारण उस समय हमने फैसला किया था कि पिछले पांच साल के दौरान 5000 मैगावाट के साधन उपलब्ध करेंगे । मुझे यह बात कहते हुए खुशी होती है कि उनमें से यमुनानगर प्लांट में 600 मैगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है और खेदड़ में भी एक यूनिट का उत्पादन शुरू हो गया है। इसी प्रकार झाड़ली में भी बिजली का उत्पादन शुरू होने वाला है। आने वाले एक-डेढ़ साल में हम 5000 मैगावाट बिजली पैदा करने में कामयाब होंगे। जहां तक बिजली के सुधार के लिए जनरेशन के अलावा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूशन की बात है, उसके लिए हमने बहुत कदम उठाये हैं। एग्रीकल्चर और रूरल सैक्टर में ऐग्रीगेशन के लिए भी हमने काफी काम किया है, उससे भी बिजली उपलब्धता में बहुत सुधार होगा, गाँवों को काफी बिजली मिलेगी और ट्यूबवैल्ज को भी काफी बिजली मिलेगी । दूसरी चर्चा मैंने सिंचाई की व्यवस्था के बारे में की है। सिंचाई के मामले में आपको मालूम है कि सबसे बड़ा हमारा मकसद है कि हरियाणा के हर कोने में हम पानी पहुंचायें जिसका जितना हक बनता है उसको उसका हक मिलना चाहिए। उसके लिए एस०वाई०एल० नहर का पानी लेने के लिए हमारा पूरा प्रयास है, उसमें हमारा हक है और हम अपने पानी का हक लेकर रहेंगे । इसके लिए हम पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रैजीडैंशिएल रैफरैंस पैंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के हक में अपना फैसला दे चुका है उसके लिए जो प्रैजीडैंशिएल रैफरैंश पैंडिंग है उसकी जल्दी से जल्दी हीयरिंग हो, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जितना हमारे पास पानी उपलब्ध है उसका न्यायोचित समान बंटवारा हो । हमने बी०एम०एल० हांसी-बुटाना लिंक नहर का निर्माण किया है, इस पर 392 करोड़ रुपये की लागत आई है। अध्यक्ष महोदय, जींद, अम्बाला, कुरूक्षेत्र, करनाल, गुड़गांव, मेवात, हिसार, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी, फरीदाबाद, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, कैथल और भिवानी 16 जिलों को इस नहर के निर्माण से लाभ होगा। इसी प्रकार से दादुपुर-नलवी नहर के बारे में आपको अच्छी तरह से मालूम है, हमने हर विधानसभा की प्रोसीडिंग्ज देखी हैं और हर सरकार के कार्यकाल में विधान सभा में यह बात उठाई गई लेकिन उसके निर्माण के लिए किसी ने शुरूआत नहीं की। इस सरकार के आने के बाद उस नहर का फर्स्ट फेज का काम पूरा हो चुका है और दूसरे फेज का काम पूरा होने जा रहा है। इसी प्रकार से मेवात कैनाल की बात है या अम्बाला कैनाल की बात है चाहे कौशल्या डैम की बात है या भिण्डावास झील और ओटू वियर झील या मैसानी बैराज की क्षमता बढ़ाने की बात है उनकी क्षमता बढ़ाई जा रही है और रजवाहों को मजबूत बनाया जा रहा है। एक एक बूंद पानी का सही इस्तेमाल हो और सही रास्ते तक पहुंचे इस बारे में मेरे बहुत से माननीय सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की है। हमारे मंत्री जी ने भी सुबह प्रश्नकाल के दौरान इस बात की चिन्ता जाहिर की और इस बात की हमें भी चिन्ता है कि अब की बार जो हमारा पानी का हिस्सा है वह और भी कम मिला है। इसके लिए हम और ज्यादा तेजी से कार्य करेंगे ताकि हर हिस्से को पानी बराबर मिले। दूसरा, सड़कें और परिवहन के इन्फ्रास्ट्रक्चर हैं। सड़कों के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। 135 किलोमीटर लम्बी कुण्डली-मानेसर-पलवल एक्सप्रैस हाईवे बन रहा है और उसमें काफी प्रोग्रैस हुई है। इसके बनने से बहुत विकास हरियाणा प्रदेश का होने जा रहा है। जैसा कि नरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि इस प्रकार की परियोजनाएं भी सोची जा रही हैं जिनसे हिन्टर लैण्ड में सड़के जोड़ी जायें। जिस प्रकार से आज अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा विकसित देश है उसका क्रेडिट आईजन हॉवर को है जिन्होंने बड़ी बड़ी-सड़कें बीच में बनाई और उससे देश का विकास हुआ।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि यहां पर कनैक्टिविटी और इन्फ्रास्ट्रैक्चर का पूरा विकास हो। परिवहन की नई नीतियां बनाई जा रही है, जिसके तहत 17 से अधिक नए स्टेट कैरियर परमिट बनाने का फैसला हमने किया है । फरीदाबाद में विगत जनवरी से सिटी बस सेवा का पहला चरण शुरू हो गया है । लो फ्लोर बसिज चालू हो गई हैं। दिल्ली से गुड़गांव तक मैट्रो का फर्स्ट ट्रायल हो चुका है और अप्रैल मई से यह सेवा शुरू हो जाएगी । यह बहुत बड़ी उपलब्धि है । इसी प्रकार से बदरपुर- फरीदाबाद, दिल्ली-बहादुरगढ़ और तीसरा फेज नरेला से कुण्डली तक विचाराधीन है ताकि इनको मैट्रो से जोड़ा जाए और प्रदेश के लोगों को इसका लाभ पहुंचाया जाए । अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि हमारी सरकार के आने से पहले के 40 सालों में कुल 16 आर०ओ०बीज० बने थे जबकि हमारे पिछले 5 सालों के कार्यकाल में 33 आर०ओ०बीज० पर काम शुरू हुआ था। उनमें से 16 आर०ओ०बीज० बन चुके हैं और बाकियों पर निर्माण कार्य शुरू हो रहा है । यह कोई छोटा काम नहीं है। शहरों और गांवों में आम आदमी की हाऊसिंग की समस्या के समाधान के लिए भी सरकार ने विचार किया है। गरीब आदमी और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए हाऊसिंग सुविधा देना हमारी विशेष प्राथमिकता है। इसी को विचार में रखकर एक बड़े स्केल पर छोटे घरों का निर्माण करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। इस स्कीम में हमने एक अमैंडमैंट की है ताकि प्राइवेट बिल्डिर्ज एफोर्डेबल मकान बना सकें। गुड़गांव और फरीदाबाद में हम देखें तो एक फ्लैट की कीमत करोड़ों रुपये में है जो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। मिडल क्लास के लोग भी ये मकान नहीं ले सकते । हमारी सरकार ने ऐसे एफोर्डेबल हाउसिज की स्कीम अलग से बनाई है ताकि गरीब और मिडल क्लास के लोग ये मकान ले सकें। पीने के पानी के लिए प्रदेश में स्कीमें बनाई गई हैं। गांवों में भी और शहरों में भी गरीब आदमियों को और शिडयूल्ड कास्ट के लोगों को 200 लिटर की पानी की मुफ्त टंकिया और कनैक्शन दिए गए हैं ताकि हर आदमी को स्वच्छ पीने का पानी मिल सके । हमने गांवों में भी और शहरों में भी हर क्षेत्र में काम किए हैं। गुड़गांव और मानेसर में पीने के पानी की कमी को देखते हुए 500 क्यूसिक की क्षमता की नई नहर निर्माणाधीन है। 15 छोटे शहरों में वाटर सप्लाई और सीवरेज का आलरेडी आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज दिया हुआ है और आगे की बढ़ती हुई आबादी की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी हमारे लिए समस्या है। सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती तथा सब खेती पर निर्भर भी नहीं कर सकते क्योंकि जोत बहुत छोटी होती जा रही है। बेरोजगारी खत्म करने का तीसरा रास्ता जो है वह इंडिस्ट्रियलाइजेशन है यानि इंडस्ट्रीज बढ़ें। एक मदर यूनिट कहीं पर आती है तो उसके साथ साथ छोटी-छोटी यूनिट्स भी कई आती हैं। जिस कारण इंडस्ट्रीज में हजारों, लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। अगर हमारा इंडस्ट्रीज इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो लोग आगे आएंगे। कुछ बच्चे खुद अपनी इंडस्ट्रीज लगाएंगे और कुछ इंडस्ट्रीज में नौकरी करेंगे । इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एच.एस.आई.आई.डी.सी. के माध्यम से अनेक इस्टेट बनाई गई हैं। हम नई आई०एम०टी० फरीदाबाद में बना रहे हैं । आई०एम०टी० खरखौदा में और आई०एम०टी० अम्बाला में भी बनने जा रही हैं । आई०एम०टी० रोहतक में पूरी होने वाले है। छः राज्यों से गुजरने वाले लगभग 1480 किलोमीटर लम्बे फ्रेट कोरिडोर के साथ साथ विकसित किए जा रहे दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कोरिडोर प्रोजैक्ट से प्रांत का विकास और आगे बढ़ेगा । इसके तहत 3 बड़े प्रोजैक्ट हम बनाने जा रहे हैं और ये प्रोजैक्ट हैं गुड़गांव-मानेसर-बावल के बीच मास रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एग्जीबिशन-कम-कंवेंशन सैंटर और इण्टीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब । जो दिल्ली एग्जीबिशन

ग्राउंड है उसको भी मानेसर में लेकर जा रहे हैं। इस बारे में केन्द्र सरकार से बात हो गई है और इसके लिए जमीन भी आईडैंटीफाई हो गई है। इसके साथ-साथ हम इण्डस्ट्रियल मोडीफाई हब भी बनाने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि किसान और कृषि हमारे प्रदेश की रीड की हड्डी हैं। कृषि हमारे प्रदेश का मुख्य व्यवसाय है और हमारे प्रदेश के लोगों का विकास इससे जुड़ा हुआ है। हमने किसान के विकास और ग्राम विकास के लिए बहुत से ठोस कदम उठाये हैं। हमने भूमि अधिग्रहण पर भारी मुआवजा और रॉयलटी का प्रावधान किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भूमि अधिग्रहण के लिए जो नीति हमने अपना रखी है यह नीति हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस प्रकार की प्रथम नीति है, जो कि भारी मुआवजे के साथ-साथ 33 साल तक रॉयलटी भी देती है। अध्यक्ष महोदय, हम किसानों की भलाई के लिए किसान आयोग का भी गठन करने जा रहे हैं। हम सभी को मालूम है कि पशुपालन किसान की आमदनी को बढ़ा सकता है इसलिए अच्छी नस्ल के पशुओं की बढ़ोत्तरी के लिए भी हमने कई कदम उठाये हैं। यही वजह है कि हिसार के अंदर लाला लाजपत राय के नाम से एनीमल साईंसिज पर वैटरनरी यूनीवर्सिटी बनाने जा रहे हैं क्योंकि लाला लाजपत राय जी कुछ दिन हिसार में रहे थे। इसी प्रकार से हमने किसानों के हित में 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ किए जिनको वे लोग छोड़कर चले गये थे । बिजली के बिल माफ करने पर 9,21,736 परिवारों को फायदा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जिस समय हमारी सरकार आई उस समय कोऑपरेटिव बैंक द्वारा शॉर्ट टर्म लोन किसानों को 11 प्रतिशत ब्याज दर पर दिए जाते थे जो कि आज 4 प्रतिशत ब्याज दर पर दिए जा रहे हैं। इसके साथ-साथ जो लोन न चुकाने पर जमीन नीलाम करने का और जेल में डालने का काला कानून था उसको भी हमने खत्म किया है । पहले लोन न चुकाने पर छोटे-छोटे बच्चों को भी जेल में डाल दिया जाता था लेकिन अब किसी किसान की जमीन नीलाम नहीं होगी और किसी किसान को जेल में भी नहीं जाना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, जिस समय हमारी सरकार आई उस समय किसान को एक ट्रैक्टर निकलवाने के लिए 4-5 एकड़ जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी जिसको हमने कम करके केवल एक एकड़ कर दिया है। अब किसान एक एकड़ जमीन पर ट्रैक्टर निकलवा सकते हैं तथा जिन्होंने पहले 4-5 एकड़ जमीन ट्रैक्टर लेने के लिए गिरवी रखी हुई थी उसको भी वापिस करवाया है। जिससे 4463 किसानों की 6000 एकड़ भूमि रिलीज हुई है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जो कोऑपरेटिव बैंक के लोन थे, उन लोन पर ब्याज की दर की माफी की थी, उससे 4 लाख 70 हजार किसानों को 492 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। इसी प्रकार से केन्द्र सरकार ने यू.पी.ए. की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में प्रधान मंत्री सरदार मनमोहन सिंह ने किसानों के 71,000 करोड़ रुपये के ऋण माफ किए जो कि ऐतिहासिक फैसला है। ऐसा फैसला दुनिया में किसी ने नहीं किया है। इस फैसले से हरियाणा के 7 लाख 15 हजार किसानों को 2136 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। हमारे विपक्ष के साथी 1987 की बात करते हैं, जिस समय चौधरी देवी लाल ने 33.64 करोड़ रुपये माफ किए थे। अध्यक्ष महोदय, हम 71 हजार करोड़ रुपये की बात कर रहे हैं और ये लोग 33.64 करोड़ रुपये को लेकर बहुत हल्ला कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जिन छोटे दस्तकारों ने और मुमिहिनों ने छोटे-छोटे कर्जे 30.6.2009 तक ले रखे थे, उनका भी 10 हजार रुपये तक का कर्ज और ब्याज माफ किया गया है। इसी प्रकार से नैचूरल क्लेमिटी जैसे ओलावृष्टि आदि से यदि किसानों की फसल को नुक्सान होता है तो उसके मुआवजे में भी हमने भारी बढ़ोत्तरी की है । अध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में सदन में बताना चाहूंगा कि हमने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी बहुत प्रयास किए हैं । हमने समैस्टर सिस्टम लागू किया है और जैसा कि दूसरे सदस्य भी चर्चा कर रहे थे कि हमने शिक्षकों की भी भर्ती की है तथा नई

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

भर्ती भी करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से सैंट्रल यूनीवर्सिटी महेन्द्रगढ़ में, डिफैंस यूनीवर्सिटी गुड़गांव में, वाई०एम०सी० यूनीवर्सिटी फरीदाबाद में, सर छोटूराम साईंस एंड टैक्नोलोजी यूनीवर्सिटी मुरथल में, वैटरनिटी साईंस यूनीवर्सिटी हिसार में, महिला विश्वविद्यालय खानपुर में बनाये हैं ताकि हमारे प्रदेश के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से चाहे कोई गरीब हरिजन का बच्चा है या बी०सी०ए० का बच्चा है या 36 बिरादरी में से किसी भी बी०पी०एल० परिवार का बच्चा है उनके लिए पहली कक्षा से वजीफे का प्रोविजन हमने किया है उनको हम पहली कक्षा से स्कॉलरशिप देते हैं। 75 रुपए से लेकर 400 रुपये प्रति महीने तक की हम उनको स्कॉलरशिप देते हैं ताकि हमारे बच्चे पढ़ सकें। इसी प्रकार से स्वास्थ्य के विषय के ऊपर भी हमने बहुत ध्यान दिया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने अपने पिछले शासन काल में स्वास्थ्य पर जो हमारी सरकार के सत्ताहीन होने से पहले बजट था उसको बढ़ाकर सात गुणा के करीब कर दिया है ताकि प्रत्येक प्रदेशवासी का स्वास्थ्य ठीक हो सके। आज सरकारी हस्पतालों में दवाईयां मुफ्त मिल रही हैं। पैकेज सर्जरी का भी हमारी सरकार द्वारा प्रावधान किया गया है। इसके अलावा हम प्रदेश में नये-नये मल्टी स्पैशलिटी हॉस्पिटल्ज़ बनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि एम्बूलैंस सर्विस जो हमारी सरकार ने 102 नम्बर से शुरू की है उसका भी प्रदेश की जनता को बहुत अच्छा लाभ पहुंचा है। इसी प्रकार से हमने प्रसूति गृह भी बनाये हैं। हमारी सरकार ने बहुत सारे लाभ स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश की जनता को दिये हैं। झज्जर में हमारी सरकार के प्रयासों से एम्स बन रहा है, कल्पना चावला के नाम से मैडीकल कालेज करनाल में बन रहा है, एक मैडीकल कालेज फरीदाबाद में बन रहा है और इसके साथ-साथ हमारी सरकार द्वारा एक मैडीकल कालेज मेवात में भी बनाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से हम मैडीकल कालेजिज पूरे प्रदेश में बना रहे हैं ताकि सभी प्रदेशवासियों की सेहत अच्छी रहे। अध्यक्ष महोदय, सोशल सैक्टर में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों को हमारी सरकार ने जो-जो सुविधायें दी हैं वह आप सभी को मालूम हैं। पूरे हिन्दुस्तान में इस प्रकार की सुविधायें और किसी भी प्रदेश की सरकार द्वारा नहीं दी गई हैं। बच्चों की पढ़ाई से लेकर हम दूसरी सारी सुविधायें उनको देते हैं। इसके अलावा जहां तक बुढ़ापा पैंशन की बात कल विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा की जा रही थी। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथियों द्वारा प्रत्येक विषय पर सदन को गुमराह करने की कोशिश की जाती है । अध्यक्ष महोदय, यह बुढ़ापा पैंशन वर्ष 1964 से शुरू है और शुरू-शुरू में यह मात्र 15 रुपये थी। फिर यह समय के साथ-साथ बढ़ती रही। हमारी सरकार के आने से पहले जब विपक्ष के साथियों की सरकार थी तो इनकी सरकार ने चुनाव से एक-दो महीने पहले नवम्बर, 2004 में बुढ़ापा पैंशन को 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया लेकिन यह बढ़ी हुई पैंशन दी किसी को भी नहीं, सिर्फ बढ़ाकर चले गये । हमारी सरकार आने के बाद हमने सभी पैंशनर्ज़ को बकाया पैंशन 300 रुपये के हिसाब से वितरित की । इसके बाद उसको बढ़ाकर क्रमश: 500 रुपये और 700 रुपये किया । अध्यक्ष महोदय, जो यहां पर चर्चा हुई कि 500 रुपये और 700 रुपये का भेदभाव क्यों किया गया ? स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को इस बारे में बताना चाहूंगा कि इसका यह कारण रहा कि जितना आदमी वृद्ध होता जाता है उतनी ज्यादा उसकी ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं। इस प्रकार से 60 साल के बाद जब कोई व्यक्ति 10 साल तक लगातार पैंशन ले चुका है तो उसको हम बढ़ाकर 700 रुपये दे रहे हैं और बाकी को 500 रुपये दे रहे हैं। जिनको हम 500 रुपये दे रहे हैं उनके लिए भी हमने 50 रुपये के हिसाब से प्रति वर्ष की वृद्धि का प्रोविज़न किया है ताकि किसी प्रकार का कोई भेदभाव न रहे और सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना

का सभी पैंशनर्ज को लाभ प्राप्त हो सके। इसके अलावा हमारी सरकार ने विधवाओं को 750 रुपये प्रति मास के हिसाब से पैंशन देने का फैसला किया है। अध्यक्ष महोदय, यह नोट करने वाली बात है कि वर्ष 2004-05 में बुढ़ापा पैंशन का कुल बजट 260 करोड़ रुपये था जो कि आज वर्ष 2009-10 में बढ़कर 924 करोड़ रुपये हो गया है। अध्यक्ष महोदय, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रदेश के बुजुर्गों और विधवाओं के सम्मान के लिए हमारी सरकार कितनी सजग है। अध्यक्ष महोदय, पिछले पांच साल के दौरान हमारा हरियाणा प्रांत पूरे हिन्दुस्तान के नक्शे में एक प्रगतिशील प्रदेश के तौर पर उभर कर सामने आया है। इसका श्रेय मैं हरियाणा के कर्मठ किसानों, मेहनतकश लोगों और सरकार की प्रगतिशील नीतियों को देना चाहूंगा। मैं आज लोगों को फिर से यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि राज्य के विकास के लिए हम कोई भी कोर-कसर बाकी नहीं छोडेंगे। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश और प्रदेश के लोगों के हित से जुड़े कुछेक विशेष मुद्दे हैं जिनकी यहां चर्चा करना मैं जरूरी मानता हूं। अध्यक्ष महोदय, कई बार ऐसा होता है कि प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए हमारे पड़ौसी प्रदेशों के नेता और उनके मुख्यमंत्री अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए बात करते हैं। एक बात तो चण्डीगढ़ की है। अभी हाल ही में पंजाब विधान सभा के चालू सत्र में पंजाब ने चण्डीगढ़ पर अपने अधिकार की बात कही है। जहां तक चण्डीगढ़ का सवाल है, कुछ समय पहले दिल्ली में एक मीटिंग में यह मुद्दा उठाया गया तो भारत के प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह की मौजूदगी में पूरे देश के मुख्यमंत्रियों के सामने मैंने यह बात कही थी कि चण्डीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है और चण्डीगढ़ पर जितना अधिकार पंजाब का है उतना ही हरियाणा का भी है। जब पंजाब के मुख्यमंत्री ने यह बात कही कि चण्डीगढ़ हरियाणा की राजधानी नहीं है तब मैंने उनको भी यही कहा था कि चण्डीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों प्रदेशों की राजधानी है और अगर पंजाब अपनी अलग से राजधानी चाहता है तो वह चण्डीगढ़ को छोड़कर बाहर कहीं भी अपनी राजधानी बना ले हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। इसके अलावा मैंने उनको यह भी कहा था कि आप अपनी राजधानी खरड़ तहसील से बाहर बनायें क्योंकि खरड़ तहसील को भी शाह कमीशन द्वारा हरियाणा को दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहता हूं कि सिर्फ पंजाब का ही चण्डीगढ़ पर कोई हक नहीं है बल्कि हरियाणा का भी पूरा हक है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से चण्डीगढ़ एयरपोर्ट की बात है। इसमें भी पंजाब और हरियाणा बराबर के साझीदार हैं। इस बारे में मैं अखबारों में प्राय: देखता हूं कि पंजाब द्वारा मोहाली एयरपोर्ट के नाम से एडवरटाईज़मैंट दी जाती है। यहां पर मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि मोहाली नाम का कोई भी एयरपोर्ट पूरे हिन्दुस्तान में कहीं पर भी नहीं है अगर है तो वह चण्डीगढ़ एयरपोर्ट के नाम से है। ये लोग यह सब दूसरों को गुमराह करने के लिए करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मैं हाई कोर्ट के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा। इस बारे में अभी हमारे प्रैस के साथी भी पूछ रहे थे। हाई कोर्ट का हमने भी दावा किया है और आज के दिन चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया भी इन-प्रिंसीपल एग्री करते हैं। यह मेरा भी वायदा है कि हम इसके लिए कोशिश करते रहेंगे और चण्डीगढ़ में अपना अलग से हाई कोर्ट बनवाकर ही रहेंगे। एक वे लोग थे जो बहुत सालों तक पंजाबी भाषा की बात करके लोगों को गुमराह करते रहे। अध्यक्ष महोदय, इस बात की मुझे खुशी है कि हरियाणा ने पहली दफा पंजाबी भाषा को नोटिफाई किया है और हमने इस बात के भी आदेश दिये हैं कि यहाँ पर असैम्बली में भी पंजाबी भाषा की कार्यवाही कवर करने के लिए व्यवस्था की जाये ताकि उसको अपना उचित स्थान मिल सके। हमारे बहुत सारे लोग पंजाबी को चाहते हैं। वे चाहते हैं कि बच्चे पंजाबी

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

भी पढ़ सकें, हिन्दी भी पढ़ सकें, संस्कृत भी पढ़ सकें और अंग्रेजी भी पढ़ सकें। बच्चे ये भाषायें पढ़ेंगे तो बच्चों का सम्पूर्ण विकास हो सकेगा। इसी प्रकार से एक बात मैं विशेष तौर से कहना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश का विकास हमने लोकतांत्रिक परम्पराओं और संस्थाओं की मर्यादाओं को निभाकर किया है। उसको तोड़ कर या नष्ट करके नहीं किया जैसे कि उन्होंने विकास भी नहीं किया और मर्यादाएं भी तोड़ कर और नष्ट करके गये हैं। यह हमने नहीं किया, हमने मर्यादाओं के दायरे में रह कर विकास किया है। लेकिन आत्म संतुष्टि की अभी गुंजाइश नहीं है । अध्यक्ष महोदय, हमें निरन्तर आगे बढना है । हमने बहुत कुछ किया है लेकिन बहुत कुछ करना अभी बाकी है । हमारे हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है । पिछली बार भी मैंने कहा था, "अभी तो मापी है, हमने मुट्ठी भर जमीन आगे सारा आसमान बाकी है।" अध्यक्ष महोदय, एक और मुद्दा है और इसके बारे में बार-बार बात उठती है। इस बारे में मेरे प्रेस वाले साथी भी कहते हैं, वह एस.जी.पी.सी. का मुद्दा है। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक एस.जी.पी.एस. का सवाल है इस बारे में हरियाणा सरकार का और हमारा बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड है। आपकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी और उस बारे में आपने अपनी रिकमैंडेशन दे दी है। वह विचाराधीन है और उस बारे में लीगल ओपिनियन ली जा रही है। लीगल रिपोर्ट आने के बाद जो भी हमारे हरियाणा के सिखों की भावनाएं हैं हम उनके अनुरूप ही फैसला लेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमें अभी बहुत काम करने हैं। हर नई उपलब्धि हमारे सामने नये अवसर पैदा करती है। हम इन अवसरों का लाभ उठायेंगे और जो नई-नई चुनौतियाँ पैदा होंगी, हम इकट्ठे हो कर उनका मुकाबला करेंगे । हमारा यह संकल्प है कि हम हर नई चुनौती को विकास और एक नया अवसर मानेंगे और उसका भरपूर लाभ उठायेंगे ।

मुंह जो बात कहे वह है पत्थर की लकीर,
शाम-ओ-शहर के साथ नहीं बदलते हैं हम।

इन्हीं शब्दों के साथ राज्यपाल महोदय का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें संबोधित किया। धन्यवाद ।

Mr. Speaker: Question is—

That an address be presented to the Governor in the following terms:—

"That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 5th March, 2010 at 2.00 P.M."

(The motion was carried)

वर्ष 2009-2010 के लिए अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) प्रस्तुत करना

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will present the Supplementary Estimates for the year 2009-2010 (Second Instalment).

Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav): Sir, I beg to present the Supplementary Estimates for the year 2009-2010 (Second Instalment).

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Now, Rao Dharam Pal, Chairperson, Committee on Estimates, will present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (Second Instalment) for the year 2009-2010.

Rao Dharam Pal (Chairperson, Committee on Estimates): Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (Second Instalment) for the year 2009-2010.

वर्ष 2009-2010 के लिए अनुपूरक अनुमानों की मांगें (द्वितीय किस्त) पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, Now discussion and voting on Supplementary Estimates (Second Instalment) for the year 2009-2010, will take place.

As per the past practice and in order to save the time of the House, all the demands on order paper will be deemed to have been read and moved. The Hon'ble Members can discuss any demand but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise the discussion.

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 1,48,21,000/-**for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2010 in respect of **Demand No. 1-Vidhan Sabha.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 101,66,84,000/-**for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2010 in respect of **Demand No. 4-Revenue.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 3,000/-**for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2010 in respect of **Demand No. 6-Finance.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 1,000/-**for revenue expenditure and **Rs. 1,50,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2010 in respect of **Demand No. 7-Other Administrative Services.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 142,12,50,000/-**for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2010 in respect of **Demand No. 9-Education.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 17,82,88,000/-**for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2010 in respect of **Demand No. 10-Medical & Public Health.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 1,000/-**for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2010 in respect of **Demand No. 11-Urban Development.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 16,61,00,000/-**for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2010 in respect of **Demand No. 12-Labour & Employment.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 61,24,95,000/-**for revenue expenditure and **Rs. 41,60,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2010 in respect of **Demand No. 13-Social Welfare and Rehabilitation.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 766,23,14,000/-**for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2010 in respect of **Demand No. 14-Food & Supplies.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 114,58,10,000/-**for revenue expenditure and **Rs. 5,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2010 in respect of **Demand No. 15-Irrigation.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 19,53,86,000/-**for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2010 in respect of **Demand No. 17-Agriculture.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 22,27,25,10,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 85,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2010 in respect of **Demand No. 22-Co-operation.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 13,20,47,000/-**for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2010 in respect of **Demand No. 24-Tourism.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 1,000/-**for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2010 in respect of **Demand No. 25-Loans & Advances by the State Government.**

(No. Member rose to speak.)

Mr. Speaker : Now, the demands will be put to the vote of the House—

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 1,48,21,000/-**for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2010 in respect of **Demand No. 1-Vidhan Sabha.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 101,66,84,000/-**for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2010 in respect of **Demand No. 4-Revenue.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 3,000/-**for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2010 in respect of **Demand No. 6-Finance.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 1,000/-**for revenue expenditure and **Rs. 1,50,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2010 in respect of **Demand No. 7-Other Administrative Services.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 142,12,50,000/-**for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2010 in respect of **Demand No. 9-Education.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 17,82,88,000/-**for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2010 in respect of **Demand No. 10-Medical & Public Health.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 1,000/-**for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2010 in respect of **Demand No. 11-Urban Development.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 16,61,00,000/-**for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2010 in respect of **Demand No. 12-Labour & Employment.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 61,24,95,000/-**for revenue expenditure and **Rs. 41,60,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2010 in respect of **Demand No. 13-Social Welfare and Rehabilitation.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 766,23,14,000/-**for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2010 in respect of **Demand No. 14-Food & Supplies.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 114,58,10,000/-**for revenue expenditure and **Rs. 5,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2010 in respect of **Demand No. 15-Irrigation.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 19,53,86,000/-**for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2010 in respect of **Demand No. 17-Agriculture.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 22,27,25,10,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 85,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2010 in respect of **Demand No. 22-Co-operation.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 13,20,47,000/-**for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2010 in respect of **Demand No. 24-Tourism.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 1,000/-**for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2010 in respect of **Demand No. 25-Loans & Advances by the State Government.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned till 10.00 A.M. tomorrow, the 10th March, 2010.

*14.45 hrs. (The Sabha then *adjourned till 10.00 A.M. on Wednesday, the 10th March, 2010.)

47246—H.V.S.—H.G.P., Chd.

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh